राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक

गौरवशाली भारत

दिल्ली से प्रकाशित

R.N.I. NO. DELHIN/2011/38334 वर्ष- 10, अंक- 336, पृष्ठ - 08, नई दिल्ली, मंगलवार , 15 जून 2021 मूल्य रु. 1.50

एक नज़र...

पीएम आवास पर वरिष्ठ मंत्रियों की बैठक

नई दिल्ली, (एजेंसी)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास पर केंद्र सरकार के वरिष्ठ मंत्रियों की बैठक हुई। 7 लोक कल्याण मार्ग में हुई इस बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी और सदानंद गौड़ा के साथ ही कुछ अन्य वरिष्ठ मंत्री मौजूद हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी पीएम के आवास पर हुई बैठक में मौजूद रहे। पीएम आवास पर यह बैठक ऐसे समय में हुई जब केंद्रीय मंत्रिमंडल में फेरबदल की अटकलें लगाई जा रही हैं। पिछले दिनों पीएम मोदी ने मंत्रियों के कामकाज की समीक्षा की थी। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी पिछले दिनों सूबे में नेतृत्व परिवर्तन की अटकलों के बीच अचानक दिल्ली पहुंचकर पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की थी।

फ्रैंकलिन टेम्पलटन पर 15 करोड़ का जुर्माना

नई दिल्ली, (एजेंसी)। मार्केट रेगुलेटर सेबी ने सोमवार को फ्रैंकलिन टेम्पलटन एएमसी के वरिष्ठ अफसरों और उसके ट्रस्टियों पर 15 करोड़ का जुर्माना ठोका है। यह जुर्माना 2020 में छह डेट स्कीम को बंद करने में नियामकीय नियमों का उल्लंघन करने के मामले में लगाया गया है। सेबी के आदेश में कहा गया है कि फ्रैंकलिन टेम्पलटन ट्रस्टी सर्विसेज प्रा. लि. पर तीन करोड़ का जुर्माना ठोका है। इसके अलावा फ्रैंकलिन ऐसेट मैनेजमेंट (इं.) प्रा. लि. के अध्यक्ष संजय सापरे और उसके मुख्य निवेश अधिकारी संतोष कामत पर दो-दो करोड़ का जुर्माना ठोका है। सेबी ने इसके साथ ही नियमों के उल्लंघन के समय योजना के फंड मैनेजर रहे कुणाल अग्रवाल, सुमित गुप्ता, पल्लव रॉय, सचिन पडवाल देसाई और उमेश शर्मा प्रत्येक पर डेढ़ करोड़ का जुर्माना लगाया है।

ड्रग्स के साथ अभिनेत्री नेहल शाह गिरफ्तार

मुंबई, (एजेंसी)। मायानगरी मुंबई में एक बॉलीवुड अभिनेत्री को अपने जन्मदिन पर ड्रग्स के साथ पार्टी करना मंहगा पड़ गया। पार्टी जब अपने शबाब पर थी, तभी पुलिस को किसी ने खुफिया तौर पर खबर दे दी। जिसके आधार पर पुलिस की टीम ने देर रात होटल में छापा मारा और अभिनेत्री को उसके दोस्त के साथ गिरफ्तार कर लिया। अभिनेत्री की पहचान नाइरा नेहल शाह के रूप में हुई है। मामला मुंबई के सांताक्रुज पुलिस थाना इलाके का है। जहां एक फाइव स्टार होटल में बॉलीवुड अभिनेत्री नेहल शाह अपना जन्मदिन मना रही थी। वो ड्रग्स के साथ पार्टी कर रही थी। पुलिस ने रविवार-सोमवार की दरम्यानी रात होटल में छापा मारकर इस मामले का खुलासा किया। बीती रात करीब 3 बजे एक फाइव स्टार होटल में रेड की गई।

आयशा अग्रिम जमानत को लेकर अदालत में

कोच्चि, (एजेंसी)। लक्षद्वीप निवासी फिल्म निर्माता आयशा सुल्ताना, जिनपर पुलिस ने देशद्रोह का मामला दर्ज किया है, ने सोमवार को केरल हाईकोर्ट के शरण में गई और अग्रिम जमानत देने की गुहार लगाई। आयशा ने अपने आवेदन में कहा कि अगर वह 20 जून को कवरत्ती थाना पहुंचती हैं तो उसकी गिरफ्तारी की संभावना है। पुलिस ने उसे 20 जून को कवरत्ती थाने में पेश होने को कहा है। भाजपा के नेता की शिकायत के बाद 10 जून को देशद्रोह के आरोप में सुल्ताना के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। नेता ने कहा कि एक मलयालम टीवी चैनल में बहस के दौरान उसने (आयशा ने) केंद्र शासितप्रदेश में कोविड -19 के प्रसार के बारे में झूठी खबर फैलाई।

भू-क्षरण से दो तिहाई हिस्से प्रभावित अनियंत्रित होने पर होगी समस्या

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत सरकार वर्ष 2030 तक 2.6 करोड़ एकड़ बंजर जमीन का पुनरोद्धार करने की योजना पर काम कर रही है। इस काम से भारत पर्यावरण में तीन अरब टन कार्बन उत्सर्जन को रोकने में मदद करेगा। पीएम मोदी सोमवार को संयुक्त राष्ट्र में मरुस्थलीकरण, सूखा व भूमिक्षरण विषय पर आयोजित उच्च स्तरीय संवाद को संबोधित करते हुए यह जानकारी दी।

उन्होंने विश्व के सभी देशों से आग्रह किया कि भूमि व पर्यावरण को नुकसान से बचाने के लिए पूरी मानवता को सामूहिक तौर पर जिम्मेदारी उठानी होगी और भूमि पर बढ़ते दबाव को कम करना होगा। मोदी ने कहा, हमारे सामने बहुत सारा काम है लेकिन यह किया जा सकता है। साथ मिल कर यह काम हो सकता है। मोदी ने कहा कि भारत हमेशा से भूमि को अहमियत देता रहा है और भूमि को माता का दर्जा दिया जाता है। भारत ने हमेशा से इस मामले में अंतरराष्ट्रीय फोरम में अग्रणी भूमिका निभाई है।

स्थानीय तकनीक की मदद से भूमिक्षरण रोकने पर खास जोर

भारत ने पिछले दस वर्षों में 30 लाख हेक्टेयर अतिरिक्त जमीन पर वन क्षेत्र लगाया है। इससे देश के वन क्षेत्र में एक चौथाई फीसद की वृद्धि हुई है। इसके साथ ही भारत सरकार भूमिक्षरण को रोकने के लिए भी राष्ट्रीय प्रतिबद्धता से काम कर रहा है। उन्होंने गुजरात के कछ क्षेत्र में भूमिक्षरण रोकने और वन लगाने की योजना के सकारात्मक असर के बारे में भी बताया। इससे वहां के लोगों के जीवन पर भी सकारात्मक असर पड़ा है।

पीएम मोदी ने स्थानीय तकनीक की मदद से भूमिक्षरण रोकने पर खास जोर दिया। भूमिक्षरण को विकासशील देशों के लिए खास तौर पर चुनौतीपूर्ण बताते हुए पीएम मोदी ने कहा कि भारत दूसरे विकासशील देशों को इस काम में मदद कर रहा है। अपने भाषण के अंत में उन्होंने कहा कि अपने भावी पीढ़ी को एक स्वस्थ विश्व देना हम सभी का पावन कर्तव्य है।

नई दिल्ली में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद से मुलाकात की।

सेवा ही संगठन अभियान का दूसरा चरण शुरू करेगी बीजेपी

नई दिल्ली । भारतीय जनता पार्टी सेवा ही संगठन अभियान का दूसरा चरण शुरु करेगी. यह अभियान देशभर में शुरु किया जाएगा. बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने देशभर के कार्यकर्ताओं को इस बारे में निर्देश दिए हैं. इसमें टीकाकरण अभियान, राहत कार्यक्रम और पड़ोस-ग्राम स्वास्थ्य स्वयंसेवक का प्रशिक्षण शामिल है. टीकाकरण अभियान में मेरा बूथ टीकाकरण युक्त का आह्वान किया गया है. इसके तहत 45 वर्ष से ऊपर के सभी लोगों को टीके की दोनों डोज लगना सुनिश्चित करने को कहा गया है.

इस अभियान के तहत 18 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों में लक्ष्य समूह निर्धारित किए गए, जिन्हें टीके के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा. इनमें डिलीवरी बॉय, ऑटो रिक्शा चालक, घरेलू सहायक, समाचार पत्र वितरक, गैस सिलेंडर वितरक, 12 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के माता-पिता, 18 वर्ष से अधिक उम्र के सभी लोगों को टीकाकरण के लिए प्रेरित करने को कहा गया है.

राहत कार्यक्रम में लोगों को त्योहारों के समय कोविड के अनुरूप व्यवहार करने के लिए प्रेरित करना भी शामिल है. इसके तहत सैनिटाइजर, मास्क आदि का वितरण किया जाएगा. बीजेपी अध्यक्ष ने कार्यकर्ताओं से रक्तदान शिविर लगाने के लिए कहा है. अस्पतालों में राशन किट और भोजन वितरण की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश हैं. टेली मेडिसिन सेंटर और मेडिकल हेल्प सेंटर की स्थापना करने का निर्देश दिया गया है. बीजेपी अध्यक्ष ने अपील की है कि वृद्धों के सहायता के लिए स्वयंसेवक आगे आएं. प्रभावित लोगों को बीमा सुविधा जल्द से जल्द मिले, इसका प्रयास किया जाएगा. हेल्थ वॉरियर्स का उचित सम्मान किया जाएगा. स्वास्थ्य स्वयंसेवक के लिए दो लाख शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में एक महिला तथा एक पुरूष कार्यकर्ता को तैयार करने का लक्ष्य रखा गया है.

बीजेपी के विधायक ने राज्यपाल को सौंपा ज्ञापन

कोलकाता। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने फिर ममता सरकार पर हिंसा को लेकर हमला बोलते हुए कहा कि हिंसा का तांडव चल रहा है, लेकिन सरकार के कानों में जूं नहीं रेंग रही है. उन्होंने कहा कि सरकार को आए हुए एक माह से अधिक हो गई है, लेकिन किसी भी कैबिनेट की बैठक में हिंसा पर चर्चा नहीं हुई है. मंगलवार को बीजेपी के विधायक दल के नेता शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने रायपाल को ज्ञापन सौंपा.

बता दें कि विधानसभा चुनाव के बाद बीजेपी लगातार हिंसा का आरोप लगा रही है. चुनाव के बाद बीजेपी लगातार सत्तारूढ़ पार्टी पर बीजेपी कार्यकर्ताओं पर हमला करने, उन्हें डराने और धमकाने का आरोप लगाते रही है. बीजेपी का आरोप है कि चुनाव के बाद बीजेपी के 40 से अधिक कार्यकर्ताओं की हत्या हो चुकी है. राज्यपाल ने कहा कि हिंसा का तांडव चल रहा है, लेकिन मुख्यमंत्री या मंत्री ने किसी भी पीड़ित के आंसू पोंछा है.

सीबीएसई 12 वीं मूल्यांकन तय आधारों पर देंगे मार्क्स!

नई दिल्ली, (एजेंसी)। क्लास 12 बोर्ड एग्जाम रद्द होने के बाद देश के लाखों स्टूडेंट्स को यह जानने का इंतजार है कि उनका रिजल्ट कैसे बनेगा? सीबीएसई 12वीं बोर्ड स्टूडेंट्स की मार्किंग कैसे करेगा? केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) की 12 सदस्यों की एक्सपर्ट कमेटी इस मामले में एक नतीजे पर पहुंची है।

12वीं के रिजल्ट के लिए 10वीं तक के रिजल्ट को इवैल्युएशन का हिस्सा बनाने पर विचार किया जा रहा है। शिक्षा मंत्रालय के सूत्र के अनुसार, सीबीएसई रिजल्ट एक्सपर्ट कमेटी 10वीं, 11वीं और 12वीं तीनों कक्षाओं की परफॉर्मेंस को क्लास 12 बोर्ड 2021 मूल्यांकन का आधार बनाने पर विचार कर रही है। इसके अनुसार, स्टूडेंट्स को 10वीं बोर्ड में उनकी परफॉर्मेंस, 11वीं के फाइनल एग्जाम और 12वीं के प्री बोर्ड एग्जाम की परफॉर्मेंस के आधार पर मार्क्स दिये जाएंगे। अगर यह प्रस्ताव लागू होता है, तो इस साल सीबीएसई 12वीं बोर्ड स्टूडेंट्स का मूल्यांकन तीन कंपोनेंट्स के आधार पर किया जाएगा - क्लास 10 बोर्ड एग्जाम, क्लास 11 फाइनल एग्जाम और क्लास 12 प्री-बोर्ड एग्जाम। लेकिन किस कंपोनेंट को कितना वेटेज (कितने अंक) दिया जाएगा, इसपर अंतिम फैसला होना बाकी है। थ्योरी के लिए कुल अंक 70 होने हैं। केंद्र सरकार द्वारा 01 जून को सीबीएसई 12वीं बोर्ड परीक्षा रद्द करने का फैसला किया गया था।

शिविंदर की बेल दिल्ली हाईकोर्ट से खारिज

नयी दिल्ली, एजेंसी। दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को रेलीगेयर फिनवेस्ट लिमिटेड के धन के गबन के मामले में रेलीगेयर प्रोमोटर शिविंदर मोहन सिंह को जमानत दिए जाने संबंधी आदेश को खारिज कर दिया। न्यायमूर्ति सुरेश कुमार कैत की पीठ ने कहा कि शिविंदर की नजरबंदी उसके द्वारा रची गई साजिश का पता लगाने के लिए जरूरी थी और धन गबन मामले में पैसे की हेराफेरी का पता लगाने के लिए उसके खिलाफ गंभीर आरोप लगे हैं। पीठ ने अपने आदेश में कहा कि एक एजेंट ने इतनी बड़ी मात्रा में धन गबन और धोखाधड़ी, आपराधिक हितों के उल्लंघन, बहुत बड़ी संख्या में लोगों को प्रभावित किया है।

चीन से लंबी जंग की तैयारी कर रही सेना

नई दिल्ली, (एजेंसी)। पूर्वी लद्दाख में गलवान घाटी की झड़प के एक साल बाद भी चीनी सैनिक वास्तविक नियंत्रण रेखा के पास डेरा डाले हुए हैं। इस बीच भारत ने भी लंबी अवधि की सोच के साथ उसका मुकाबला करने के लिए खास तैयारी की है।

गलवान झड़प के एक साल

सीमा विवाद को सुलझाने के लिए भारतीय और चीनी सैन्य प्रतिनिधियों के बीच 11 दौर की बातचीत हुई है। बातचीत में दोनों देश इस विवाद को शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाने पर सहमत हो गए हैं। भारतीय सेना ने पिछले एक साल में लद्दाख में चीन के साथ किसी भी संभावित लड़ाई का सामना करने के लिए बेहतर तरीके से तैयार होने पर ध्यान केंद्रित किया है।

अडाणी ग्रुप के 43,500 करोड़ के शेयर फ्रीज

सेबी की जांच शुरू, एक घंटे में करीब 50 हजार करोड़ का नुकसान

मुंबई ■ एजेंसी

अडाणी ग्रुप की छह लिस्टेड कंपनियों के शेयरों में 5 फीसदी से लेकर 22 फीसदी तक की गिरावट आई है। इसमें सबसे ज्यादा अडाणी इंटरप्राइजेज के शेयर टूटे हैं।

यह 22 फीसदी टूट कर 1,200 रुपए पर आ गया। शुक्रवार को यह 1,600 रुपए पर बंद हुआ था। इसके बाद बाकी कंपनियों के भी शेयर इसी तरह टूटे। इससे निवेशकों को शुरुआती घंटे में करीब 50,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। **तीन विदेशी निवेशकों के निवेश पर शक:** शेयरों में गिरावट का कारण यह था कि सेबी ने इस ग्रुप की कंपनियों में तीन ऐसे विदेशी निवेशकों को पकड़ा, जिन्हें फर्जी माना जा रहा है। ये तीन निवेशक हैं- अलबुला इन्वेस्टमेंट फंड, क्रेस्टा फंड और एपीएमएस इन्वेस्टमेंट फंड। ये मॉरीशस की राजधानी पोर्ट लुइस के एक ही पते पर रजिस्टर्ड हैं। इनके पास वेबसाइट नहीं है। सेबी ने इन तीनों के निवेश को फ्रीज कर दिया है और जांच शुरू हो गई है।

अडाणी समूह ने खबर को गलत बताया

अडाणी समूह ने सोमवार को कहा कि उसके पास इस बात की लिखित जानकारी है कि उसके शीर्ष शेयरधारकों में शामिल तीन विदेशी फंडों के खाते जब्त नहीं किए हैं और इस तरह की खबर स्पष्ट रूप से गलत और भ्रामक हैं। अडाणी ग्रुप की कंपनियों में हिस्सेदारी रखने वाले कुछ एफपीआई खातों को राष्ट्रीय प्रतिभूति डिपॉजिटरी लि. (एनएसडीएल) द्वारा कथित रूप से जब्त करने की खबर के बाद इन कंपनियों के शेयरों में सोमवार को गिरावट देखी गई।

पीएम मोदी के गृह जनपद में फोकस बढ़ा रहे अरविंद केजरीवाल, बोले अब गुजरात बदलेगा

नई दिल्ली । गुजरात विधानसभा चुनाव का समय ज्यों-ज्यों नजदीक आ रहा है, आप गुजरात पर अपना फोकस बढ़ा रही है। पाटी को दिल्ली में तीसरी बार जीत दिला चुके आप के तमाम नेता गुजरात के लिए रणनीति तय कर रहे हैं। वहीं आप के मुखिया ने भी गुजरात की ओर रुख कर लिया है। आप के राष्ट्रीय संयोजक और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियों का जायजा लेने के लिए अहमदाबाद पहुंचे हैं। वह वहां बनने वाले पार्टी प्रदेश कार्यालय के उद्घाटन करेंगे। स्वयं सीएम ने रविवार को ट्वीट करके इसकी जानकारी दी।

केजरीवाल ने कहा, अब गुजरात बदलेगा, मैं गुजरात आ रहा हूं। वहां गुजरात के सभी भाई-बहनों से मिलूंगा। केजरीवाल का ये दौरा इसलिए भी खास माना जा रहा है क्योंकि इस दिन कुछ बड़े चेहरे आम आदमी पार्टी के साथ जुड़ सकते हैं।

यहां बता दें कि गुजरात में हाल ही में हुए नगर निगम चुनाव में आप ने अच्छा प्रदर्शन किया था। पहली बार सूरत नगर निगम में कांग्रेस को एक भी सीट नहीं मिली, जबकि पहली बार चुनाव लड़ने वाली आप ने यहां 27 सीटों पर जीत हासिल की है।

मालूम हो कि दिल्ली की सत्ता पर आम आदमी पार्टी राज कर रही है। अब वो अन्य राज्यों में अपने पैर पसारने की सोच रही है। दरअसल बीते दिनों गुजरात के सूरत में हुए निकाय चुनाव में पार्टी को जो सीटें मिली है जिससे उसका उत्साह बढ़ा हुआ है। इसी वजह से अब पार्टी की नजर अगले साल 2022 में होने वाले के विधानसभा चुनावों पर है।

पार्टी की ओर से इन दिनों गुजरात में सदस्यता अभियान चलाया जा रहा है जिससे सदस्यों की संख्या बढ़ाई जा सके। सदस्यता अभियान के अलावा पार्टी की ओर से मिस्ड कॉल देकर भी सदस्य बनाए जा रहे हैं, इससे भी लोगों को जोड़ा जा रहा है।

पार्टी के पास पहले से मजबूत दिल्ली मॉडल है वो इसी मॉडल को गुजरात में लागू करना चाह रही है। दिल्ली में पार्टी को अपने इस मॉडल का काफी लाभ मिला है अब वो इसे अन्य राज्यों में ले जाकर वहां भी अपनी जड़ें मजबूत करना चाह रही है। वैसे आम आदमी पार्टी दिल्ली से बाहर पंजाब, यूपी और कुछ अन्य राज्यों में लगातार चुनाव लड़ती आ रही है। पंजाब-गोवा जैसे राज्यों में पार्टी को बड़ी सफलता भी हाथ लगी है।

धारा 370 को लेकर बीजेपी पर साधा निशाना

कोलकाता ■ एजेंसी

इसे हटाने से कश्मीरियों की स्वतंत्रता समाप्त हुई

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अनुच्छेद 370 को खत्म करने को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा। सीएम ममता ने कहा कि 370 हटने के बाद कश्मीर के लोगों की स्वतंत्रता, उनकी मांग और हित कमजोर हो रहे हैं।

किसी को भी बंगाल को बांटने नहीं देंगे: मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सोमवार को मीडिया से बात करते हुए कहा कि हम किसी को भी पश्चिम बंगाल को बांटने नहीं देंगे। अगर बीजेपी को लगता है कि वो कोई भी हिस्सा बेच सकती है तो यह इतना आसान नहीं है। वे दिल्ली को संभाल नहीं सकते। जो लोग बंगाल को बांटना चाहते हैं उन्हें बंगाल के नागरिकों से उचित जवाब मिलेगा।

एक राष्ट्र-एक राशन कार्ड प्रणाली से कोई दिक्कत नहीं- सुप्रीम कोर्ट के एक राष्ट्र एक राशन कार्ड की नीति को अपनाने के बारे में बंगाल की मुख्यमंत्री ने कहा कि हमें एक राष्ट्र-एक राशन कार्ड प्रणाली से कोई समस्या नहीं है। हम तीन महीने में लागू करेंगे, कुछ लोगों के पास आधार कार्ड नहीं हैं, हम तैयार कर रहे हैं।

अब राज्यपाल से मिले शुभेंदु

कोलकाता, (एजेंसी)। पश्चिम बंगाल विधानसभा में नेता विपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने बीजेपी विधायकों की अगुवाई में सोमवार को राज्यपाल जगदीप धनखड़ से मुलाकात की। इस दौरान बीजेपी के करीब 74 विधायकों में से 50 विधायक ही मौजूद रहे। 20 भाजपा विधायकों की गैरमौजूदगी रहीं। जिन विधायकों ने हिस्सा नहीं लिया वो अब भाजपा के लिए चिंता का सबब बने हुए हैं। पश्चिम बंगाल में भाजपा ने 77 सीटें जीती थी। इनमें से मुकुल रॉय के टीएमसी में शामिल होने के बाद अटकलें लगाई जा रही है कि कई और विधायक टीएमसी में शामिल हो सकते हैं। दो विधायक पहले ही विधायक पद से इस्तीफा दे चुके हैं। दोनों सांसद हैं। यह पहला मौक़ा था जब शुभेंदु अधिकारी की अगुवाई में भाजपा के विधायक राज्यपाल से मिले।

राम मंदिर ट्रस्ट के घोटाले पर जवाब दें पीएम मोदी, कोर्ट की निगरानी में हो जांच: कांग्रेस

नई दिल्ली । कांग्रेस ने श्री राम जन्म भूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट से संबंधित एक जमीन सौदे में लगे भ्रष्टाचार के आरोप को लेकर जवाब मांगा है. कांग्रेस ने सोमवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस 'घोटाले' पर जवाब देना चाहिए. इस मामले की जांच सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में होनी चाहिए.

पार्टी के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने सुप्रीम कोर्ट से यह से आग्रह किया कि वह मंदिर निर्माण के चंदे के रूप में प्राप्त राशि और खर्च का ऑडिट करवाए. साथ ही चंदे से खरीदी गई सारी जमीन की कीमत को लेकर भी जांच की जाए.

सुरजेवाला ने संवाददाताओं से कहा, 'भगवान श्री राम आस्था के प्रतीक हैं. पर भगवान राम की अलौकिक अयोध्या नगरी में श्री राम मंदिर निर्माण के लिए करोड़ों लोगों से एकत्रित चंदे का दुरुपयोग और धोखाधड़ी महापाप और घोर अधर्म है, जिसमें भाजपाई नेता शामिल हैं.'

सुरजेवाला ने दावा किया, 'जमीन की रजिस्ट्री के दोनों कागजों पर श्री राम जन्म भूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के ट्रस्टी अनिल मिश्रा गवाह के तौर पर मौजूद हैं. दोनों कागजों पर दूसरे गवाह भाजपा के प्रमुख नेता और अयोध्या के मेयर ऋषिकेश उपाध्याय हैं. इसका मतलब साफ है कि 2 करोड़ रुपये मूल्य की जमीन पांच मिनट में 18.5 करोड़ रुपये में खरीदने के निर्णय की राममंदिर निर्माण ट्रस्ट के न्यासियों को पूरी जानकारी थी.'

उन्होंने कहा, 'श्री राम मंदिर निर्माण के लिए ट्रस्ट का गठन सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के अनुसार 5 फरवरी, 2020 को हुआ. उपरोक्त तथ्यों से साफ है कि करोड़ों लोगों द्वारा राम मंदिर निर्माण के लिए दी गई दान राशि में घोर महापाप, अधर्म व घोटाला हुआ है. लेकिन प्रधानमंत्री पूरी तरह से चुप हैं.'

सुरजेवाला ने सवाल किया, 'प्रधानमंत्री को इसका जवाब देना चाहिए कि क्या भगवान राम की आस्था का सौदा करने वाले पापियों को मोदी जी का संरक्षण प्राप्त है? मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के नाम पर इतना बड़ा कदाचार भाजपा नेताओं ने कैसे किया?' उन्होंने यह भी पूछा, 'इस प्रकार और कितनी जमीन मंदिर निर्माण के चंदे से औने-पौने दामों पर खरीदी गई है?

कांग्रेस नेता ने कहा, 'राम मंदिर निर्माण के लिए इस ट्रस्ट का गठन देश के उच्चतम न्यायालय के निर्देश पर किया गया है. जब यह घोटाला और इसके तथ्य सामने हैं, तो देशवासियों की ओर से हमारी मांग है कि प्रधानमंत्री उपरोक्त सवालों का देश को जवाब दें. देश के प्रधान न्यायाधीश व उच्चतम न्यायालय पूरे मामले का संज्ञान लेकर न्यायालय की निगरानी में जांच करवाएं' उन्होंने यह मांग भी की, 'उच्चतम न्यायालय मंदिर निर्माण के चंदे के रूप में प्राप्त राशि व खर्च का न्यायालय के तत्वाधान में ऑडिट करवाए, मंदिर निर्माण के लिए मिले चंदे से खरीदी गई सारी जमीन की कीमत के आकलन बारे भी जांच करे तथा न्यायालय देशवासियों व भक्तजनों के समक्ष वह ऑडिट रिपोर्ट सार्वजनिक करे.

गौरतलब है कि आम आदमी पार्टी (आप) के राज्यसभा सदस्य संजय सिंह ने रविवार को श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाते हुए उसकी जांच सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) से कराने की मांग की थी. सिंह ने लखनऊ में दावा किया था कि ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने संस्था के सदस्य अनिल मिश्रा की मदद से दो करोड़ रुपये कीमत की जमीन 18 करोड़ रुपये में खरीदी. उन्होंने कहा था कि यह सीधे-सीधे धन शोधन का मामला है और सरकार इसकी सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय से जांच कराए.

वहीं, समाजवादी पार्टी की पूर्ववर्ती सरकार में मंत्री रहे एवं अयोध्या के पूर्व विधायक पवन पांडे ने भी अयोध्या में राय पर भ्रष्टाचार के ऐसे ही आरोप लगाए और मामले की जांच सीबीआई से कराने की मांग की. चंपत राय ने इस पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि वह इस तरह के आरोपों से नहीं डरते और इन आरोपों का अध्ययन करेंगे.

मामले का विचाराधीन होना सूचना देने से मना करने का आधार नहीं

नई दिल्ली ■ एजेंसी

आरटीई पर सीआईसी ने दिए निर्देश

सूचना के अधिकार (आरटीआई) अधिनियम के तहत राजनीतिक दलों को लाने से संबंधित एक मामले में केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) ने हाल ही में आरटीआई मामलों के लिए केंद्र सरकार के नोडल विभाग कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) को याद दिलाया कि न्यायालय के विचाराधीन मामलों को आरटीआई अधिनियम की धारा 8 (1) (बी) के तहत इनकार नहीं किया जा सकता है।

मामले में आरटीआई आवेदन यश पॉल मानवी द्वारा 17 जुलाई, 2019 को दायर किया गया था। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में रिट (सिविल) संख्या 333/2015 के संबंध में डीओपीटी द्वारा दायर जवाब की एक प्रति मांगी थी। उसी वर्ष मार्च में सुप्रीम कोर्ट ने एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (एडीआर) और आरटीआई कार्यकर्ता सुभाष चंद्र अग्रवाल द्वारा संयुक्त रूप से दायर एक याचिका को आरटीआई अधिनियम के तहत राष्ट्रीय राजनीतिक दलों को जवाबदेह ठहराने के लिए संज्ञान में लिया था।

केंद्रीय सूचना आयोग ने पहले जून 2013 में फैसला सुनाया था कि राजनीतिक दल पारदर्शिता कानून के दायरे में आते हैं, लेकिन दलों ने जोर देकर कहा कि उन्हें अधिनियम के तहत सार्वजनिक प्राधिकरण नहीं माना जा सकता है। केंद्र ने जनवरी 2018 में शीर्ष अदालत कहा था कि राजनीतिक दलों को 'सार्वजनिक प्राधिकरण' कहकर उन्हें आरटीआई अधिनियम के दायरे में नहीं लाया जाना चाहिए, क्योंकि इससे न केवल उनके सुचारू कामकाज में बाधा आएगी। राजनीतिक प्रतिद्वंद्वियों को भी सूचना मांगने की आड़ में दुर्भावनापूर्ण मंशा के तहत याचिका दायर करने में मदद मिलेगी।

मनीला में एक तेल टैंकर में लगी आग के बाद उसमें लदा हुआ ट्रक भी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हुआ।

भारत को स्थाई शत्रु न बनाएं जिनपिंग : जिआंगताओ

बीजिंग, (एजेंसी)। पूर्वी लद्दाख के गलवान घाटी में खूनी हिंसा के एक साल पूरे होने से ठीक पहले चीन के एक विशेषज्ञ ने राष्ट्रपति शी जिनपिंग को भारत के साथ स्थाई शत्रुता को लेकर आगाह किया है। हांगकांग के वरिष्ठ पत्रकार शी जिआंगताओ ने अपने एक आलेख में कहा है कि अगर चीन सचमुच में भारत को स्थाई शत्रु नहीं बनाने के लिए गंभीर है, तो उसे सीमा से जुड़ी शिकायतों को एक तरफ रखकर और लद्दाख में गतिरोध को खत्म करके इसकी शुरूआत करनी चाहिए।

शी जिआंगताओ ने कहा कि एक साल पहले किसी ने यह अपेक्षा नहीं की थी कि वर्ष 2017 के बाद सुधर रहे चीन-भारत संबंध अचानक इतने निचले स्तर पर पहुंच जाएंगे। करीब 13 महीने बीत जाने के बाद भी पूर्वी लद्दाख में जारी गतिरोध खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है।

चीन के न्यूक्लियर प्लांट से लीकेज की आशंका, अध्ययन में जुटा अमेरिका

वॉशिंगटन, (एजेंसी)। दुनिया में कोरोना महामारी फैलाने और उसकी जांच पर पर्दा डालने में जुटे चीन की एक और बड़ी लापरवाही सामने आई है। चीन के एक न्यूक्लियर पावर प्लांट में लीकेज की जानकारी सामने आई है। अमेरिकी सरकार बीते एक हफ्ते से इस रिपोर्ट के अध्ययन में जुटी है।

दरअसल, चीनी न्यूक्लियर पावर प्लांट में फ्रांस की एक कंपनी भी हिस्सेदार थी। इसी कंपनी ने लीकेज के कारण संभावित रेडियोलॉजिकल खतरे को लेकर चेतावनी दी थी। अमेरिकी अधिकारियों से मिली जानकारी और मामले से संबंधित दस्तावेजों को देखने के बाद पूरे मामले का खुलासा किया गया है। फ्रेंच कंपनी ने यह भी बताया कि चीन के गुआंगदोंग प्रांत में मौजूद यह न्यूक्लियर पावर प्लांट कहीं बंद न हो जाए, इससे पहले ही चीनी सुरक्षा अधिकारियों ने इसके बाहर विकिरण की स्वीकार्य सीमा को बढ़ा दिया है। दरअसल, फ्रेंच कंपनी ने इस संबंध में यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी को चिट्ठी लिखी है।

फ्रांस की कंपनी फ्रैमाटोम की ओर से मिली इस चिट्ठी के बावजूद बाइडेन प्रशासन को फिलहाल यह लग रहा है कि न्यूक्लियर प्लांट में स्थिति अभी नियंत्रित है। अमेरिकी अधिकारियों का कहना है कि मौजूदा स्थिति प्लांट में काम करने वालों और चीनी नागरिकों के लिए खतरा नहीं पैदा कर रही है। हालांकि, यह अपने आप में अजीब है कि एक विदेशी कंपनी अमेरिकी सरकार से मदद मांग रही है, जबकि उसके चीनी पार्टनर को इस समस्या के बारे में अब तक कोई जानकारी नहीं है। फ्रांस की कंपनी के साथ चीन ने सन 2009 में ताइशन प्लांट का निर्माण शुरू किया था, जिसके बाद साल 2018 और 2019 में यहां बिजली उत्पादन शुरू हुआ था।

अमेरिका की नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने बीते हफ्ते इस मसले पर लगातार बैठकें कीं। इसके अलावा बाइडेन प्रशासन ने स्थिति को लेकर फ्रांस की सरकार और ऊर्जा विभाग में उनके अपने एक्सपर्ट्स से चर्चा की। चीन ने अपने परमाणु ऊर्जा के इस्तेमाल को हाल के सालों में बढ़ाया है। देश में पैदा हो रही बिजली में 5 फीसदी हिस्सेदारी परमाणु ऊर्जा की है। चीन के न्यूक्लियर एनर्जी एसोसिएशन के मुताबिक, मौजूदा समय में देश में 16 न्यूक्लियर प्लांट काम कर रहे हैं, जिनसे 51 हजार मेगावॉट बिजली का उत्पादन हो रहा है।

चीन के गुआंगदोंग प्रांत के ताइशन में कुल 9 लाख 50 हजार की आबादी है। अमेरिका इस मुद्दे को लेकर चीन की सरकार के भी संपर्क में है, हालांकि अभी तक दोनों देशों के बीच कितनी बात हुई है, यह स्पष्ट नहीं है। बता दें कि फ्रेंच कंपनी ने यह चिट्ठी ऐसे वक्त लिखी है जब अमेरिका और चीन के बीच टकराव चरम पर है। रविवार को ही संपन्न हुए जी-7 देशों की बैठक में भी चीन को लेकर अहम चर्चा हुई।

अल्जीरिया के चुनाव में इस्लामी पार्टी ने किया जीत का दावा

अल्जीयर्स। अल्जीरिया के संसदीय चुनाव में एक उदारवादी इस्लामी पार्टी ने जीत हासिल करने का दावा किया है, हालांकि नतीजे अगले कुछ दिन तक आने की उम्मीद नहीं है। उत्तर अफ्रीकी देश में चुनाव खत्म होने के 24 घंटे से भी कम समय में मूवमेंट फॉर ए पीसफुल सोसाइटी के प्रमुख अब्देरजाक मकरी ने कहा कि पार्टी कई क्षेत्रों और उससे बाहर भी बहुमत की ओर बढ़ रही है। पार्टी प्रमुख मकरी ने नतीजों को बदलने के लिए फजीर्वाड़ा के प्रयास के आरोपों की निंदा की। हालांकि पार्टी ने यह नहीं बताया कि वह किस आधार पर जीत का दावा कर रही है। अल्जीरिया के चुनाव प्राधिकार के प्रमुख ने कहा संसदीय चुनाव के लिए मतदान निराशाजनक रहा, जिसमें 2.4 लाख योग्य मतदाताओं में से एक तिहाई से भी कम मतदाताओं ने भाग लिया।

आयुधों को ज्यादा मारक बनाने में जुटे परमाणु शक्ति संपन्न देश, संख्या में भी कर रहे वृद्धि

स्टॉकहोम, (एजेंसी)। परमाणु हथियारों पर नजर रखने वाली अंतरराष्ट्रीय संस्था सिप्री की वार्षिक रिपोर्ट के मुताबिक 1990 के दशक के बाद पहली बार दुनिया में परमाणु हथियारों संख्या में कमी का क्रम ठहर गया है। सिप्री की रिपोर्ट में बताया गया है कि परमाणु हथियार संपन्न देश अब न केवल अपने परमाणु हथियारों को ज्यादा मारक बनाने का प्रयास कर रहे हैं, बल्कि उनकी संख्या में भी बेहिसाब बढ़ोतरी करने में जुट गए हैं। पिछले एक साल में भारत के धुर विरोधी देशों चीन ने 30 और पाकिस्तान ने 5 नए परमाणु बम बनाए हैं। सिप्री की रिपोर्ट में बताया गया है कि सन 2020 की तुलना में वर्ष 2021 में दुनिया के कुल परमाणु बमों की संख्या में कमी आई है, लेकिन तुरंत इस्तेमाल किए जाने वाले परमाणु बमों की संख्या में काफी बढ़ोतरी हो गई है।

सन 2021 में परमाणु हथियार संपन्न राष्ट्रों अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस, चीन, भारत, पाकिस्तान, इजरायल और नॉर्थ कोरिया के पास कुल 13,080 परमाणु बम हैं। जबकि सन 2020 में यह संख्या 13,400 थी। रिपोर्ट में कहा गया है कि परमाणु बमों की कुल संख्या में भले ही कमी आई हो, लेकिन तुरंत इस्तेमाल के लिए सेना के पास तैनात परमाणु हथियारों की संख्या में वृद्धि हो गई है। सन 2020 में 3720 परमाणु बम तैनात थे, वहीं सन 2021 में 3825 परमाणु हथियार कभी भी हमला करने के लिए बिल्कुल तैयार हालत में रखे गए हैं। बिल्कुल अलर्ट पर रखे गए महाविनाशक हथियारों में 2000 परमाणु बम केवल रूस और अमेरिका के हैं। सिप्री ने कहा सन 1990 के दशक से शुरू हुआ परमाणु बमों को कम करने का सिलसिला अब थम गया है।

अमेरिका और रूस लगातार अपने परमाणु हथियारों के जखीरे को अत्याधुनिक बनाने में जुटे हुए हैं। दोनों ही देशों ने पिछले साल की तुलना में 50 और परमाणु बमों को बिल्कुल हमला करने की स्थिति में तैनात कर दिया है। रूस ने अपने जखीरे में 180 परमाणु बम और बढ़ाए हैं, ताकि उन्हें अमेरिका तक मार करने में सक्षम मिसाइलों में तैनात किया जा सके। दुनिया पर राज करने का सपना देख रहे चीन ने परमाणु हथियारों का निर्माण तेज कर दिया है। चीन ने पिछले साल की तुलना में 30 नए परमाणु बम बनाए हैं। चीन के कुल परमाणु बमों की संख्या अब बढ़कर 350 हो गई है। वहीं कंगाली की हालत से गुजर रहा पाकिस्तान परमाणु हथियारों पर पानी की तरह से पैसा बहा रहा है। पाकिस्तान ने पिछले साल 5 नए परमाणु बम बनाए हैं। इसके साथ ही उसके पास अब कुल 165 परमाणु हथियार हो गए हैं।

इसे देखते हुए भारत ने भी अपने हथियारों के जखीरे को बढ़ाना शुरू कर दयिा है। पिछले साल भारत ने 6 नए परमाणु बम बनाए हैं। भारत के पास कुल परमाणु हथियारों की संख्या बढ़कर 156 हो गई है। उधर, एक अन्य एशियाई देश उत्तर कोरिया ने पिछले साल की तुलना में 10 नए परमाणु बम बनाए हैं। तानाशाह किम जोंग उन के पास अब 40 से 50 परमाणु बम हैं।

सेंट इव्स में जी सात देशों के बैठक स्थल के बाहर समुद्र तट पर विरोध प्रदर्शन के दौरान मौत का स्वांग रचते हुए लोग।

चीन में फैला डेल्टा वैरिएंट, लोगों की निगरानी और मास्क की याद दिलाने को तैनात किए 60 ड्रोन

बीजिंग, (एजेंसी)। चीन के दक्षिण शहर ग्वांग्झू में लोगों को घरों के भीतर रहने और बाहर जाते समय मास्क पहनने की याद दिलाने के लिए 60 ड्रोन तैनात किए गए हैं। चीन ने कोरोना वायरस के स्थानीय संक्रमण पर काफी हद तक काबू पा लिया है, लेकिन ग्वांग्झू में कोरोना पीड़ित कई मरीजों में कोरोना के डेल्टा वैरिएंट की मौजूदगी ने चीन की चिंताएं बढ़ा दी हैं।

ग्वांग्झू में पिछले 24 घंटों में छह नए मामले आए हैं जिससे संक्रमण के नए स्वरूप के मामले बढ़कर 100 हो गए हैं। पुलिस ने कैमरों से लैस ड्रोन उड़ाए और उन लोगों को संदेश दिए जो बाहर जा रहे थे।

शहर में ड्रोन के अलावा फोन पर स्वास्थ्य की जानकारी लेने, तापमान मापने और संक्रमण की अधिक आशंका वाले इलाकों की यात्रा करने वाले लोगों को पृथक करने जैसे कदमों से भी निगरानी की जा रही है।

ग्वांग्झू ने कई शहरों से अपने आप को अलग कर लिया है, शहर और आसपास के लोगों के प्रांत के बाहर जाने पर पाबंदी है तथा वहां सिनेमा और अन्य मनोरंजन स्थलों को भी बंद कर दिया गया है।

गौरतलब है कि अमेरिका और यूरोप में कोरोना वायरस की उत्पत्ति का सच जानने के लिए इसके वुहान की वायरॉलजी लैब से फैलने की थिअरी की जांच की मांग की जा रही है। अमेरिकी खुफिया एजेंसियों ने दावा किया है कि एक बंद पड़ी खदान की सफाई के दौरान बीमार हुए मजदूरों के सैंपल वुहान लैब भेजे गए थे। चीन पर आरोप है कि उसने अपने यहां वायरस फैलने और इसके घातक होने की जानकारी दुनिया को देर से दी।

कोरिया की रणनीतिक स्थिति पर चर्चा के बाद किम ने दिया सेना की युद्ध क्षमता बढ़ाने का निर्देश

प्योंगयांग, (एजेंसी)। उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन ने उत्तर कोरियाई सेना की युद्धक क्षमता बढ़ाने का ऐलान किया है। वर्कर्स पार्टी ऑफ कोरिया (डब्ल्यूपीके) के अंतर्गत काम करने वाले सेंट्रल मिलिट्री कमीशन की दूसरी बैठक में शामिल हुए किम जोंग उन ने कोरियाई प्रायद्वीप के रणनीतिक हालात की जानकारी लेने के बाद यह आदेश दिया।

सेंट्रल मिलिट्री कमीशन उत्तर कोरिया की सबसे शक्तिशाली निकायों में से एक है। उत्तर कोरिया की सुरक्षा और सेना के तीनों अंगों के संचालन की जिम्मेदारी इसी निकाय के पास है। बैठक के बाद किम जोंग उन ने सेना की युद्ध क्षमता को बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। बैठक में वर्कर्स पार्टी ऑफ कोरिया के केंद्रीय सैन्य आयोग के सदस्यों के अलावा नॉर्थ कोरियन पीपुल्स आर्मी के एक्जिक्यूटिव मेंबर्स भी शामिल हुए। बैठक में देश और दुनियाभर की रणनीतिक स्थिति से जुड़ी हालिया घटनाओं की चर्चा की गई।

किम जोंग उन ने रणनीतिक उद्देश्यों को निर्धारित करने और उन्हें मजबूत करने के तरीकों पर निर्णय लेने से पहले उत्तर कोरियाई सेना की स्थिति और प्रभावशीलता के बारे में जानकारी ली। किम जोंग ने कहा पीपुल्स आर्मी को देश की संप्रभुता और सुरक्षा के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। इतना ही नहीं, सेना को पार्टी, क्रांतिकारी कार्य, राज्य और लोगों के हितों और समाजवादी निर्माण की रक्षा भी करनी चाहिए।

किम जोंग उन के कुछ महीने पहले ही अपनी सेना को किसी भी समय परमाणु मिसाइलों को लॉन्च करने के लिए तैयार रहने का आदेश दिया था। यह आदेश उत्तर कोरिया के संस्थापक किम इल-सुंग के जन्मदिन के अवसर पर जारी किया गया था। इस दिन उत्तर कोरिया में सार्वजनिक अवकाश रहता है और लोग सन फेस्टिवल मनाते हैं।

अप्रैल में ही उत्तर कोरियाई तानाशाह ने परमाणु मिसाइल और हथियार बनाने के लिए समर्पित एक विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक कॉलेज को किम जोंग उन नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी नाम दिया गया है। यहां हाइपरसोनिक मिसाइल तकनीक विकसित करने पर काम किया जाएगा। हाइपरसोनिक मिसाइल ध्वनि की पांच गुना गति से यात्रा करने में सक्षम हैं। इन्हें वर्तमान मिसाइल रक्षा प्रणालियों के जरिए रोकना लगभग असंभव है।

उत्तर कोरिया इन दिनों किलर डॉल्फिन की सेना बनाने में जुटा हुआ है। अमेरिका की तर्ज पर इस देश में भी डॉल्फिन मछलियों को बारुदी सुरंगों को नष्ट करने और दुश्मन के गोताखोरों को मार गिराने का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। यूनाईटेड स्टेट नेवल इंस्टीट्यूट को मिली तस्वीरों के आधार पर कहा जा रहा है कि उत्तर कोरिया का नेवल मरीन मैमल प्रोग्राम अक्टूबर 2015 में शुरू हुआ था। डॉल्फिन को प्रशिक्षण देने के अड्डे को पहली बार एक शिपयार्ड के भूरे रंग के पानी में देखा गया था।

अल्जीरिया के संसदीय चुनाव में इस्लामी पार्टी ने जीत का दावा किया

अल्जीयर्स, (एजेंसी)। पार्टी कई क्षेत्रों और उससे बाहर भी बहुमत की ओर बढ़ रही है। यह बात कहते हुए अल्जीरिया के संसदीय चुनाव में एक उदारवादी इस्लामी पार्टी ने जीत हासिल करने का दावा किया है। उत्तर अफ्रीकी देश में चुनाव खत्म होने के 24 घंटे से भी कम समय में रविवार को मूवमेंट फॉर ए पीसफुल सोसाइटी के प्रमुख अब्देरजाक मकरी ने नतीजों को बदलने के लिए फजीर्वाड़ा के प्रयास के आरोपों की निंदा की।

हालांकि पार्टी ने यह नहीं बताया कि वह किस आधार पर जीत का दावा कर रही है। अल्जीरिया के चुनाव प्राधिकार के प्रमुख ने शनिवार को कहा कि संसदीय चुनाव के लिए मतदान निराशाजनक रहा, जिसमें 2.4 लाख योग्य मतदाताओं में से एक तिहाई से भी कम मतदाताओं ने भाग लिया। मतदाताओं की कम भागीदारी चुनाव प्रणाली में उनकी अरूचि, बरबर क्षेत्र में लंबे समय तक विरोध और लोकतंत्र समर्थक मुहिम द्वारा चुनाव के बहिष्कार को दर्शाती है, इसी मुहिम की वजह से देश के लंबे समय तक राष्ट्रपति रहे अब्देलअजीज बुतेफ्लिका को 2019 में इस्तीफा देना पड़ा था। चुनाव के लिए राष्ट्रीय स्वतंत्र प्राधिकरण के प्रमुख मोहम्मद चारफी ने बताया कि आधिकारिक रूप से नतीजे सामने आने में करीब चार दिन का समय लग सकता है। नयी प्रणाली के कारण 1,000 से अधिक निर्दलीय उम्मीदवारों के लिए चुनाव लड़ने का मार्ग प्रशस्त हुआ। राष्ट्रपति अब्देलमादजिद तेबुने ने नए अल्जीरिया के निर्माण की अपनी मुहिम के तहत नए चुनावी नियम बनाये हैं जिसमें ईमानदार युवाओं, महिलाओं को प्रतिनिधित्व दिया गया है।

सीरिया में गोलीबारी से क्षतिग्रस्त हुए एक अस्पताल के करीब से जाते हुए एक व्यक्ति।

चीनी रिसर्चर्स ने चमगादड़ों में ढूंढे 24 और कोरोना वायरस

वॉशिंगटन। कोरोना को लेकर फैली ऊहापाह के बीच एक ताजा स्टडी में चीनी रिसर्चर्स ने बताया है कि उन्हें चमगादड़ों में नए कोरोना वायरस मिले हैं। इनमें कोविड-19 महामारी फैलाने वाले सार्स-कोव -2 जैसा वायरस भी है। इस स्टडी के लिए सैंपल मई 2019 से लेने शुरू किए गए और नवंबर में वुहान में वायरस तेजी से फैलना शुरू हो गया था। रिपोर्ट के अनुसार रिसर्चर्स का कहना है कि उनकी खोज से पता चलता है कि चमगादड़ों में कितने कोरोना वायरस होते हैं और कितने इंसानों में फैल सकते हैं। सेल पत्रिका में छपी स्टडी में शाडॉन्ग यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स ने कहा है कि चमगादड़ की अलग-अलग प्रजातियों से कुल 24 नोवेल कोरोना वायरस जीनोम असेंबल किए गए हैं जिनमें से चार सार्स-कोव -2 जैसे हैं। सैंपल मई 2019 से नवंबर 2020 के बीच जंगल में रहने वाले चमगादड़ों से लिए गए थे। रिसर्चर्स का कहना है कि एक वायरस सार्स-कोव -2 से काफी हद तक मिलता-जुलता है। इसके स्पाइक प्रोटीन में ही कुछ अंतर है, जिसके जरिए वायरस कोशिकाओं से अटैच होता है।

अमेरिका में भारत के राजदूत संधू ने फिलाडेल्फिया में दवा कम्पनियों के अधिकारियों से की मुलाकात

वाशिंगटन, (एजेंसी)। अमेरिका में भारत के राजदूत तरनजीत सिंह संधू ने फिलाडेल्फिया के मेयर और प्रमुख दवा कम्पनियों के अधिकारियों के साथ बैठक की। 11 जून को दो दिवसीय दौर पर फिलाडेल्फिया पहुंचे संधू से बैठक के दौरान मेयर ने पिछले साल 18 लाख एन-95 मास्क भेजने के लिए भारत की सराहना की। कोरोना संकट के दौरान अमेरिका में भारत के राजदूत संघू का यह पहला फिलाडेल्फिया दौरा है।

संधू ने ट्वीट किया-फिलाडेल्फिया के मेयर जिम एफ केनी के साथ मुलाकात कर दिन की शुरूआत की। बैठक के दौरान केनी ने 2020 में 18 लाख एन-95 मास्क फिलाडेल्फिया भेजने के लिए भारत का शुक्रिया अदा किया। सितम्बर 2020 में मेयर ने भारत से मदद मांगी थी। भारतीय दूतावास ने अनुरोध पर त्वरित कार्रवाई करते हुए 18 लाख मास्क भेजे थे, जो फिलाडेल्फिया को पांच अक्टूबर 2020 को मिले थे।

बैठक के दौरान संधू और केनी ने अर्थव्यवस्था, स्वास्थ्य प्रणाली, शिक्षा और प्रवासियों से जुड़े मुद्दे पर बातचीत की। उन्होंने चिकित्सा विज्ञान सहित स्वास्थ्य सहयोग के भविष्य पर भी चर्चा की। मेयर, फिलाडेल्फिया और भारत के बीच हवाई सम्पर्क बढ़ाने को भी इच्छुक दिखे। विद्युत गतिशीलता सहित अन्य पहलों पर सहयोग करने की क्षमताओं पर भी चर्चा हुई। संधू ने एक अन्य ट्वीट में कहा आर्थिक, स्वास्थ्य देखभाल और शिक्षा संबंधों से लेकर प्रवासियों तक, भारत इस ऐतिहासिक शहर के साथ साझेदारी को महत्व देता है।

संधू ने फिलाडेल्फिया में अकुजेन के केन्द्रों और जुबिलेंट फार्मा के कार्यालय का दौरा भी किया। पेनसिल्वेनिया के यार्डली स्थित जुबिलेंट फार्मा, भारत के उत्तर प्रदेश के नोएडा स्थित जुबिलेंट लाइफ साइंसेज लिमिटेड की सहायक कम्पनी है। अकुजन इंक एक बायोफर्मास्यूटिकल कम्पनी है जो दुर्लभ आंखों की बीमारियों के इलाज के लिए जीन थेरेपी की खोज कर रही है और कोविड-19 रोधी टीके का निर्माण कर रही है। भारतीय दवा कम्पनियों के अमेरिका के सार्वजनिक स्वास्थ्य के विस्तार में अहम भूमिका निभाने की बात को ध्यान में रखते हुए उन्होंने ट्वीट किया जुबिलेंट फार्मा के अधिकारियों के साथ फिलाडेल्फिया में अच्छी बातचीत हुई। उनकी महत्वपूर्ण दवाइयां वैश्विक महामारी से निपटने में काफी कारगार साबित हुई हैं। वहीं अकुजेन के सीईओ शंकर मुसुनूरी तथा बोर्ड के अन्य सदस्यों ने संधू को बताया कि उनकी एफडीए के साथ कोविड-19 रोधी टीके कोवैक्सीन को अमेरिकी बाजार में लाने और उसके विपणन को लेकर बातचीत जारी है। अकुजेन के केन्द्रों का दौरा किया और उसके बोर्ड के सदस्यों से मुलाकात की। इस दौरान कोवैक्सीन को अमेरिका में लाने पर चर्चा हुई। संधू ने पेन्सिलवेनिया विश्वविद्यालय में सेंटर फॉर द एडवांस्ड स्टडी ऑफ इंडिया के निदेशक एवं प्रोफेसर तारिक थाचिल से भी मुलाकात की।

एम्स में 6 से 12 साल के बच्चों के लिए आज से शुरू होगी स्क्रीनिंग

नई दिल्ली । एम्स में पिछले कुछ दिनों से बच्चों पर कोरोना के टीके का ट्रायल चल रहा है। इसके तहत 12 से 18 साल की उम्र के कई बच्चों को कोवैक्सीन के टीके की पहली डोज दी जा चुकी है। इसी क्रम में मंगलवार और बुधवार को दो दिन छह से 12 साल की उम्र के बच्चों की स्क्रीनिंग की जाएगी। इस टीके के ट्रायल में शामिल होने के इच्छुक माता-पिता बच्चों को लेकर एम्स में पहुंच सकते हैं। बच्चों की स्क्रीनिंग के बाद टीका लगाया जाएगा। पहले सोमवार को स्क्रीनिंग की तैयारी थी लेकिन अब कार्यक्रम में बदलाव किया गया है। दरअसल, देश के कई अस्पतालों में दो से 18 साल की उम्र के 525 बच्चों पर कोवैक्सीन का ट्रायल होना है। इसके तहत बच्चों को तीन वर्गों में बांट कर यह ट्रायल चल रहा है। पहले 12 से 18 साल की उम्र के बच्चों को टीके की पहली डोज दी गई है।

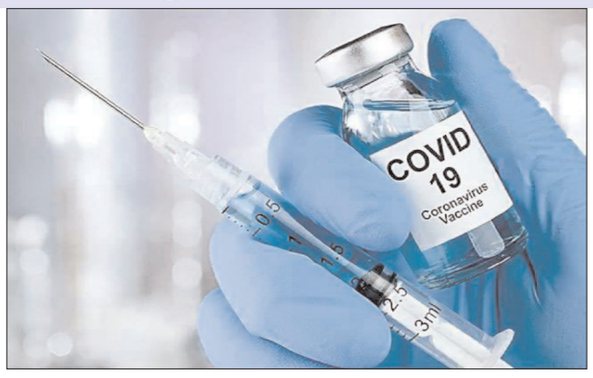

एम्स में कोवैक्सीन टीके के ट्रायल के प्रभारी डा. संजय राय ने कहा कि अब छह से 12 साल के बच्चों की स्क्रीनिंग की जाएगी। इस दौरान बच्चों की आरटीपीसीआर, एंटीबाडी सहित कई तरह की जांच की जाएगी। इस उम्र के बच्चों को टीका लगने के बाद दो से छह साल की उम्र के बच्चों की स्क्रीनिंग की जाएगी। वहीं, दिल्ली में युवाओं के लिए कोवैक्सीन का दो दिन और कोविशील्ड का एक दिन से भी कम समय का स्टाक बचा है। दिल्ली सरकार ने केंद्र सरकार से दिल्ली के युवाओं के लिए वैक्सीन का पर्याप्त स्टाक सुनिश्चित करने की अपील की है। 18 से 44 वर्ष के युवाओं के लिए 10,34,910 वैक्सीन की डोज मिली हैं, जिसमें से 61 हजार डोज अभी उपलब्ध हैं। जिसमें कोवैक्सीन की करीब 18 हजार और कोविशील्ड की करीब 43 हजार डोज उपलब्ध हैं। कोवैक्सीन केवल दूसरी डोज के लिए ही उपयोग की जा रही है। 45 वर्ष से अधिक उम्र के लिए 11 दिन का कोवैक्सीन और 24 दिन का कोविशील्ड का स्टाक उपलब्ध है। दिल्ली को 45 वर्ष से अधिक उम्र की श्रेणी के लिए शनिवार को कोवैक्सीन की 72,800 डोज मिली हैं। दिल्ली में 12 जून को 83,113 लोगों को वैक्सीन की डोज लगाई गई। जिसमें 54,788 लोगों को पहली और 28,325 लोगों को दूसरी डोज लगाई गई है। दिल्ली सरकार की ओर से रविवार को टीकाकरण बुलेटिन जारी करते हुए आम आदमी पार्टी की नेता व विधायक आतिशी ने कहा कि जैसे ही युवाओं के लिए टीकाकरण शुरू होता है वैसे ही इस कार्य की गति बढ़ जाती है।

नई दिल्ली में चल रहे कोविड-19 प्रेरित तालाबंदी के दौरान, गर्मी के मौसम के कारण पानी के संकट के बीच विवेकानंद शिविर में एक टैंकर से पीने का पानी इकट्ठा करते निवासी।

संक्षिप्त खबर

कोरोना को लेकर परेशान हैं तो इस नंबर पर करें कॉल, टेंशन जल्द हो जाएगी खत्म

नई दिल्ली । मध्य जिला प्रशासन ने इन दिनों कोरोना संक्रमण को लेकर परेशान और उससे जंग जीत चुके लोगों की काउंसिलिंग के लिए योजना बनाई है। इस योजना में मदद फाउंडेशन के साथ दिल्ली विश्वविद्यालय के मनोवैज्ञानिक कोरोना मरीजों को बीमारी से उभरने और बीमारी को लेकर बनी विचारधारा को दूर भगाने में मदद करेंगे। साथ ही उनकी तनाव, चिंता, दुख, भावनात्मक विकृति और अन्य परेशानी का परामर्श प्रदान करेंगे। मदद संस्था से जुड़े लोग अब भी लगातार लोगों के घरों तक दवा, आक्सीमीटर, आक्सीजन पहुंचाने के काम करने में जुटे हैं। वह आगे भी लोगों तक यह मदद जारी रखेंगे। मध्य जिले की जिलाधिकारी आकृति सागर ने बताया कि प्रशासन ने दिल्ली विश्वविद्यालय और मदद संस्था के साथ मिलकर कोरोना मरीजों की मदद के लिए परामर्श की पहल की है। इसके लिए नंबर भी जारी किया गया है। लोग 01149127700 पर काल कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि बहुत से ऐसे लोग हैं, जो कोरोना के कारण परेशान हैं। ऐसे लोगों की समस्याएं दूर करने के लिए प्रशासन डाटा एकत्रित कर रहा है, जिसे विश्वविद्यालय के मनोवैज्ञानिकों को दिया जाएगा, जो लोगों से बात कर उनकी परेशानी का निस्तारण करेंगे। इस पहल में आनलाइन माध्यम से लोगों की मदद की जाएगी, लोगों से 40 से 45 मिनट तक मनोवैज्ञानिक बात करेंगे। जिलाधिकारी ने बताया कि जिस व्यक्ति से बात की जाएगी। उसकी पूरी जानकारी और सवाल गोपनीय रखें जाएंगे, जिससे वह खुलकर अपनी परेशानी मनोवैज्ञानिकों को बता सकें। इसमें गार्गी कालेज, मनोविज्ञान विभाग, साउथ कैंपस, मेडिकल साइंस कालेज के मनोवैज्ञानिक शामिल रहेंगे। इसके अलावा इहबास इंस्टीट्यूट के मनोवैज्ञानिक भी समय-समय पर इसमें शामिल होंगे। जो लोगों की परेशानी सुनकर उनको तनाव मुक्त करेंगे।

नोएडा में हिंदू युवती ने नमाज पढ़ने की बनाई वीडियो, वायरल होने के बाद सच आया सामने

नोएडा । राजधानी दिल्ली से सटे गौतमबुद्धनगर में जेवर इलाके के निवासी एक युवती की मजाक में नमाज पढ़ने की एक्टिंग करते हुए वीडियो इंटरनेट मीडिया पर अपलोड कर दी गई। वहीं युवती किसी बात को लेकर अपनी मां के डांटने से नाराज होकर अपनी सहेली के यहां चली गई। इसके बाद वीडियो को युवती का धर्मांतरण करने का आरोप लगा, उसे वायरल कर दिया गया। वहीं, युवती के आने पर पिता ने ऐसी सभी अफवाहों को गलत बताते हुए पुलिस में शिकायत दी। समय रहते पूरा मामला संभल गया वरना बड़ा बवाल भी हो सकता था, क्योंकि कभी-कभार ऐसे मजाक बड़ी आफत की शक्ल अख्तियार कर लेते हैं। जेवर के मोहल्ला रावतिया की रहने वाली एक दलित युवती का नमाज पढ़ते हुए एक वीडियो इंटरनेट मीडिया पर वायरल हुआ। युवती के पिता ने बताया कि उसकी बेटी को उसकी मां ने पांच दिन पहले किसी बात को लेकर डांट दिया था। वह कस्बे में ही अपनी एक सहेली के यहां पहुंच गई और वहीं रुकी। जब पिता को पता चला तो वह उसको लेकर घर पहुंचे, इसी बीच किसी ने उसके धर्म परिवर्तन की अफवाह फैलाते हुए इंटरनेट मीडिया पर उसकी नमाज पढ़ती हुई कि वीडियो वायरल कर दी। युवती ने बताया कि वह हरियाणा में एक कंपनी में सिलाई करने के लिए तीन माह पहले नौकरी करती थी। तभी वह अपनी सहेलियों के साथ मिलकर एक दिन मजाक में नमाज पढ़ने की एक्टिंग कर रही थी और उसकी वीडियो बनाई गई, जो अब वायरल हो गई। जेवर कोतवाली प्रभारी उमेश बहादुर सिंह ने बताया कि धर्मांतरण की बात गलत है। युवती की मजाक में नमाज पढ़ती हुई वीडियो बनाई गई थी।

मेट्रो में यात्रियों से ठगी करने वाले दो ठग हुए गिरफ्तार, हो रही पूछताछ

नई दिल्ली । मेट्रो पुलिस के स्पेशल स्टाफ ने मेट्रो में यात्रियों से ठगी करने वाले दो शातिर ठग को दबोच लिया है। इनमें एक नाबालिग है। बालिग को रिमांड पर लेकर पुलिस पूछताछ कर रही है। डीसीपी मेट्रो जितेंद्र मणि के मुताबिक गिरफ्तार किए गए ठगों के नाम अजय कुमार है। वह सी-ब्लॉक, जेजे कॉलोनी, बवाना का रहने वाला है। दूसरा आरोपित 17 वर्षीय नाबालिग ए-ब्लॉक, जेजे कॉलोनी, बवाना का रहने वाला है। दिल्ली मेट्रो में ठगी, चोरी, जेब तराशी की बढ़ती घटनाओं को देखते हुए इंस्पेक्टर विवेकानंद अमोली, एसआई हरिओम को जांच की जिम्मेदारी सौंपी गई। पुलिस टीम जांच कर ही रही थी कि 12 जून को फरुखाबाद निवासी जगमोहन से ठगी करते पुलिस ने उसे दबोच लिया। वह रोहतक से दिल्ली विश्वविद्यालय आ रहा था। दिल्ली में वह इंद्रलोक मेट्रो स्टेशन पर मेट्रो ट्रेन में चढ़ गया। मेट्रो में उसे दो युवक मिले। उन्होंने शिकायतकर्ता को एक नकली कहानी सुनाई और रूमाल में लिपटे भारतीय मुद्रा का एक बंडल भी दिखाया, जिसके ऊपर पांच सौ रुपये का नोट लगा हुआ था और उसके नीचे नोटों के आकार में मुड़े हुए कागज लगे हुए थे।

किसान नेता राकेश टिकैत ने किसानों के हित के लिए केंद्र सरकार से की एक और मांग

नई दिल्ली । भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने केंद्र सरकार से अब एक नई मांग की है। उन्होंने कहा कि इस बार किसानों ने खेत में गेंहू पैदा किया है, गेंहू कट चुका है, अब किसान उसे लेकर क्रय केंद्रों पर बैठे हुए हैं। उनका कहना है कि यूपी में पंचायत चुनाव व कोरोना के कारण गेहूं खरीद सुचारू रुप से नहीं ही पायी है। कई क्रय केंद्रों पर किसान पिछले 4 दिन से मंडी में गेंहू लेकर पड़े है। दूसरी ओर सरकार गेंहू क्रय केंद्र बंद कर रही है, ऐसे में किसानों के सामने परेशानी बढ़ जाएगी। उन्होंने केंद्र सरकार से मांग की है कि वो गेंहू क्रय केंद्र पर खरीद 15 दिनों तक के लिए और आगे बढ़ाए जिससे किसान अपना गेंहू क्रय केंद्र पर बेच सकें। उन्होंने इंटरनेट मीडिया के माध्यम से सरकार से ये मांग भी की है। ट्वीट करते हुए उन्होंने केंद्र सरकार के सामने यही मांग रखी है। मालूम हो कि किसान

संगठन तीन कृषि कानूनों के विरोध में बीते छह माह से दिल्ली की सीमा पर धरना देकर प्रदर्शन कर रहे हैं। उधर कृषि कानून के विरोध में यूपी बार्डर पर चल रहे धरना-प्रदर्शन को एक बार फिर से धार देने का प्रयास किया जा रहा है।

इसके लिए आपातकाल की बरसी के अगले दिन 26 जून को चुना गया है। संयुक्त किसान मोर्चा खेती बचाओ लोकतंत्र बचाओ अभियान के तहत धरना प्रदर्शन करेगा। किसान नेता तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को भी तानाशाह बताते हुए मौजूदा सरकार से तुलना कर रहे हैं। शुरूआत से धरने का समर्थन कर रही कांग्रेस के नेताओं में 26 जून के धरने को लेकर ऊहापोह की स्थिति है और वह कुछ भी बोलने से बच रहे हैं।

बता दें कि कृषि कानून के विरोध में यूपी बार्डर पर करीब साढ़े छह माह से धरना चल रहा है। यूपी गेट पर दिल्ली जाने वाली सभी लेनों पर कृषि कानून विरोधियों का कब्जा है। इस धरने प्रदर्शन को कांग्रेस ने जमकर हवा दी और पार्टी के राष्ट्रीय नेताओं से लेकर प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू, उत्तराखंड़ के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत समेत कई बड़े नेता शामिल हुए। समय-समय पर यहां दूसरे प्रदेश व जिलों से कांग्रेसियों ने धरना स्थल पर पहुंचकर कृषि कानून विरोधियों का समर्थन किया। अब 26 जून को आपातकाल की बरसी के अगले दिन धरने के सात माह पूरे होने पर संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है।

आनंद विहार बस अड्डा परिसर में शुरू हुआ भूमिगत हिस्से का काम

नई दिल्ली । दिल्ली-मेरठ रीजनल रैपिड रेल परियोजना के भूमिगत हिस्से का निर्माण करने के लिए आनंद विहार बस अड्डा परिसर में सुरंग खोदने से पहले सुरक्षा दीवार बनाने का काम रविवार को शुरू कर दिया गया है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम (एनसीआरटीसी) ने अधिकारियों ने बताया कि सुरंग बनाने के लिए टनल बोरिंग मशीन (टीबीएम) उतारने के लिए लांचिंग शाफ्ट का निर्माण करने के लिए यह दीवार बनाना अहम है। तकनीकी तौर इस दीवार को डायफ्राम वाल (डी-वाल) कहा जाता है। यह दीवार सुरंग के लिए मिट्टी खोदते वक्त ढाल का काम करती है। मिट्टी ढहने और पानी की रिसाव जैसे खतरों को टाला जा सकता है। अधिकारियों ने बताया कि इसे बनने में वक्त लगेगा। सुरंग की खोदाई का कार्य अगले वर्ष शुरू किया जाएगा।

दस मंजिल जितनी गहरी होगी सुरंग- न्यू अशोक नगर से आनंद विहार बस अड्डा होते हुए साहिबाबाद बीईएल तक रैपिड रेल का 5.60 किलोमीटर भूमिगत कारिडोर बनाया जाना है। आनंद विहार बस अड्डा परिसर में स्टेशन भी भूमिगत होगा। यह भूमिगत हिस्सा जमीन के 20 मीटर नीचे बनेगा। सामान्य रूप में इस गहराई को समझा जाए तो खोदाई के बाद नीचे से ऊपर तक करीब दस मंजिला इमारत खड़ी की सकती है।

भूमिगत हिस्से की चौड़ाई करीब 6.50 मीटर व्यास की होगी। एनसीआरटीसी के अधिकारियों ने बताया कि सुरंग बनाने के लिए 20 मीटर लंबी और पांच मीटर सुरक्षा दीवार बनाई जाएगी। जोकि पूरी तरह कंक्रीट की होगी। लांचिंग शाफ्ट 20 मीटर लंबी और 16 मीटर चौड़ी बनाई जाएगी।

चार टीबीएम से खोदी जाएगी सुरंग- भूमिगत हिस्से को बनाने के लिए चार टीबीएम की मदद से सुरंग खोदी जाएगी। दो टीबीएम से आनंद विहार बस अड्डे से न्यू अशोक नगर की तरफ करीब तीन किलोमीटर लंबी सुरंग बनाई जाएगी। जबकि बाकी दो टीबीएम से आनंद विहार बस अड्डे से साहिबाबाद बीईएल तक सुरंग खोदी जाएगी। भूमिगत हिस्से में वायु संचार के लिए एक एयर वेंटिलेशन शाफ्ट का निर्माण भी किया जाएगा। आपातकालीन स्थिति में भूमिगत स्टेशन से यात्रियों को सुरक्षित निकालने के लिए आपातकालीन निकासी सुविधा का निर्माण भी किया जाएगा।

बालाकोट स्ट्राइक का हिस्सा रहीं विधु को दिल्ली हाई कोर्ट से नहीं मिली अंतरिम राहत

नई दिल्ली । बालाकोट एयर स्ट्राइक में अहम भूमिका निभाने वालीं विंग कमांडर विधु सिंह को दिल्ली हाई कोर्ट से अंतरिम राहत नहीं मिली है। तीन जून को उनकी सेवा समाप्त करने के वायुसेना के आदेश को विधु ने चुनौती देते हुए आवेदन दाखिल किया था। आवेदन पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति नवीन चावला व न्यायमूर्ति आशा मेनन की अवकाशकालीन पीठ ने अंतरिम राहत देने से इन्कार कर दिया। विधु ने यह आवेदन मुख्य याचिका पर दाखिल किया है। उन्होंने इससे पहले महिला सैन्य अधिकारियों को स्थायी कमीशन देने से जुड़ी नीति को रद करने से इनकार करने के आर्म्ड फोर्स टिब्यूनल (एएफटी) के फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दी थी।

विधु वर्तमान में उप्र के गाजियाबाद के राजनगर में रहती हैं। अधिवक्ता अंकुर छिब्बर के माध्यम से आवेदन दाखिल कर विधु ने दलील दी कि हाई कोर्ट ने उनकी याचिका पर पिछली तारीख पर केंद्र समेत अन्य पक्षकारों को नोटिस जारी कर 19 जुलाई तक जवाब मांगा था। साथ ही अदालत ने केंद्र के स्टैंडिंग काउंसल को मौखिक निर्देश भी दिया था कि वह प्रतिवादी को सूचित करें कि

अगली सुनवाई तक विधु को सेवा से रिलीज न किया जाए।

अधिवक्ता अंकुर छिब्बर ने कहा, इस सुनवाई में वायुसेना के अधिकारी भी वर्चुअल तरीके से शामिल थे, लेकिन वायुसेना ने अवैध व मनमाने तरीके से तीन जून को सेवा समाप्त करने का आदेश विधु को चार जून सौंप दिया। विधु ने आवेदन दाखिल कर तीन जून के आदेश पर अगली सुनवाई तक रोक की मांग की थी।

यह है मामला- अधिवक्ता अंकुर छिब्बर के माध्यम से दायर की गई याचिका में विधु ने कहा, शार्ट सर्विस कमीशन के तहत उनकी नियुक्त एरोनाटिकल इंजीनियरिंग ब्रांच में 2007 में हुई थी। महिला सैन्य अधिकारियों को स्थायी कमीशन देने से जुड़ी नई नीति 16 जनवरी 2019 को आई थी और इसके तहत हर अधिकारी को तीन मौके दिए जाने थे। विधु को स्थायी कमीशन को दो मौके दिए गए। विधु ने स्थायी कमीशन हासिल करने को बनाई गई नीति को एएफटी में चुनौती देते हुए अंतरिम राहत की मांग की थी। एएफटी ने राहत से इन्कार कर दिया।

एक जनवरी 2021 को विधु की सेवा समाप्त हो रही थी। ऐसे में उन्होंने हाई कोर्ट में याचिका दायर की। तत्कालीन न्यायमूर्ति प्रतिबा एम सिंह व न्यायमूर्ति एस प्रसाद की पीठ ने एएफटी द्वारा निर्णय लिए जाने तक विधु को रिलीज करने पर रोक लगा दी थी। इसके बाद एएफटी ने 16 मार्च 2021 को स्थायी कमीशन की नीति पर कोई भी टिप्पणी न करते हुए कहा, वायु सेना को विधु को तीसरा मौका दिया जाना चाहिए। लेकिन, वायुसेना ने उनको स्थायी कमीशन देने से इन्कार कर दिया। इस फैसले को विधु ने हाई कोर्ट में चुनौती दी है और इस पर आगामी 19 जुलाई को सुनवाई होनी है। विधु ने नई नीति के तहत बनाई गई कैटेगरी ग्रेडिंग को अवैध करार दिया है। उनका कहना है कि नई नीति आने से पहले तक उन्हें कंबाइड कोर्स को सिर्फ पास करना जरूरी था। उस समय बेहतर ग्रेडिंग हासिल करने के संबंध में कोई जानकारी नहीं दी गई थी।

नई दिल्ली में उच्च अध्ययन के लिए विदेश यात्रा करने वाले छात्रों के लिए आयोजित टीकाकरण केंद्र में छात्र कोविड-19 वैक्सीन की एक खुराक प्राप्त करने की प्रतीक्षा करते हुए।

केजरीवाल का रेस्टोरेंट, माल जैसी बंद जगहों को खोलने का फैसला तर्कहीन : कांग्रेस

नई दिल्ली । प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अनिल चौधरी ने राजधानी में सुबह 10 बजे से रात आठ बते तक बाजार खोलने के फैसले पर अपनी आपत्ति जताते हुए कहा कि इससे भीड़ बढ़ेगी, संक्रमण का खतरा बढ़ेगा। वजह, इस गर्म मौसम में लोग दोपहर के समय कम ही निकलते हैं। उन्होने दिल्ली सरकार से बाजार खुलने की समयावधि को बढ़ाने, सभी साप्ताहिक बाजार व पार्कों को खोलने तथा शादियों, अंतिम संस्कार में कुछ और लोगों को बुलाने की छूट देने की मांग की। चौधरी ने केजरीवाल के अनलाक प्रक्रिया में पार्कों को बंद रखने के फैसले को भी गलत बताया। उन्होने कहा कि दिल्ली कि जनता 19 अप्रैल से लाकडाउन के कारण घरों में बंद हैं। ऐसे में पार्कों को खोलने से लोग व्यायाम कर पाते व खुली हवा में साँस ले सकेंगे। लेकिन, पार्क को नहीं खोला गया है।

उन्होंने कहा कि केजरीवाल का रेस्टोरेंट, माल जैसी बंद जगहों को खोलने व पार्क जैसे खुली जगहों को बंद रखने का फैसला तर्कहीन है। उन्होंने प्रत्येक एमसीडी जोन में मात्र एक साप्ताहिक बाजार खोलने के फैसले का भी विरोध किया। उन्होने कहा कि कांग्रेस की स्पष्ट मांग है कि सभी साप्ताहिक बाजार खोले जाने चाहिए।

कोरोना के मामले घट रहे हैं, सावधानी जरूरी- मीनाक्षी- वहीं, नई दिल्ली से सांसद मीनाक्षी लेखी ने चितरंजन पार्क में जरूरतमंदों को राशन व कोरोना से बचाव के लिए 300 लोगों को किट वितरित की। इस दौरान मीनाक्षी लेखी ने कि कहा कि अब कोरोना के मामले कम हो रहे हैं। इसके बावजूद लोगों को पूरी सावधानी बरतने की जरूरत है। अगर लोगों ने जरा सी भी लापरवाही बरती तो संक्रमण फैलने का खतरा फिर से बढ़ सकता है। खुद सावधान रहने के साथ ही अपने घर परिवार के लोगों को भी इसके प्रति जागरूक करते रहें। मीनाक्षी लेखी ने कहा कि भाजपा ने सेवा ही संगठन अभियान के तहत राजधानी के लाखों लोगों की सहायता की है। यह अभियान अभी भी जारी है, जबकि कोरोना काल में अन्य राजनीतिक दलों के नेता घरों में बैठे रहे।

दिल्ली-पटना की फ्लाइट में बम होने की दी थी सूचना, दिल्ली एयरपोर्ट पर हुआ गिरफ्तार

नई दिल्ली । दिल्ली स्थित इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे पर दिल्ली पुलिस ने एक ऐसे शख्स को पकड़ा है, जिसने दिल्ली-पटना की फ्लाइट में बम होने की सूचना दी थी। आरोपित की उम्र 22 साल बताई जा रही है। गिरफ्तारी के बाद दिल्ली पुलिस उससे पूछताछ कर रही है। दिल्ली पुलिस के मुताबिक, शुरुआती जांच में यह फर्जी कॉल लग रहा है और युवक भी मानसिक रूप से विक्षिप्त लग रहा है।

गौरतलब है कि इसी साल अप्रैल महीने में भी इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एक विमान को बम से उड़ाने की धमकी से सनसनी फैल गई थी। जांच के दौरान एयरपोर्ट के एक शौचालय में एक पर्ची मिली थी, जिस पर बेंगलूरु से दिल्ली आने वाले विमान में बम होने और उसके दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचते ही उड़ाने की बात लिखी गई थी। वहीं, छानबीच ने विमान में कोई विस्फोटक नहीं मिला था। वहीं, नवंबर, 2019 में दिल्ली एयरपोर्ट पर आरडीएक्स से भरा संदिग्ध बैग मिलने की अफवाह के बाद एयरपोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी भरा मैसेज मिला था। मैसेज एक युवती की फेसबुक प्रोफाइल से दिल्ली एयरपोर्ट के ऑपरेशन की जिम्मेदारी संभालने वाली डायल के फेसबुक पेज पर भेजा गया था। इससे एयरपोर्ट प्रबंधन, पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों में हड़कंप मच गया था। वहीं, सघन जांच के बाद इसमें कोई संदिग्ध सामान या विस्फोटक नहीं मिला था। दरअसल, डायल के फेसबुक पेज पर धमकी भरा मैसेज मिलने की शिकायत की थी। मैसेज में एयरपोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी दी गई थी। शिकायत पर कार्रवाई करते हुए पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों ने तत्काल एयरपोर्ट पर सघन तलाशी अभियान चलाया था, लेकिन वहां ऐसा कोई संदिग्ध सामान नहीं मिला था।

कृषि कानून के विरोध में बैठे आंदोलनकारियों ने ग्रामीण पर किया जानलेवा हमला, विरोध में होगी महापंचायत

सोनीपत । कृषि कानून के विरोध में धरने पर बैठे आंदोलनकारियों ने सेरसा गांव निवासी रामनिवास पर शनिवार शाम को जानलेवा हमला कर दिया। उनकी कार तोड़ डाली और उन पर डंडों व धारदार हथियार से हमला किया। उन्होंने 200 मीटर दौड़कर और एक दुकान के अंदर घुसकर अपनी जान बचाई। रामनिवास को वहां से कुंडली पुलिस ने सुरक्षित निकाला। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर रामनिवास का चिकित्सकीय परीक्षण कराया है। वहीं, घटना से नाराज क्षेत्र के दर्जनभर गांवों के लोगों ने कथित आंदोलनकारियों की मनमानी का मुकाबला करने का एलान किया है। इसके लिए क्षेत्र में जल्द ही महापंचायत आयोजित की जाएगी।

क्या है विवाद का कारण- रामनिवास (58) ने बताया कि वे अपने मकानों का किराया लेने कुंडली गए थे। जीटी रोड से गांव जाने वाले रास्ते पर आंदोलनकारियों ने पत्थर

लगाकर रोड जाम कर रखा था। इस पर उन्होंने सड़क के एक किनारे से होकर अपनी कार को निकालने का प्रयास किया। इसी दौरान आंदोलन में शामिल एक युवा ने उनकी कार पर डंडे बरसाने शुरू कर दिए। इससे कार में नुकसान हो गया। इस पर वे नीचे उतरे और कार पर डंडा मारने का कारण पूछने लगे।

धारदार हथियार से किया वार- रामनिवास ने बताया कि उसी समय 10-12 कथित आंदोलनकारी वहां पर पहुंचे और बिना कुछ कहे-सुने उन पर हमला बोल दिया। उनको डंडे मारे गए और किसी धारदार हथियार से वार किया गया। इस पर जान बचाने के लिए वह भाग निकले। हमलावरों ने भागते समय भी करीब सौ मीटर तक उनका पीछा किया और उनको लगातार डंडे मारे गए। करीब 200 मीटर दूर वे अपने एक परिचित की दुकान में घुस गए और शटर गिरा लिया। वहां से घटना की जानकारी पुलिस को दी गई। सूचना पाकर कुंडली थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने कार को मौके से हटाया और रामनिवास को लेकर नागरिक अस्पताल पहुंचे। पुलिस ने रामनिवास की शिकायत पर रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

किसानों के विरोध में सोमवार को होगी पंचायत- हमले से नाराज क्षेत्र के दर्जनभर गांवों के लोगों ने सेरसा व मनौली गांव में बैठक का आयोजन किया। इसमें निर्णय लिया गया कि कथित आंदोलनकारियों के नाम पर गुंडागर्दी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ये आंदोलनकारी हमारा रास्ता बंद करके आए दिन मारपीट कर रहे हैं। पुलिस प्रशासन भी हमारी सुनवाई नहीं कर रहा। इसके चलते सोमवार को क्षेत्र के ग्रामीणों की पंचायत बुलाई गई है। इसमें आरपार की रणनीति तैयार कर कथित आंदोलनकारियों का मुकाबला कर रास्ता खुलवाया जाएगा। बैठक में पुलिस अधिकारियों पर धरना दे रहे लोगों का सहयोग करने का आरोप लगाया है।

पुलिस ने कहा- सेरसा गांव के रामनिवास पर डंडों से कई वार किए गए हैं। आंदोलनकारियों ने रास्ता रोक रखा है। वहां पर कार निकालने को लेकर दोनों पक्षों में विवाद हुआ था। हमने रिपोर्ट दर्ज कर ली है। आरोपितों की पहचान कर यथोचित कार्रवाई की जाएगी।

रवि कुमार, एसएचओ, थाना कुंडली।

संपादकीय

उन्हें जरूरी लगाम से परहेज क्यों

सोशल मीडिया के क्षेत्र में हाल ही में दो अलग, लेकिन महत्वपूर्ण घटनाक्रम हुए हैं। एक ओर, सरकार ने सामग्री (कंटेंट) पर अपने एकतरफा विचारों के लिए ट्विटर पर सवाल उठाए हैं। दूसरी ओर, एक अन्य मोर्चे पर वाट्सएप (फेसबुक के स्वामित्व वाले) ने दिल्ली उच्च न्यायालय में भारत के नियामक कानूनों को चुनौती दे दी है। आइए देखें कि इन दोनों घटनाओं में क्या समानता और क्या अंतर है। विवाद लंबे समय से चल रहा है, लेकिन अभी जो अलग व नया है, उससे हम शुरुआत कर सकते हैं। वाट्सएप ने अपने नए गोपनीयता नियम घोषित किए हैं, जो उसे यूजर्स अर्थात उपयोगकर्ताओं की व्यक्तिगत सूचनाएं जुटाने और अपने ग्राहकों (कंपनियों) को देने की अनुमति देंगे। फेसबुक अब वाट्सएप, इंस्टाग्राम और मैसेंजर का मालिक है और वह इन सभी के यूजर्स की सूचनाओं को जुटाना चाहता है। ऐसे नियमों को लेकर भारत सरकार ने फेसबुक पर सवाल खड़े किए हैं।

सरकार फर्जी और दुर्भावनापूर्ण सूचनाओं के तेज प्रसार को लेकर भी चिंतित है। इस संबंध में उसने फेसबुक और वाट्सएप को एक प्रावधान करने के लिए कहा है, जहां जरूरत पड़ने पर सामग्री या कंटेंट के प्रवर्तक या मूल लेखक की पहचान की जा सके। जहां तक दो लोगों के बीच के संदेश का प्रश्न है, तो वे सुरक्षित हैं और सरकार की मांग से प्रभावित नहीं होंगे। पर कुछ मामलों में एक नियत प्रक्रिया के तहत सरकार जानना चाहती है कि कौन ऐसे कंटेंट तैयार कर रहा है, जो आपराधिक या हानिकारक हो सकते हैं। नए आईटी नियमों में एक 'ट्रेसबिलिटी क्लॉज' शामिल है, जिसके तहत अधिकारी सूचना के पहले प्रवर्तक का पता लगाने के लिए किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से सूचनाएं मांग सकेंगे। वाट्सएप का कहना है, उसकी तकनीक इसकी इजाजत नहीं देती और उसका यह भी दावा है कि इससे उपभोक्ता की निजता को ठेस पहुंचेगी। हालांकि, फेसबुक जैसी कंपनी के ऐसे विचार को मानना मुश्किल है। उसने तो निजता पर हमला करने और व्यक्तिगत डाटा बेचने का व्यवसाय किया है। यदि वाट्सएप के दावे के अनुसार, तकनीक 'ट्रेसबिलिटी' (कंटेंट के मूल लेखक की खोज) की अनुमति नहीं देती, तो उसे इसका समाधान खोजना चाहिए, जो 'ट्रेसबिलिटी' को संभव कर सके। अब ट्विटर के मुद्दे पर नजर डालते हैं। सवाल है, क्या कॉरपोरेट मुख्यालय में बैठे कुछ लोग तय कर सकते हैं कि दुनिया के लिए अच्छी सामग्री क्या है? जनवरी 2021 में अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को हटाने के लिए ट्विटर, फेसबुक साथ आ गए थे। क्या ये कंपनियां एकतरफा फैसले कर सकती हैं, किसे मंजूरी हो और किसे नहीं? ऐसी कंपनियों के आलोचकों के पास उनके पक्षपात और अपारदर्शी फैसलों को लेकर कई वाजिब सवाल हैं। हर लोकतंत्र में सेंसरशिप और अभिव्यक्ति की आजादी का मुद्दा कानून की उचित प्रक्रिया द्वारा तय होता है। विशिष्ट कानून, न्यायपालिका और सरकारी एजेंसियां एक प्रक्रिया के तहत अभिव्यक्ति की आजादी के मुद्दों पर फैसले करती हैं। क्या हम कुछ कंपनियों के कुछ लोगों को दुनिया के लिए अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता तय करने को मंजूरी दे सकते हैं? ट्विटर ने तो सामग्री के साथ छेड़छाड़ या 'मैनुपुलेटेड मीडिया' का टैग जोड़ना शुरू कर दिया है, पर उसे ऐसे फैसले किस तरह लिए जाते हैं, इसमें कोई पारदर्शिता नहीं है। आइए अब उन मुद्दों पर नजर डालते हैं, जो भारत में वाट्सएप और ट्विटर से जुड़े विवादों के बीच आम हैं। मूल रूप से हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि भारत सोशल मीडिया की दिग्गज कंपनियों के लिए सबसे बड़ा खुला बाजार है। चीन ने इन कंपनियों को ब्लॉक कर रखा है और अपनी अलग घरेलू सोशल मीडिया कंपनियां बना रखी हैं। इसलिए इन कंपनियों के पास अपने विस्तार के लिए केवल भारत जैसा क्षेत्र है। भारत की आबादी और बाजार का आकार अमेरिका और यूरोप से भी बड़ा है। ये कंपनियां बिना किसी नियम-कानून के इन बाजारों में अपना विस्तार चाहती हैं। दिलचस्प बात यह है कि दुनिया के सभी लोकतंत्र अब इन कंपनियों की ताकत पर सवाल उठा रहे हैं और चुनौती दे रहे हैं। भले ही ट्विटर और फेसबुक की डोनाल्ड ट्रंप को हटाने में भूमिका रही हो, लेकिन नए राष्ट्रपति जो बाइडन की सरकार भी इन कंपनियों की लगाम कसने में लगी है। बाइडन प्रशासन को भी पता है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और गोपनीयता तय करने की शक्ति निजी कंपनियों पर नहीं छोड़ी जा सकती। यूरोप ने सख्त कानून बनाए हैं। अमेरिकी सीनेट ने भी सोशल मीडिया दिग्गजों से सवाल किए हैं। अमेरिका में इन कंपनियों को छोटे उद्यमों में बांट देने के लिए बड़ा आंदोलन चल रहा है, ताकि वे अपने बड़े आकार का दुरुपयोग न कर सकें। भारत को इन कंपनियों पर सख्त होना पड़ेगा और ऐसे नियमों को लागू करना होगा, जो समाज के लिए अच्छे हों। अगर अमेरिका और यूरोपीय संघ इन कंपनियों के नियमों को सख्त कर सकते हैं, तो भारत भी कर सकता है। कुछ आलोचक भारत पर उत्तर कोरिया जैसा बनने या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर अंकुश लगाने का आरोप लगा रहे हैं। यह बिल्कुल भ्रामक है। एक समाज के रूप में हमें मांग करनी चाहिए कि एक उचित, पारदर्शी प्रक्रिया और स्वतंत्र एजेंसी द्वारा सोशल मीडिया प्रबंधित हो। यह एजेंसी तय करे कि स्वतंत्रता और गोपनीयता क्या है। ट्विटर और वाट्सएप को भी ऐसी कानूनी प्रक्रिया मंजूर करनी चाहिए, ताकि सरकार द्वारा मांगे जाने पर जरूरी सूचनाएं उसे मुहैया हों। याद रहे कि दूरसंचार सेवा ऑपरेटर भी सरकार द्वारा मांगे जाने पर प्रासंगिक सूचनाएं साझा करते हैं, और इसकी बदौलत लाखों अपराध सुलझे हैं। जब सरकार ने मांग की थी कि प्रत्येक सिम कार्ड खरीदार को एक पहचान दस्तावेज जमा करना होगा, तब दूरसंचार कंपनियों ने विरोध किया था। लेकिन सरकार ने उन्हें मजबूर कर दिया और हम अब उसके फायदे देख सकते हैं। फोन टेप के लिए भी एक तय प्रक्रिया है और सरकार में कोई न कोई ऐसे फैसलों के लिए जवाबदेह होता है। ऐसा नहीं हो सकता कि निजी कंपनियां अपने फायदे के लिए हमारी निजता पर हमला करें और जब चाहे, हमारे डाटा का इस्तेमाल करें। एक उचित प्रक्रिया और कानूनों के साथ सरकार को अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए सूचना मांगने का पूरा अधिकार है। निजता और अभिव्यक्ति की आजादी पर कोई भी फैसला निजी कंपनियों को नहीं, राष्ट्रीय संस्थानों को लेना चाहिए।

प्रवीण कुमार सिंह

कंपनियां जनता के प्रति तो जवाबदेह हों, पर सरकार के पूर्णतया अधीन न हों

तीसरा उपाय यह है कि कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया को आदेश दिया जाए कि वह किसी भी इंटरनेट मीडिया कंपनी के भारत में अधिकतर सदस्यों की संख्या निर्धारित कर दे, जैसे कमीशन तय कर दे कि कोई भी कंपनी दो करोड़ से अधिक सदस्य नहीं बना सकती। यदि वह दो करोड़ से अधिक सदस्य बनाएगी तो कंपनी का दो टुकड़ों में विभाजन कर दिया जाएगा। ऐसा करने से तमाम कंपनियां बन जाएंगी और किसी एक पर हमारी निर्भरता समाप्त हो जाएगी। हमें इस चिंता में बिल्कुल नहीं रहना चाहिए कि इंटरनेट मीडिया कंपनियों पर नियंत्रण से भारत की साख गिरेगी और विदेशी निवेश का अकाल पड़ जाएगा।

किसी देश में जो भी वाणिज्यिक गतिविधियां करता है, उसे उस देश की जनता के प्रति जवाबदेह होना चाहिए। हम भूल नहीं सकते कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने व्यापार के माध्यम से देश पर किस प्रकार कब्जा किया और विश्व की आय में देश का हिस्सा 200 वर्षों में किस तरह 23 प्रतिशत से घटकर मात्र दो प्रतिशत रह गया था। इंटरनेट मीडिया कंपनियों की पैठ ईस्ट इंडिया कंपनी से ज्यादा गहरी है, क्योंकि वे हमारी मानसिकता को ही प्रभावित कर रही हैं। आज इन कंपनियों ने यह भ्रामक प्रचार कर रखा है कि यदि भारत ने उन पर नियंत्रण करने का प्रयास किया तो विदेशी निवेश मिलना बंद हो जाएगा। पहली बात तो यह कि विदेशी निवेश मिलना बंद नहीं होगा। चीन में तमाम नियंत्रण के बावजूद भी विदेशी निवेश आना बंद नहीं हुआ है। दूसरी बात यह कि यदि विदेशी निवेश मिलना बंद हो जाता है तो देश का आर्थिक स्वास्थ्य सुधर जाएगा। कई बार विदेशी निवेश आकर्षित करने का आडंबर इसलिए किया जाता है, ताकि देश के अमीर अपनी पूंजी आसानी से बहार ले जा सकें। इस प्रकार के मिथ्या और भ्रामक प्रचार पर नियंत्रण करने के लिए जरूरी है कि इंटरनेट मीडिया कंपनियां देश की जनता के प्रति जवाबदेह हों।

बीते समय में ट्विटर ने राष्ट्रपति ट्रंप को प्रतिबंधित कर दिया था। हाल में उसने भारत में भाजपा नेताओं की कुछ खबरों को गुमराह करने वाली सूचना बता दिया। विषय यह नहीं कि ऐसा करके सही किया या गलत? विषय यह है कि इन खबरों के सच अथवा झूठ होने का निर्णय ट्विटर अपने वाणिज्यिक स्वार्थों की दृष्टि से करेगा अथवा देश की जनता? इस दृष्टि से सरकार ने इन इंटरनेट मीडिया कंपनियों पर जो नियम लगाए हैं, वे पूर्णतया सही हैं। सरकार ने कहा है कि इन्हें एक शिकायत निवारण अधिकारी और सरकार से संबंध स्थापित करने के लिए एक विशेष

अधिकारी नियुक्त करना होगा। इसी क्रम में सरकार ने वाट्सएप से कहा है कि वह किसी सूचना का मूल स्नोत पता लगाने की व्यवस्था करे।

जिस प्रकार कोरियर वाले को मालूम नहीं होता कि पैकेट में क्या है, पर वह बता सकता है कि पैकेट किसने भेजा, उसी प्रकार वाट्सएप भी बताए कि संदेश कहां से शुरू हुआ? आइआइटी मद्रास के प्रोफेसर कामकोटी के अनुसार यह संभव है कि वाट्सएप बिना कंटेंट खोले, उसके मूल स्नोत का पता लगा सकता है। सरकार द्वारा बनाया गया नियम तो ठीक है, पर इस नियंत्रण की जिम्मेदारी सरकारी अधिकारियों के हाथ में देने से दूसरा संकट पैदा होगा। ध्यान रहे कि चीन ने वुहान में कोरोना वायरस पनपने की खबरों पर रोक लगा दी। इसी तरह म्यांमार के शासक जनता के दमन की खबरों पर रोक लगा रहे हैं। हमारे सामने दो परस्पर विरोधी उद्देश्य हैं। एक तरफ इंटरनेट मीडिया कंपनियों को जनता के प्रति जवाबदेह होना चाहिए और दूसरी तरफ उन्हें सरकार के नियंत्रण से बाहर रखा जाना चाहिए। इस दिशा में फेसबुक ने एक ओवरसाइट बोर्ड की स्थापना की है, जो उसके द्वारा लिए गए निर्णयों की समीक्षा करता है। खबरों के अनुसार अपील किए गए मामालों में फेसबुक के पांच में से चार निर्णयों को ओवरसाइट बोर्ड ने गलत ठहराया। इसके बाद फेसबुक ने बोर्ड की सलाह का अनुपालन भी किया। ओवरसाइट बोर्ड सही दिशा में कार्य करता दिख रहा है, लेकिन यह बोर्ड फिर भी भारत की जनता के प्रति जवाबदेह नहीं है और भारत की संप्रभुता के बाहर है। ऐसे में यह जरूरी है कि ऐसी व्यवस्था बनाई जाए कि इंटरनेट मीडिया कंपनियां देश की जनता के प्रति तो जवाबदेह हों, पर सरकार के पूर्णतया अधीन न हों। उक्त दोनों परस्पर विरोधी उद्देश्यों को हासिल करने के तीन उपाय दिखते हैं। पहला यह कि सभी इंटरनेट मीडिया कंपनियों को आदेश दिया जाए कि वे भारत में एक नई कंपनी गठित करें और अपनी गतिविधियों को उसी के तत्वाधान में क्रियान्वित करें। इस कंपनी में भारत सरकार द्वारा स्वतंत्र निदेशकों को नियुक्त किया जा सकता है, जैसे कंपनियों में स्वतंत्र निदेशक नियुक्त किए जाते हैं। छोटे निवेशकों के हितों की रक्षा करना इनकी जिम्मेदारी होती है। जैसे कंपनियों के बोर्ड में ऋण देने वाले बैंक द्वारा अपना प्रतिनिधि नियुक्त कर दिया जाता है, वैसे ही इंटरनेट मीडिया कंपनियों के बोर्डों में एक स्वयं कंपनी द्वारा स्वतंत्र निदेशक हो और एक सरकार द्वारा तय स्वतंत्र निदेशक और एक सरकार के प्रतिनिधि के रूप में तय निदेशक। ऐसा करने से कंपनी की गतिविधियों की पूर्ण जानकारी इन निदेशकों को रहेगी और वे कंपनी के निर्णयों में दखल भी दे सकेंगे।

दूसरा उपाय यह है कि भारत सरकार को आत्मनिर्भर डिजिटल प्लेटफॉर्म प्रोत्साहित करना चाहिए। वाट्सएप द्वारा निजता का उलंघन करने की नीति बनाने के बाद सिग्नल और टेलीग्राम जैसे प्लेटफार्म में वृद्धि हुई है, लेकिन ये भी विदेशी कंपनियां हैं। उनकी शरण में जाना तो कुएं से निकलकर खाई में गिरने जैसा है। इसलिए भारत सरकार को आत्मनिर्भर डिजिटल प्लेटफॉर्म को प्रोत्साहन देने के लिए देश की कंपनियों के लिए पैकेज बनाना चाहिए कि यदि वे दस लाख या इससे अधिक सदस्य बनाएंगी तो उन्हें प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। ऐसा करने से देश में कई इंटरनेट मीडिया कंपनियां पनप जाएंगी और फेसबुक और ट्विटर पर हमारी निर्भरता स्वतः समाप्त हो जाएगी।

तीसरा उपाय यह है कि कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया को आदेश दिया जाए कि वह किसी भी इंटरनेट मीडिया कंपनी के भारत में अधिकतर सदस्यों की संख्या निर्धारित कर दे, जैसे कमीशन तय कर दे कि कोई भी कंपनी दो करोड़ से अधिक सदस्य नहीं बना सकती। यदि वह दो करोड़ से अधिक सदस्य बनाएगी तो कंपनी का दो टुकड़ों में विभाजन कर दिया जाएगा।

ऐसा करने से तमाम कंपनियां बन जाएंगी और किसी एक पर हमारी निर्भरता समाप्त हो जाएगी। हमें इस चिंता में बिल्कुल नहीं रहना चाहिए कि इंटरनेट मीडिया कंपनियों पर नियंत्रण से भारत की साख गिरेगी और विदेशी निवेश का अकाल पड़ जाएगा। विदेशी निवेश के अकाल का भय इन्हीं इंटरनेट मीडिया कंपनियों के दिमाग की उपज है, ताकि वे ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह भारत के मानस को सम्मोहित करके अपने क्षुद्र स्वार्थ हासिल कर सकें।

डिजिटल सेवाओं के लिए देना होगा सुविधा शुल्क

दुनिया को जोड़ने वाला, इंटरनेट। एक क्लिक पर हमारे हर सवाल के तमाम जवाब देने वाला, इंटरनेट। घर बैठे शॉपिंग और फिर घर बैठे ही डिलीवरी करने वाला, इंटरनेट। आम हो या खास सबकी एक जरूरत बन चुका है यह इंटरनेट। इतनी खूबियों वाले इंटरनेट का फायदा उठाने के लिए एक अदद कंप्यूटर या मोबाइल के साथ जिस चीज की जरूरत होती है वो है एक सर्च इंजन। सारी दुनिया में आज खोज का पर्याय बन चुकी कंपनी का नाम है गूगल। गूगल इंटरनेट का प्रवेश द्वार है और खोज-विज्ञापन के बाजार में यह विशालकाय है। शुरुआत में इंटरनेट पर उपलब्ध लगभग हर सेवा मुफ्त में ही मिलती थी, फिर धीरे-धीरे इंटरनेट पर उपलब्ध कई सेवाओं की खिड़कियां मुफ्त के लिए बंद होने लगीं, पर ज्यादातर ये मुफ्त सेवाएं विशेषीकृत सेवाओं की थी, जैसे नौकरी तलाशना या फिर अपने लिए जीवनसाथी की तलाश आदि पर गूगल की सेवाएं सब मुफ्त ही रहीं। इस बीच गूगल लगातार हमारे जीवन में घुसपैठ बढ़ाता रहा। सर्च इंजन से शुरू हुआ सफर ई-मेल फोटो वीडियो और न जाने कितनी सेवाओं को जोड़कर हमारे जीवन को आसान करता रहा। यदि उपभोक्ताओं को छूट और बहुत कुछ मुफ्त मिल रहा है तो उन्हें चिंता क्यों करनी चाहिए? इसको समझने के लिए जरूरी है कि वर्ष 2016 में भारत में एक फोन कंपनी ने 4जी सेवा शुरू की जिसमें उपभोक्ताओं को करीब एक वर्ष तक इंटरनेट और कॉलिंग की मुफ्त सेवाएं दी गईं।

परिणाम यह हुआ कि एक समय 15 से ज्यादा टेलीकॉम कंपनियां भारत में सेवाएं दे रही थीं, अब महज तीन बची हैं। अब तीनों कंपनियां अपनी दरें बढ़ा रही हैं। बाजार से प्रतिस्पर्धा काफी हद तक खत्म हो गई है। इंटरनेट के व्यवसाय का ढांचा भी बदल रहा है जो अब सिर्फ विज्ञापन आधारित न होकर सेवाओं के सब्सक्रिप्शन शुल्क के रूप में अपना विस्तार कर रहा है। इसी कड़ी में गूगल ने आगामी एक जून से अपनी गूगल फोटो मुफ्त क्लाउड स्टोरेज सिर्वस बंद करने का फैसला किया है। अब गूगल की ओर से गूगल फोटो के क्लाउड स्टोरेज के लिए शुल्क वसूला जाएगा। इसका यह मतलब हुआ कि अगर आप गूगल ड्राइव या फिर किसी अन्य जगह अपनी फोटो और डाटा को 15 जीबी से ज्यादा स्टोर करते हैं, तो इसके लिए आपको चार्ज देना होगा। जो उन्हें प्रतिमाह के हिसाब से 1.99 डॉलर (लगभग 144 रुपये) पड़ेगा। गूगल ने इसे 'गूगल वन' नाम दिया गया है। इस तरह का शुल्क जीमेल में पहले से ही लागू है जिसमें कोई भी जीमेल उपभोक्ता 15 पंद्रह जीबी तक का मेल स्टोरेज मुफ्त हासिल कर सकता है, इससे ज्यादा के लिए उसे शुल्क देना होगा। यानी भारत में इंटरनेट समय का एक चक्र पूरा कर चुका है और इस इंटरनेट पर कुछ कंपनियों का एकाधिकार है। बीच में चीन की कुछ कंपनियों ने भारत में पहले से स्थापित गूगल जैसी कंपनियों को चुनौती देने की शुरुआत जरूर की, पर राजनीतिक वजहों से उन कंपनियों को देश से बाहर जाना पड़ा।

दुनिया में दूसरे स्थान पर इंटरनेट उपभोक्ताओं वाला देश ऐसी कोई स्वदेशी कंपनी विकसित नहीं कर पाया, नतीजा गूगल जैसी कंपनियों का एकाधिकार हमारे जीवन का अंग बन चुका है। कंपनी मुनाफा बढ़ाने के लिए ऑनलाइन सर्च कारोबार में अपने प्रभुत्व का दुरुपयोग कर रही है। गूगल की मूल कंपनी अल्फाबेट इंक है और इसका बाजार मूल्य एक हजार अरब डॉलर से अधिक है। गूगल से टक्कर लेना इसलिए भी आसान नहीं है, क्योंकि उसने सर्च के मामले में एकाधिकार कायम कर रखा है। लगभग 92 प्रतिशत सर्च को गूगल नियंत्रित करता है, जो उसके सबसे बड़े प्रतिस्पर्धी माइक्रोसॉफ्ट बिंग की हिस्सेदारी महज ढाई प्रतिशत से बहुत ज्यादा है।

फिलहाल गूगल की आय का सबसे बड़ा स्रोत विज्ञापनों से होने वाली आय से आता है जो कि गूगल केवल उपभोक्ताओं को अपने सर्च इंजन पर ही नहीं, बल्कि यूट्यूब, जी मेल, क्रोम, एंड्रायड, मैप और अन्य सभी सेवाओं पर भी ट्रैक करते हैं। गूगल ट्रैकर्स वास्तव में 75 प्रतिशत शीर्ष वेबसाइटों पर लगे होते हैं। गूगल एनालिटिक्स को अधिकांश साइटों पर इंस्टॉल किया गया है, जिससे वेबसाइट मालिकों और गूगल को पता चलता है कि उपभोक्ता कौन सी साइट पर कब और कितने देर के लिए जाता है। जो विज्ञापन हर जगह आपका पीछा करते हैं, उनमें से अधिकांश वास्तव में इन गूगल विज्ञापन नेटवर्क के माध्यम से चलाए जाते हैं।अपनी सेवाओं के लिए शुल्क लेना या नहीं लेना किसी भी कंपनी का विशेषाधिकार है, पर यहां स्थिति थोड़ी अलग है। उपभोक्ताओं के पास ऐसा कोई सशक्त विकल्प है ही नहीं कि वो इंटरनेट की कुछ सेवाओं के लिए किसी अन्य कंपनी के बारे में विचार कर सके। ऐसे में जहां हम अपने ही आंकड़ों से कमाए गए मुनाफे से गूगल जैसी कंपनियों को विशाल बनाने में मदद करते हैं, जबकि उस मुनाफे का कोई भी हिस्सा उस उपभोक्ता तक नहीं पहुंचता जिसके कारण मुनाफा कमाया जा रहा है, वहीं मुनाफे को अधिकतम करने के लिए अब उन्हीं उपभोक्ताओं से शुल्क भी वसूला जा रहा है। मुनाफा कमाने की ये होड़ वास्तव में कहां जाकर रुकेगी इसका फैसला अभी होना बाकी है, परंतु यह सच है कि इंटरनेट का यह दावा कि वह हमारा समय बचा कर हमारे जीवन को आसान बनाता है, कहीं से भी सच नहीं प्रतीत होता, बल्कि यह उस बचे हुए समय को उसी इंटरनेट की अंधी सुरंगों में बिताने के लिए प्रेरित करता है।

इंसानी गरिमा का सवाल

मद्रास हाईकोर्ट ने सोमवार को LGBTIQA+ समुदायों के अधिकारों का सम्मान सुनिश्चित करने के पक्ष में बड़ा महत्वपूर्ण फैसला दिया। अदालत के सामने मामला एक लेस्बियन कपल की इस शिकायत के रूप में आया था कि परिवार वालों द्वारा लापता बताए जाने के बाद उसे पुलिस प्रताड़ना झेलनी पड़ रही है। कोर्ट ने उस कपल को तो राहत दी ही, इस अवसर का इस्तेमाल करते हुए ऐसे तमाम मौकों को रेखांकित करने की कोशिश की, जहां LGBTIQA+ (यानी लेस्बियन, गे, बाइसेक्शुअल, ट्रांसजेंडर, क्वीर, इंटरसेक्स, ए-सेक्शुअल प्लस) समुदायों के सदस्यों को लांछन, उपेक्षा और भेदभाव का शिकार होना पड़ता है। यौन स्वायत्तता को निजता के अधिकार का अहम हिस्सा बताते हुए कोर्ट ने ऐसे सभी जरूरी इंतजाम करने को कहा, जिससे इन समुदायों के लोगों के साथ होने वाला गैरकानूनी भेदभाव खत्म हो। फैसले का वह हिस्सा खास तौर पर ध्यान देने लायक है, जिसमें जस्टिस आनंद वेंकटेश कहते हैं कि मुझे यह स्वीकार करने में कोई हिचक नहीं कि मैं भी उन सामान्य लोगों के बहुमत का हिस्सा हूं, जो होमोसेक्शुअलिटी को अभी पूरी तरह समझ नहीं पाए हैं। लेकिन इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि अज्ञानता भेदभाव के किसी रूप को औचित्य प्रदान करने का आधार नहीं हो सकती।

आश्चर्य नहीं कि यह फैसला न्यायिक, पुलिस और जेल अधिकारियों को प्रशिक्षण के जरिए इन समुदायों के अधिकारों के प्रति जागरूक बनाने की जरूरत बताता है। इसके अलावा स्कूलों में पैरंट टीचर्स असोसिएशन जैसे मंचों के सहारे अभिभावकों में जागरूकता लाने और स्कूलों में जेंडर न्यूट्रल रेस्टरूम उपलब्ध कराने और फॉर्मों में मेल, फीमेल के साथ ट्रांसजेंडर का विकल्प जोड़ने जैसे सुझाव भी काफी महत्वपूर्ण हैं। फैसले का एक अहम हिस्सा उन लोगों से संबंधित है, जो [illegible]+ समुदायों के लोगों के यौन व्यवहार को एक बीमारी बताते हैं और उसका तरह-तरह से इलाज करने का दावा करते हैं। इनमें अस्पतालों, स्वास्थ्य केंद्रों से जुड़े चिकित्साकर्मी ही नहीं धार्मिक संस्थानों से जुड़े गुरु भी शामिल हैं। कोर्ट ने ऐसे तमाम प्रयासों को निषिद्ध घोषित कर दिया है। हालांकि अपने देश में सुप्रीम कोर्ट 2018 में ही कह चुका है कि दो वयस्कों के बीच स्वैच्छिक समलैंगिक संबंध अपराध नहीं है। इसके बावजूद समाज में प्रचलित पूर्वाग्रहों का प्रभाव इतना व्यापक है कि सरकार भी समलैंगिक शादी को मान्यता देने में हिचकती है क्योंकि उसके मुताबिक यह भारतीय परिवार की अवधारणा के अनुरूप नहीं है। ऐसे में आसानी से समझा जा सकता है कि LGBT+ समुदायों को समाज में इंसानी गरिमा के साथ जीने का अधिकार दिलाने के लिए अभी कितना लंबा सफर तय करना है। बावजूद इसके, इसमें कोई शक नहीं कि मद्रास हाईकोर्ट का यह फैसला इस लंबी यात्रा में मील के एक अहम स्तंभ के रूप में दर्ज हुआ है।

कोरोना महामारी के बीच मोदी सरकार के चुनौतियों और उपलब्धियों से भरे सात साल

लेकिन तभी मार्च के आखिर में इसकी दूसरी लहर ने पांव पसारने शुरू कर दिए। हालांकि कोरोना की दूसरी लहर अधिक खतरनाक साबित हुई है, लेकिन इस कठिन परिस्थिति में राज्यों को आक्सीजन की उपलब्धता के अलावा अन्य सहायता मुहैया कराने के लिए केंद्र सरकार हमेशा तैयार दिखी। पीएम केयर्स फंड से 200 करोड़ रुपये से अधिक की रकम राज्यों को आक्सीजन प्लांट लगाने के लिए समय रहते केंद्र सरकार द्वारा दे दी गई थी, लेकिन अधिकांश राज्यों की तरफ से इसको लेकर समय रहते उत्साह कम दिखाया गया।

वर्ष 2014 में पहली बार जब भाजपा सत्ता में आई तब देश के सामने कई चुनौतियां थीं। आज उन चुनौतियों से देश को उबारने में मोदी सरकार कितना कामयाब हो पाई है, इस पर चर्चा जरूरी है। वर्ष 2014 में पहली बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने के बाद नरेंद्र मोदी ने कहा था, 'मेरी सरकार गरीब कल्याण को समिर्पत है।' ऐसा कहना कल्याणकारी राज्य की अवधारणा पर आगे बढ़ने का संकेत था। सवाल था 'गरीब कल्याण' की भावना को मोदी अमल में कैसे लाएंगे। यह सवाल इसलिए भी था कि गरीब कल्याण के वादों का बुरा हश्र देश ने दशकों तक देखा है। निश्चित ही पुराने घिसे-पिटे ढर्रे पर चलने की बजाय नीतिगत बदलावों तथा नवाचारों को अपनाने की जरूरत थी।

गरीब कल्याण की राह में सबसे बड़ा रोड़ा था गरीब का हक सीधे गरीब तक नहीं पहुंच पाना। दशकों तक देश ने ऐसा कोई पारदर्शी तंत्र नहीं विकसित किया जिसके माध्यम से गरीब का हक सीधे गरीब को पहुंचाया जा सके। देश के करोड़ों गरीब परिवार ऐसे थे जो मुख्यधारा के अर्थतंत्र से बाहर थे। उनका बैंक खाता न होने की वजह से कोई भी आर्थिक लाभ सीधा लाभार्थी को दे पाना संभव नहीं था। आज देश के 42 करोड़ से अधिक लोग बैंकों से जुड़े चुके हैं। गरीबों के आर्थिक उत्थान में इसका बड़ा लाभ हुआ कि 54 मंत्रालयों की 319 योजनाओं का आर्थिक लाभांश बिना किसी बिचौलिये के सीधे गरीबों के खाते में पहुंच रहा है। कोरोना काल में आम जनता को त्वरित आर्थिक सहायता में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर का तंत्र रामबाण साबित हुआ है।

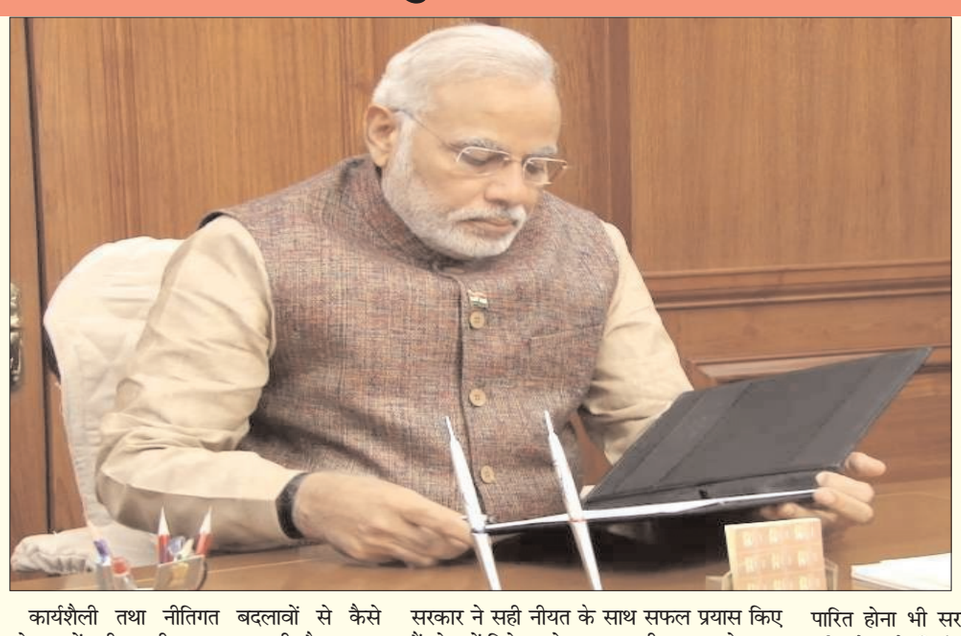

कार्यशैली तथा नीतिगत बदलावों से कैसे योजनाओं की तस्वीर बदल सकती है जनधन योजना इसका एक उदाहरण है। कोई सरकार गरीब कल्याण की भावना रखे इतना पर्याप्त नहीं होता, उसे अमल में लाने के लिए सही नीति, सटीक निर्णय और सशक्त नेतृत्व मायने रखता है। भाजपा सरकार आने के बाद यह बदलाव देश ने महसूस किया है। अपने पहले पांच साल के कार्यकाल में जनहित के साथ-साथ अिर्थक सुधारों तथा कानूनी जटिलताओं से ईज ऑफ डूइंग तक के लिए मोदी सरकार ने सही नीयत के साथ सफल प्रयास किए हैं। देश में निवेश बढ़े, उत्पादन की क्षमता बढ़े, स्व-रोजगार को बढ़ावा मिले, आधारभूत संरचना के विकास में गति आए तथा भारत की साख दुनिया में मजबूत हो, इन सबको लेकर मोदी सरकार ने चौतरफा कार्य किए।

किसी भी सरकार के कामकाज का संपूर्ण मूल्यांकन उसकी वैचारिक प्रतिबद्धता तथा घोषणापत्र में किए वादों की अनदेखी करके नहीं की जा सकती है। वर्ष 2019 में सरकार बनने के बाद हुए संसद के पहले ही सत्र में सरकार ने जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद-370 को समाप्त करने का ऐतिहासिक निर्णय लिया। राज्य को दो भागों जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में बांटकर केंद्रशासित प्रदेश का दर्जा देते हुए इस ऐतिहासिक समस्या का समाधान किया गया। पिछले कार्यकाल से राज्यसभा में अटके हुए तीन तलाक के विरुद्ध कानून पारित कराने में भी सरकार सफल रही। उसी वर्ष नवंबर में श्रीरामजन्मभूमि पर सर्वोच्च न्यायालय का ऐतिहासिक निर्णय आया। इसी क्रम में संसद के शीतकालीन सत्र में नागरिकता संशोधन कानून पारित होना भी सरकार की एक बड़ी उपलब्धि रही। ये सारे निर्णय दशकों से लंबित थे। मोदी सरकार अपनी विचारधारा और अपने घोषणापत्र के मुताबिक इसे पूरा करने में सफल रही। यह सब करते हुए सरकार को शायद अंदाजा भी नहीं रहा हो कि आने वाले समय में उसका सामना एक बड़ी चुनौती से होने जा रहा है।

पूरी दुनिया के साथ ही कोरोना संक्रमण ने वर्ष 2020 के आरंभिक दौर में ही भारत में भी दस्तक दी। धीरे-धीरे यह संक्रमण पूरे देश में फैलने लगा था। सरकार और जनता दोनों के लिए यह संकट एकदम नया और अबूझ पहेली की तरह था। मोदी सरकार संपूर्ण लॉकडाउन के विकल्प पर आगे बढ़ी। यह एक साहसिक फैसला था। इस फैसले के बाद श्रमिकों का पलायन सरकार के समक्ष बड़ी समस्या के रूप में आया, लेकिन सरकार ने पूरी योजना के साथ लोगों की परेशानियों को कम करने के लिए अनेक मोर्चों पर काम किया। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में देश हर मोर्चे पर मुस्तैद दिखा। स्थिति को संभालने के साथ-साथ देश ने अपने स्तर पर दो-दो वैक्सीन का परीक्षण पूरा करने के बाद टीकाकरण अभियान भी शुरू कर दिया। एक समय ऐसा लगने लगा कि देश इस महामारी से जल्द ही पूरी तरह से पार पा लेगा। लेकिन तभी मार्च के आखिर में इसकी दूसरी लहर ने पांव पसारने शुरू कर दिए। हालांकि कोरोना की दूसरी लहर अधिक खतरनाक साबित हुई है, लेकिन इस कठिन परिस्थिति में राज्यों को आक्सीजन की उपलब्धता के अलावा अन्य सहायता मुहैया कराने के लिए केंद्र सरकार हमेशा तैयार दिखी। पीएम केयर्स फंड से 200 करोड़ रुपये से अधिक की रकम राज्यों को आक्सीजन प्लांट लगाने के लिए समय रहते केंद्र सरकार द्वारा दे दी गई थी, लेकिन अधिकांश राज्यों की तरफ से इसको लेकर समय रहते उत्साह कम दिखाया गया। राज्यों की उदासीनता और समय रहते तैयारी में कमी भी दूसरी लहर की विभीषिका का एक कारण है। कोरोना की इस दूसरी लहर से भी निपटने के लिए सरकार युद्धस्तर पर प्रयासरत है और दिन-प्रतिदिन स्थिति में सुधार देखने को मिल रहा है।

गौरवशाली भारत के स्वामी प्रकाशक एवं मुद्रक प्रवीण कुमार सिंह द्वारा आला प्रिंटिंग प्रेस 3636 कटारा दिना बेग लाल कुआं, दिल्ली.... से मुद्रित एवं, ब्लॉक नं. 23 मकान नं. 399 त्रिलोकपुरी दिल्ली....91 से प्रकाशित संपादक -प्रवीण कुमार सिंह टेलीफोन नं. 011.22786172 फैक्स नं. 011.22786172
RNI, No. DELHIN383334, E-mail: gauravashalibarat@gmail.com इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के पीआरबी एट के तहत

संक्षिप्त खबर

इंदौर : बेटे ने बुजुर्ग पिता को पीट-पीटकर मार डाला

इंदौर। बुजुर्ग पिता भूरालाल अलावा निवासी श्रीराम नगर द्वारकापुरी की रविवार देर रात उसके बेटे सचिन से बेरहमी से पीट-पीट कर हत्या कर दी। सोमवार सुबह सचिन एक वाहन में पिता का शव लेकर अंतिम संस्कार करने जा रहा था। पड़ोसियों ने पूछा तो उसने बताया कि वे कई दिनों से बीमार थे। जिस कारण उनकी मौत हो गई। यह सुनते ही लोगों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पीएम करने भिजवाया। द्वारकापुरी टीआई सतीश कुमार द्विवेदी ने बताया पहले मामला संदिग्ध लगा था। सचिन से जब कहा कि सच्चाई सामने आ जाएगी तो उसने स्वीकार किया कि मैंने ही पिता से मारपीट की थी उसके बाद वह गिर गए तब मैंने सोचा कि वे बेहोश हो गए हैं। कुछ देर बाद चैक किया तो उनकी सांसें थम गई थीं।

सागर : जन्मोत्सव पर बधाई लेने गए किन्नर से मारपीट

सागर। शाहगढ़ में रविवार की देर रात बरायठा रोड स्थित वार्ड 2 में बधाई लेने पहुंचे किन्नर बिजली पिता चन्दर गौंड़ के साथ मारपीट की गई है। इस मारपीट की सूचना घायल किन्नर ने पुलिस को दी। घायल किन्नर का सामुदायिक स्वास्थ्य इलाज के लिए पहुंचाया गया। पुलिस के अनुसार नगर के भगतसिंह वार्ड 2 कुचबंदिया गौंड़ जाति परिवार के घर बेटी का जन्म हुआ था। ईदगाह मस्जिद वार्ड एक के किन्नर बिजली बेटी होने की बधाई लेने पहुंचे थे। जिसमे गढ़ाकोटा के बालाजी मंदिर निवासी कुचबंदिया परिवार के लोगों ने मारपीट कर दी। किन्नर की शिकायत पर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। वहीं मारपीट करने वाले मौके से भाग निकले पुलिस जिनकी तलाश में जुटी है।

बड़वानी : एसडीएम ने दबिश देकर 300 ट्रॉली रेत की जब्त

बड़वानी। बड़वानी जिला के समीप भीलखेड़ा बसाहट में सोमवार की शाम संयुक्त दल द्वारा दबिश देकर अवैध रूप से संग्रहित 300 ट्रॉली रेत जब्त की गई। जानकारी के अनुसार एसडीएम बड़वानी घनश्याम धनगर एवं डिप्टी कलेक्टर अंशु जावला ने बताया कि शिकायत मिलने पर मिली सूचना के आधार पर भील खेड़ा बसाहट में राजेंद्र पटेल के परिसर से 125 से अधिक ट्रॉली रेत जब्त की गई है। इसके अलावा वहां अन्य स्थानों पर भी रेत का अवैध संग्रहण पाया गया। मौके पर मौजूद अधिकारी ने बताया कि इस कार्यवाही के दौरान जब्त की गई रेत को कलेक्टर परिसर में संग्रहित कराया जा रहा है। जहां पर खनिज विभाग के माध्यम से नीलामी कर प्राप्त आय को शासकीय खजाने में जमा कराया जाएगा।

मुरैना : रेंजर की शिकायत पर सौ ग्रामीणों पर केस दर्ज

मुरैना। जिले की नगरा पुलिस ने एक ग्रामीण महावीर तोमर की गोली लगने से हुई मौत के मामले में वनकर्मियों पर हत्या का मामला दर्ज किया। इसके बाद मुरैना कोतवाली पुलिस ने भी वन रेंजर के एक आवेदन पर सैकड़ा अज्ञात ग्रामीणों के खिलाफ वनकर्मियों पर फायरिंग करने और सर्विस राइफलें लूटने आदि की धाराओं में मामला दर्ज किया है। पुलिस के अनुसार रविवार की देर रात दीपंकन सिंह गेम रेंजर चंबल अभयारण्य अम्बाह और भिंड क्षेत्र ने मुरैना पुलिस कोतवाली में एक आवेदन दिया जिसमें कहा है कि रविवार की सुबह वन कर्मियों की एक टीम अवैध रेत से भरे एक ट्रैक्टर ट्राली का पकड़ने पीछा करने पर अमोलपुरा के करीब सैकड़ा ग्रामीणों ने लाठियों से हमला किया और सर्विस राइफलों को लूटने की कोशिश की।

खरगोन: मवेशियों का अवैध परिवहन करते पांच गिरफ्तार

खरगोन। बलकवाड़ा थाना क्षेत्र में दो मिनी ट्रकों के माध्यम से मवेशियों का अवैध परिवहन करने के आरोप में पांच लोगों को गिरफ्तार किया गया है। बलकवाड़ा के थाना प्रभारी वरुण तिवारी के मुताबिक मुखबिर की सूचना पर चेकिंग के दौरान आगरा मुंबई राष्ट्रीय राजमार्ग पर खुरमपुरा में पीछा कर दो मिनी ट्रकों को रोका गया। वाहनों की तलाशी लेने पर 28 मवेशी अवैध परिवहन करते पाए गए। उन्होंने बताया कि मौके से राजस्थान के भीलवाड़ा जिले के आबिद मुबारक हुसैन व शाहरुख मोहम्मद, तथा राजस्थान के अजमेर क्षेत्र के दीपक राठौर और मुरली दाहिमा और बीकानेर जिले के नरसिंह रेगर को गिरफ्तार किया गया। दोनों ट्रकों से मवेशियों को महाराष्ट्र की ओर ले जाया जा रहा था।

महासमुंद : कटहल भरे ट्रक से दो करोड़ का गांजा जब्त

महासमुंद। जिले में गांजा तस्करों के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। कोमाखान पुलिस ने एक ट्रक से 11 क्विंटल गांजा बरामद किया है। कीमत 2 करोड़ 20 लाख रुपए है। गांजे की तस्करी करते दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक ट्रक में कटहल की आड़ में गांजा छुपाकर ओडिशा से उप्र ले जाया जा रहा था। उससे पहले ही पुलिस ने टेमरी नाका के पास आरोपियों को धर दबोचा। गिरफ्तार किए गए आरोपी देवेन्द्र सिंह (30 वर्ष) और गुड्डू (25 वर्ष) उत्तरप्रदेश के अलीगढ़ के रहने वाले हैं। पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ 20 बी एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है।

नर्मदा नदी में फंसी दो दर्जन यात्रियों से भरी नाव

महिला टीआई की सजगता से बाल-बाल बचे 30 लोग, ठेकेदार और नाविक पर केस दर्ज

सिवनीमालवा (एजेंसी)।

सोमवार को दोपहर में नर्मदा नदी के बाबरी घाट पर यात्रियों से भरी नाव अनियंत्रित होकर बीच नर्मदा नदी में फंस गई। नाव के बीच नर्मदा नदी में फंसते ही यात्री घबरा कर मदद के लिए चिल्लाने लगे। यात्री मदद के लिए अपने परिचितों के साथ साथ 100 डॉयल पर भी फोन लगाते रहे। जिसकी सूचना मिलते ही शिवपुर थाना प्रभारी मोनिका सिंह दलबल के साथ मौके पहुंचीं और छोटी नाव से सभी यात्रियों को सुरक्षित निकाल घाट पर लाई।

वही सिवनी मालवा से भी एसडीएम अखिल राठौर, तहसीलदार प्रमेश जैन एवं नायब तहसीलदार नीलेश पटेल मौके पर दल बल के साथ पहुँचे और ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए उन सभी नावों को जब्त कर उनके इंजन शिवपुर थाने भिजवा दिए, जिनमें सुरक्षा उपकरण नहीं थे।

शिवपुर थाना प्रभारी मोनिका सिंह ने बताया कि हमें सूचना मिली थी कि बीच नर्मदा नदी में सवारी नाव फंस गई है जिसके बाद हम मौके पर पहुँचे और छोटी नाव से लगभग 25 से 30 लोगों को सुरक्षित घाट पर लाए। वहीं नाव वहां से अभी नहीं निकल पाई है। नाव ठेकेदार भीमसिंह के खिलाफ लापरवाही पूर्वक नाव संचालन के चलते शिवपुर थाने में मामला दर्ज किया जा रहा है।

12 की क्षमता वाली नाव पर बैठे थे 30 लोग

सोमवार को नाव ठेकेदार ने 12 लोगों की क्षमता वाली नाव में 30 लोगों को बैठा लिया। इसके बाद नदी के दूसरे किनारे ले जाने लगा। बीच मझधार में नाव जाकर फंस गई। इसके बाद नाव में बैठे लोग घबरा गए। इस कारण लोगों की चीख पुकार मच गई।सिवनी मालवा तहसील के अंतर्गत आने वाले आठो नाव घाट पर संचालित हो रही नाव में न तो यात्रियों के लिए सुरक्षा उपकरण है न ही किराए की रसीद या टिकिट दी जाती है। जिसकी भी जांच की जाना बहुत जरुरी है।

इनका कहना है...

बाबरी घाट पर पानी बढ़ने से नर्मदा नदी में करीब दो दर्जन सवारीयों से भरी नाव फंस गई थी। सूचना मिलने पर तुरंत पहुंचकर सभी को दूसरी नाव से घाट पर सुरक्षित लाया गया। लापरवाही की वजह से नाव संचालक पर एफआईआर की जावेगी।

मोनिका सिंह, थाना प्रभारी शिवपुर

10 घंटे तक बिना रुके ऑपरेशन कर दीपक को दी नई जिंदगी

रीवा के सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में ब्रेन ट्यूमर का सफल ऑपरेशन

रीवा, (एजेंसी)। रीवा के सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में सोमवार को डॉक्टरों ने ब्रेन ट्यूमर का सफल ऑपरेशन कर मरीज की जान बचा ली। 22 वर्षीय दीपक सिंह पिछले कई दिनों से अस्पताल में भर्ती था, लेकिन उसकी हालत में सुधार नहीं हो रहा था। डॉक्टरों की टीम ने 10 घंटे तक लगातार चले ऑपरेशन के बाद उसे नई जिंदगी दे दी।

ब्रेन ट्यूमर के मरीज 22 वर्षीय सिंह का पहले भी एक ऑपरेशन किया गया था, लेकिन उसके मस्तिष्क के दाहिने हिस्से में दोबारा ट्यूमर बन गया था। अस्पताल में भर्ती किए जाने के बाद भी उसकी हालत लगातार खराब हो रही थी। इसके बाद उसकी दोबारा सर्जरी का फैसला डॉक्टरों ने किया। न्यूरो सर्जन डॉ दिनेश पटेल के नेतृत्व में टीम ने लगातार 10 घंटे तक उसका ऑपरेशन किया और अब मरीज की हालत पहले से बेहतर है। दीपक सिंह ऑपरेशन के बाद पूरी तरह स्वस्थ है। वह लोगों से बात कर रहा है और चलने-फिरने के साथ भोजन भी कर रहा है। डॉ. दिनेश पटेल का कहना है कि सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में पहले न्यूरो सर्जन नही थे जिसकी वजह से लोग अपना इलाज कराने के लिए नागपुर या फिर अन्य प्रदेशों में जाते थे। अब अस्पताल में न्यूरो सर्जन डॉक्टरों के आने से लोगों का समय और पैसा दोनों की बचत होती है।

सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस डॉ. डीवॉय चंद्रचूड ने तीन डिजिटल योजना का किया शुभारंभ

मप्र हाईकोर्ट समेत जिला न्यायालय हुए हाईटेक

जबलपुर (एजेंसी)।

सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस डॉ. डीवाय चंद्रचूड़ ने मप्र हाईकोर्ट के लिए सेक्योर वाय-फाय प्रोजेक्ट का वर्चुअल शुभारंभ किया।

न्याय प्रणाली को हाईटैक करने के लिए तीन नई योजनाओं की शुरूआत मध्यप्रदेश में की गई है। इन योजनाओं को डिजिटल शुभारंभ सर्वोच्च न्यायालय की ई-कमेटी के अध्यक्ष जस्टिस डॉ डीवाय चंद्रचूड द्वारा किया गया। इस अवसर पर मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस मोह. रफीक, जस्टिस अतुल श्रीधरन तथा जस्टिस रोहित आर्या उपस्थित थे।

इस अवसर पर मध्यप्रदेश ई-कोर्ट समिति के अध्यक्ष जस्टिस रोहित आर्या ने कहा कि वर्तमान वर्ग कम्युनिकेशन का युग है। त्वरित न्याय के लिए सूचना का त्वरित आदान प्रदान किया जाना बहुत आवश्यक है। इस क्रम में इन तीन डिजिटल योजना का शुभारंभ किया जा रहा है। इस योजना के लिए उन्होंने प्रदेश सरकार के विधि सचिव सहित संबंधित विभाग के सहयोग की प्रशंसा की। इस अवसर पर मध्य उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिश मोह. रफीक ने कहा कि यह तीनों योजनाएं हाईकोर्ट में न्यायधीशों के साथ जिला न्यायालय के न्यायधीश तथा पक्षकारों के लिए लाभकारी होगीं। मध्यप्रदेश की जबलपुर स्थित मुख्यपीठ सहित इंदौर और ग्वालियर बेंच सहित 72 न्यायालयों में वाय-फाई परियोजना की शुरूआत की जा रही है। इसके अलावा जमीन तथा प्रॉपर्टी की जानकारी के लिए सीआईएस सॉफ्टवेयर तथा प्रकरण की निगरानी के लिए एनएसटीरईपी आवेदन की शुरूआत की गई है।

सीआईएस सॉफ्टवेयर उपलब्ध करवा देगा भूमि अभिलेखों का रिकॉर्ड

इस संबंध पर सर्वोच्च न्यायालय की ई-कमेटी के अध्यक्ष जस्टिस डॉ. डीवाय चंद्रचूड ने ई-सेवा का उपयोग मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा किये जाने की सराहना की। उन्होंने कहा कि न्यायालय में लगभग दस लाख प्रकरणों में 9 लाख से अधिक प्रकरणों में सुनवाई किस कारण बढ़ी, इसकी जानकारी प्रदान की गई है। इस अलावा महामारी काल में मध्यप्रदेश में लगभग चार लाख प्रकरणों को निराकरण किया गया। सीआईएस सॉफ्टवेयर से भूमि अभिलेखों का रिकॉर्ड उपलब्ध करवा देगा, जो प्रकरणों की सुनवाई में अहम होता है। आभार प्रदर्शन मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय में ई-कमेटी के सदस्य जस्टिस अतुल श्रीधरन ने किया।

कोरोना संक्रमित वकीलों को 10.30 लाख की सहायता स्वीकृत

जबलपुर। कोरोना संक्रमण काल में मप्र राज्य अधिवक्ता परिषद ने चिकित्सा सहायता योजना 2021 के तहत 42 अधिवक्ताओं के आवेदनों को स्वीकार करते हुए 10 लाख 30 हजार रुपये की सहायता राशि स्वीकृत की है। उक्त निर्णय मप्र राज्य अधिवक्ता परिषद वित्त समिति ने लिया है। जिसमें संक्रमित अधिवक्ताओं को 25 हजार रुपये के हिसाब से सहायता राशि स्वीकृत की गई जो कि सीधे ई-पेमेन्ट के माध्यम से आवेदकों के खातें में पहुंचेगी।

जमीनी विवाद में मां-बेटे की बोलेरो से कुचलकर हत्या, परिजनों ने लगाया जाम

टीकमगढ़ के कुड़ीला थाना में घटना छावनी में तब्दील हुआ खरगापुर नगर

टीकमगढ़/खरगापुर, (एजेंसी)। जिले के कुड़ीला थाना अंतर्गत ग्राम मातौल में बोलोरोवाहन की टक्कर से मां-बेटे की मौत हो गई। स्वजनों ने आरोप लगाया कि युवक की बोलेरो वाहन से कुचलकर रंजिशन हत्या की गई है। वहीं स्वजनों सहित ग्रामीणों ने आक्रोशित होकर खरगापुर पहुंचकर सोमवार की दोपहर जाम लगा दिया। वहीं सूचना मिलते ही खरगापुर, बल्देवगढ़, जतारा और कुडीला की पुलिस मौके पर पहुंच गई। इस दौरान नगर छावनी में तब्दील हो गया।

घटना के संबंध में मिली जानकारी के मुताबिक हरदयाल कुशवाहा पुत्र कमला कुशवाहा, अपनी मां श्यामबाई के साथ अपनी बाइक से सोमवार की सुबह करीब 9 बजे जब जा रहा था। तभी पीछे से बोलेरो वाहन से आ रहे मातौल निवासी घंसू कुशवाहा की टक्कर बाइक से हो गई। यह घटना इतनी अधिक भयाभह भी कि घटना स्थल पर ही मां बेटे की मौत हो गई। अचानक हुई घटना के चलते आसपास के लोग भी काफी संख्या में पहुंच गए। वहीं जानकारी मिलने पर मृतक के स्वजन भी घटना स्थल पर पहुंच गए। जहां मृतकों के स्वजनों ने आरोप लगाते हुए कहा कि घंसू कुशवाहा से उसकी जमीन विवाद में पुरानी रंजिश चल रही थी जिसके चलते ही यह घटना हुई है।

बोखलाए परिजन तथा ग्रामीणों ने खरगापुर चौराहे पर जाम लगा दिया, जिसके चलते वाहनों की दोनों और लंबी-लंबी लाइनें लग गईं। मृतकों के स्वजनों ने आरोप लगाते हुए कहा कि पहले तो बोलेरो वाहन चालक ने बाइक सवार को टक्कर मारी, जिससे वह नीचे गिर गए और उसके वाद वाहन का रिवर्स गियर डालकर तेज गति से मां-बेटे को कुचल दिया, जिसके चलते दोनो की मौत हो गई। पुलिस ने वाहन चालक के खिलाफ धारा 302 भादवि के तहत मामला पंजीबद्व किया।

कोरोना गाइडलाइन को ताक में रख ली जा रही थी प्रवेश परीक्षा, निजी स्कूल को नोटिस

बुरहानपुर,(आरएनएन)। लालबाग स्थित नेहरू माटेसरी स्कूल में सोमवार को कक्षा पहली से नवमीं तक के विद्यार्थियों की प्रवेश परीक्षा ली जा रही थी। विद्यार्थियों को कमरों में बैठाया गया। शिकायत मिलने पर जिला शिक्षा अधिकारी स्कूल पहुंचे और स्कूल प्रबंधन को कारण बताओ नोटिस जारी किया है।

जिला शिक्षा अधिकारी रविन्द्र महाजन ने बताया सूचना के आधार पर सोमवार सुबह 11.30 बजे नेहरू माटेसरी स्कूल का आकस्मिक निरीक्षण किया गया है। निरीक्षण के दौरान पाया गया कि स्कूल प्रबंधन द्वारा स्कूल में कक्षा नर्सरी से नौवीं तक प्रवेश के लिए छात्रों से प्रवेश परीक्षा ली जा रही है। कोरोना काल में स्कूल प्रबंधन द्वारा स्कूल में छात्रों को एकत्रित कर प्रवेश के लिये परीक्षा लिये जाने वाला कृत्य कोविड गाइड लाइन के प्रतिकूल होकर शासन के निर्देशों की अवहेलना की श्रेणी में आता है। डीईओ ने बताया स्कूल को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। स्कूल प्रबंधन से सात दिन जवाब मिलने के बाद आगे की कार्रवाई होगी।

नौकरी से हटाने पर दो युवकों ने साथियों के साथ दफ्तर में मैनेजर को पीटा

ग्वालियर। लापरवाही पर नौकरी से निकाले जाने से नाराज नीरज राणा और आदित्य राणा दोनों कोरियर बॉय अपने 10 -12 साथियों के साथ रविवार रात 8 बजे के करीब एमएच चौराहा पर पृथ्वीराज मार्ग पर स्थित कोरियर सर्विस कंपनी डेल्हीवरी के दफ्तर में पहुंचकर हंगामा खड़ा कर दिया। युवकों ने कंपनी के मैनेजर अनूप राजावत और सुपरवाइजर मुरारी कुशवाह को पीटा। इसके बाद वहां रखी गाड़ियों में तोड़फोड़ की और सड़क पर गोलियां चलाईं। बता दें कि गोलीबारी से क्षेत्र में दहशत है। फायरिंग और मारपीट का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने मामला दर्ज किया है। हमलावरों की तलाश की जा रही है। जानकारी के अनुसार उपनगर मुरार के एमएच चौराहा के पृथ्वीराज मार्ग पर कोरियर कंपनी डेल्हीवरी का दफ्तर है। यहां मुरार के नीरज और आदित्य काम करते हैं। दो दिन पहले एक पार्सल को नहीं पहुंचाने की लापरवाही पर इन दोनों को मैनेजर ने नौकरी से हटा दिया था। लापरवाही की शिकायत सुपरवाइजर ने की थी। उस समय भी नीरज और आदित्य ने काफी बहस की थी। यहां इन दोनों को छोड़कर सभी लड़कों ने अपने चेहरे ढके हुए थे। यह अंदर पहुंचे और मैनेजर को हाथ से पकड़कर सीट से उठाया और मारपीट शुरू कर दी। मैनेजर ने डर के चलते शटर डाल दिया। काफी देर बाद जब बाहर से कोई आवाज नहीं आई तो मैनेजर ने शटर उठाया और बाहर निकलकर पुलिस को सूचना दी।

सीसीटीवी में रिकॉर्ड पूरी घटना

पूरी घटना कोरियर सर्विस कंपनी के सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुई है। युवक मारपीट करते और हंगामा मचाते नजर आ रहे हैं। टीआई मुरार थाना अजय पवार का कहना है कि नीरज राणा व आदित्य राणा सहित अन्य पर मामला दर्ज किया है।

पुरानी पेंशन की मांग को लेकर 2700 शिक्षाकर्मी पहुंचे हाईकोर्ट

राज्य सरकार समेत अन्य को नोटिस

जबलपुर। राज्य सरकार से सालों से पुरानी पेशन की मांग कर रहे प्रदेश के करीब 2700 से अधिक शिक्षा कर्मियों ने हाईकोर्ट की शरण ली है। जिसमें कहा है कि पेंशन व पे-स्केल पर सरकार उनके साथ भेदभाव कर रहीं है। इसके लिए अलग-अलग समय पर उनके पदनाम बदले जाते हैं।

चीफ जस्टिस मोह.रफीक एवं जस्टिस विजय कुमार शुक्ला की युगलपीठ ने सोमवार को हुई मामले की सुनवाई पश्चात राज्य सरकार सहित अन्य को नोटिस जारी करते हुए जवाब पेश करने के निर्देश दिए हैं। अगली सुनवाई जुलाई माह के पहले सप्ताह में निर्धारित की है। आवेदकों का कहना है कि वर्ष 1998 में हुई भर्ती से राज्य सरकार अलग-अलग समय पर उनके पदनाम बदलती आ रहीं है। भर्ती के बाद वर्ष 2000 के बाद उन्हें नियमित किया गया। अध्यापक नाम दिया और उसके बाद शिक्षक, लेकिन उन्हें पुरानी पेंशन नहीं दी है।

मामले में प्रमुख सचिव विधि एवं विधायी विभाग, प्रमुख सचिव स्कूल शिक्षा विभाग, उप सचिव स्कूल शिक्षा विभाग, आयुक्त लोक शिक्षण संचनालय सहित जबलपुर, छिंदवाड़ा, रायसेन, सिवनी, छतरपुर व बालाघाट के जिला कलेक्टर एवं डीईओ को पक्षकार बनाया है। सोमवार को सुनवाई पश्चात् कोर्ट ने अनावेदकों को नोटिस जारी कर जवाब पेश करने के निर्देश दिए है। याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता विवेक कृष्ण तन्खा, अधिवक्ता वरुण तन्खा व अधिवक्ता राहुल गुप्ता ने पैरवी की।

ब्लैक, व्हाइट, यलो के बाद अब ग्रीन फंगस का संक्रमण मिला

इंदौर। ब्लैक के बाद व्हाइट और यलो फंगस के केस भी सामने आए थे। अब ग्रीन (एसपरजिलस) फंगस से पीड़ित का मामला भी सामने आए है। मरीज की हालत गंभीर होने पर सोमवार को मरीज को एयरलिफ्ट करचार्टड प्लेन से मुंबई स्थित हिन्दुजा अस्पताल भेजा गया है।

मरीज की हालत गंभीर, एयरलिफ्ट कर भेजा मुंबई

इंदौर के माणिकबाग रोड क्षेत्र में रहने वाले 34 वर्षीय विशाल श्रीधर को कोविड संक्रमण से ठीक होने के करीब डेढ़ माह बाद ग्रीन फंगस हो गया था। उनके फेफड़ों व साइनस में एसपरजिलस फंगस मिला। चिकित्सकों के मुताबिक यह ब्लैक फंगस से भी ज्यादा खतरनाक है। उसके फेफड़ों में 90 फीसद संक्रमण होने के कारण सोमवार को उन्हें एयरलिफ्ट कर विशेष चार्टड विमान से दोपहर 3.30 बजे इंदौर से मुंबई के हिंदुजा अस्पताल में भेजा गया। अरबिंदो अस्पताल के चेस्ट रोग विशेषज्ञ डा. रवि डोसी के मुताबिक यह मरीज पोस्ट कोविड था। उसके फेफड़ों व साइनस में एसरपरजिलस फंगस मिलने के बाद उसका अलग ट्रीटमेंट किया गया। उसे वेरिकोनोजोल इंजेक्शन दिया गया। युवक के दांए फेफड़ों में पस भर गया था जिसे अस्पताल में निकाला गया। इसके डेढ़ माह बाद मरीज को खंखार व गुदा द्वार से रक्त आने लगा। उस समय उसे बुखार भी 103 डिग्री से कम नहीं हो रहा था। शुरुआत में इलाज के दौरान म्युकर मायकोसिस की संभावना जताई जा रही थी इस वजह से उसे एम्फोटेरिसन बी इंजेक्शन भी दिए गए लेकिन उससे ज्यादा सुधार नहीं हो रहा था। जांच में एसपरजिलस फंगस की पुष्टि होने के बाद उसे सिर्फ वेरिकोनोजोल इंजेक्शन ही दिए गए। फेफड़ों में ज्यादा संक्रमण होने के कारण उसे मुंबई भेजा गया है।

उपलब्धि — इंदौर के 48 फीसदी से ज्यादा लोगों को लग चुकी टीके की पहली खुराक

टीकाकरण में इंदौर देश में दूसरे नंबर पर

इंदौर (एजेंसी)।

प्रदेश का इंदौर शहर कई मामलों में अनुकरणीय पहल के लिए जाना जाता है। अब कोरोना टीकाकरण में भी वह देश में कोलकाता के बाद दूसरे नंबर पर है। अभी तक शहर के 48 फीसदी से ज्यादा लोगों को टीके की पहली खुराक लग चुकी है, जबकि कोलकाता में 50 फीसदी को। इस तरह आबादी के टीकाकरण के मान से इंदौर देश में दूसरे नंबर पर है। कोविड-19 की रोकथाम के तहत इंदौर जिला प्रशासन ने चलने-फिरने से लाचार लोगों को उनके घर जाकर कोविड-19 रोधी टीका लगाने का फैसला किया है। इससे टीकाकरण की गति बढ़ाने में मदद मिलेगी।

टीकाकरण में पहले स्थान पर कोलकाता

इंदौर के जिला टीकाकरण अधिकारी डॉ. प्रवीण जड़िया ने सोमवार को संवाददाताओं को बताया कि सामाजिक न्याय एवं निःशक्त जन कल्याण विभाग ने सर्वेक्षण के बाद स्वास्थ्य महकमे को ऐसे 51 लोगों की सूची सौंपी है जो किसी दिव्यांगता, अधिक उम्र और गंभीर बीमारियों के कारण चलने-फिरने से लाचार हैं तथा इन कारणों से उनकी जिंदगी उनके घर के बिस्तर तक सीमित है। सिविल सर्जन इन लाचार लोगों के स्वास्थ्य की वास्तविक स्थिति का पता लगाएंगे। इसके बाद पात्र लोगों को उनके घर जाकर कोविड-19 रोधी टीका लगाया जाएगा। जड़िया ने कहा कि आमतौर पर हर पात्र व्यक्ति को तय केंद्र में ही कोविड-19 रोधी टीका लगाया जा सकता है, लेकिन विशेष जरूरत वाले लोगों को महामारी से बचाने के लिए उनके घर जाकर टीके की खुराक देने का फैसला किया गया है। गौरतलब है कि इंदौर, मध्यप्रदेश में कोविड-19 से सबसे ज्यादा प्रभावित जिला है।

अब तक 13.53 लाख को लगे टीके

करीब 35 लाख की आबादी वाले इंदौर जिले में में टीकों की पात्रता वाली यानी 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों की संख्या 28 लाख है। इनमें से 13.53 लाख से ज्यादा लोगों को कोविड-19 रोधी टीके की पहली खुराक दी जा चुकी है। इनमें शामिल 2.35 लाख से ज्यादा लोगों को इस टीके की दोनों खुराक दी जा चुकी हैं।

प्रदेश में कोरोना के 242 नए मामले, 36 की मौत

भोपाल। प्रदेश में कोरोना के घटते मामलों के बीच सोमवार को 242 नए मामले आए, तो वहीं 36 नए मरीजों ने इस बीमारी से जान गवां दी है। वर्तमान में संक्रमण 0.3 पर पहुंच गई है। राज्य स्वास्थ्य संचालनालय द्वारा सोमवार को यहां जारी बुलेटिन के अनुसार पिछले चौबीस घंटों में प्रदेश में कोरोना के 242 नए मामले आए। वहीं 36 नए मरीजों की इस बीमारी से जान गवां दी। प्रदेश भर में अब तक 7,88,425 लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। इनमें से 7,75,896 मरीज कोरोना से मुक्त हो चुके हैं। सोमवार को 516 मरीज स्वस्थ हुए। इसके अलावा 3941 एक्टिव मरीज हैं, जिनका इलाज चल रहा है। इस बीच राजधानी भोपाल में सबसे अधिक 79 नए मामले सामने आए, तो वहीं इंदौर में 56 नए मामले सामने आए। इसके अलावा जबलपुर में 16, ग्वालियर में 6, सागर में 8, खरगोन में 6 सहित कुछ अन्य जिलों में कोरोना के मामले सामने आए है। प्रदेश के 52 जिलों में 18 जिले ऐसे हैं, जिनमें कोरोना के एक भी नए मामले सामने नहीं आए हैं।

टूलकिट मामले में रमन सिंह और संबित पात्रा को राहत

हाईकोर्ट ने एफआईआर पर लगाई अंतरिम रोक

बिलासपुर, (एजेंसी)। टूलकिट मामले में उच्च न्यायालय ने अंतरिम फैसला सुनाते हुए पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह और भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा के खिलाफ दर्ज एफआईआर पर राहत देते हुए रोक लगा दी है। शासन की तरफ से जब तक जवाब प्रस्तुत नहीं किया जाता तब रोक लगी रहेगी।

बता दें कि एनएसयूआई प्रदेश अध्यक्ष आकाश शर्मा की शिकायत पर रायपुर के सिविल लाइन थाने में पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह और भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया गया था। मामले में सिविल लाइन थाना ने पूछताछ के लिए दोनों की नेताओं को तलब किया था। वहीं दूसरी ओर टूलकिट मामले में कांग्रेस नेता राजीव गौड़ा, रोहन गुप्ता और सौम्या वर्मा से पूछताछ के लिए बेंगलुरु भी गई थी। पूर्व सीएम डॉ. रमन सिंह ने 18 मई को अपने ट्विटर अकाउंट से कांग्रेस का कथित लेटर पोस्ट करते हुए दावा किया था कि इसमें देश का माहौल खराब करने की तैयारी की प्लानिंग लिखी है। साथ ही लिखा गया कि विदेशी मीडिया में देश को बदनाम करने दुष्प्रचार और जलती लाशों की फोटो दिखाने का कांग्रेस षड्यंत्र कर रही है। ऐसा ही पोस्ट संबित पात्रा ने भी की थी। इसके बाद युवा कांग्रेस के नेताओं ने रमन सिंह व संबित पात्रा पर एफआईआर दर्ज करा दी।

समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने नई दिल्ली में राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव से मुलाकात की।

गुवाहाटी के राजगढ़ में भारी बारिश के बाद जलभराव वाली सड़क से गुजरता दूधवाला।

जम्मू में जम्मू क्षेत्र के पारंपरिक डोगरी त्योहार तमदेह से पहले लोग मिट्टी के पानी के बर्तन खरीदते हैं। हुए।

एक नजर

बंशी पहाड़पुर में अब होगा वैध खनन, राम मंदिर निर्माण के लिए यहीं से भेजा जा रहा है लाल और गुलाबी पत्थर

जयपुर । राजस्थान के भरतपुर जिले में स्थित बंशी पहाड़पुर में खनने को लेकर केंद्रीय वन,पर्यावरण एवं जलवायु मंत्रालय ने खनन की अनुमति दे दी है । बंशी पहाड़पुर से ही अयोध्या में राममंदिर निर्माण के लिए गुलाबी और लाल पत्थर भेजा जा रहा है। केंद्र सरकार के तीन दिन पहले खनन की अनुमति देने के बाद अब राज्य सरकार बंशी पहाड़पुर में खनन ब्लॉक तैयार कर निलामी करेगी। राज्य सरकार में खान विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव सुबोध अग्रवाल ने बताया कि केंद्र सरकार ने बंशी पहाड़पुर क्षेत्र के 398 हैक्टेयर क्षेत्र में डायवर्जन की पहली अनुमति दी है । अब राज्य के खान विभाग द्वारा शीघ्र ही निलामी के लिए ब्लॉक तैयार होंगे और फिर ई-ऑक्शन होगा । यहां करीब 70 ब्लॉक विकसित होने की उम्मीद है । यहां अब तक अवैध रूप से खनन हो रहा था,लेकिन अब वैध खनन होने से सरकार को काफी राजस्व मिलेगा । उल्लेखनीय है कि यहां निकलने वाले पत्थर की पूरे देश में मांग है ।

साल,2016 में इस पहाड़ी को अभ्यारण्य के लिए नोटिफाई कर दिया गया था । लेकिन जहां से पत्थर निकलते हैं वहां न तो जंगल है और न ही जानवर । इसको देखते हुए राज्य सरकार के राजस्व,खनन एवं वन विभाग ने संयुक्त सर्वे करवा कर डिनोटिफाई कराने के लिए केंद्र सरकार को कई बार पत्र लिखे गए थे,जिस पर अब निर्णय हुआ है । यहां निकलने वाले पत्थर की उम्र करीब 5 हजार साल मानी जाती है । अब तक यहां अवैध खनन हो रहा था । लेकिन अब वैध खनन हो सकेगा । अवैध खनन पर कई बार खान विभाग और भरतपुर जिला प्रशासन कार्यवाही करता था । उल्लेखनीय है कि बंशी पहाड़पुर से अयोध्या राम मंदिर निर्माण के लिए कुल 2.75 लाख घन फीट पत्थर भेजा जाएगा । इसमें से एक लाख घन फीट से अधिक भेजा जा चुका है ।

कटक में घट रहा है कोरोना ग्राफ, संक्रमितों की तुलना में दो गुना मरीज हुए स्वस्थ

कटक । कटक जिले में कोरोना का ग्राफ घट रहा है। जहां एक ओर कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या घट रही है। वही कोरोना से जंग लड़कर स्वस्थ होकर घर लौट रहे हैं अधिक संख्या में मरीज। अब जितनी संख्या में कोरोना संक्रमित मरीज जिले से पहचाने जा रहे हैं। अस्पताल से स्वस्थ होकर लौटने वाले मरीजों की संख्या उसकी तुलना में दो गुना है। रविवार को कटक जिले से 413 कोरोना संक्रमित मरीज की पहचान की गई थी। जिसमें से कटक शहर से 102 और ग्रामीण इलाकों से 284 मरीज शामिल है। ठीक इसी तरह कटक जिले से रविवार को 808 कोरोना संक्रमित मरीज स्वस्थ होकर घर लौटे हैं। हालांकि कटक जिले में संक्रमण घट रहा है लेकिन मौत का आंकड़ा थमने का नाम नहीं ले रहा है। सरकारी तथ्य अनुसार रविवार को चार कोरोना संक्रमित मरीजों की कटक जिले में मौत हुई है। कटक जिले के विभिन्न अस्पताल में आए दिन कोरोना बेड खाली होता जा रहा है। लेकिन कई गंभीर मरीज अब भी आईसीयू में भर्ती होने हेतु मौत की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। यह बात जिला प्रशासन की ओर से स्पष्ट की गई है। रविवार को कुल 340 टेस्टिंग की गई थी। जिले का आठगड़, सालेपुर, माहांगा, बारंग, नरसिंहपुर, कटक सदर में रविवार को एंटीजन टेस्ट नहीं किया गया था। छुट्टी के चलते टेस्टिंग संख्या भी घट रहा है। सोमवार को मिली रिपोर्ट के अनुसार कटक जिले में फिर से 480 कोरोना संक्रमित मरीज की पहचान की गई है।

ओडिशा में शुरू हुआ तीन दिवसीय रज महोत्सव, सीएम नवीन पटनायक ने दी शुभकामनाएं

भुवनेश्वर । कोरोना महामारी के बीच ओडिशा में आज से तीन दिवसीय रज महोत्सव शुरू हुआ है। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने प्रदेशवासियों को खास करके मां एवं बहनों को अपनी शुभकामनाएं दी है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि रज महोत्सव धरती माता की उपासना तथा नारी जाति की महानता का अनुपम पर्व है। समाज में नारी के अवदान को सम्मान जताने का पर्व है। इस अवसर पर छोटी-छोटी लड़कियों से लेकर मां बहनों तक सभी के स्वास्थ्य शिक्षा को बेहतर बनाने तथा उनके सुंदर भविष्य के लिए एक स्वस्थ समाज गठन करने को मुख्यमंत्री ने आह्वान किया है। मुख्यमंत्री ने सभी से अनुरोध किया है कि कोविड नियम का अनुपालन करते हुए घर में ही रहकर रज महोत्सव का पालन करें। पीठा ऑन व्हील - वहीं दूसरी तरफ ओटीडीसी की तरफ से पीठा ऑन व्हील कार्यक्रम शुरू किया गया है। इस कार्यक्रम के जरिए लोगों के घर-घर तक रज पीठा पहुंचाने की व्यवस्था की गई है। ओटीडीसी की अध्यक्ष श्रीमयी मिश्र ने इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया। पिछले साल की ही तरह इस साल भी ओटीडीसी की तरफ से पंथनिवास एवं मिशन शक्ति मां के सहयोग से भुवनेश्वर, संबलपुर तथा कटक शहर में पहली रज सेसुलभ मूल्य में स्वादिष्ट पीठा मुहैया किया जा रहा है। राजधानी भुवनेश्वर में 6 जगहों पर सुबह 7 बजे से पूर्वाह्न 11 बजे तक यह पीठा उपलब्ध किया गया है। मास्टर कैंटीन चौक, खंडगिरी, सीआरपी, पटिया, चंद्रशेखरपुर, रूपाली चौक एवं पंथनिवास में शहर के लोगों के लिए पीठा की व्यवस्था की गई है। महिला स्वयं सहायता समूह की तरफ से पीठा ऑन व्हील कार्यक्रम के जरिए पीठा बिक्री की जा रही है। यहां भी महिला स्वयं सहायता समूह की ओर से मास्क का वितरण किया जा रहा है। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने ओटीडीसी के पंथनिवास एवं मिशन शक्ति मां के सहयोग से आयोजित पीठा ऑन व्हील कार्यक्रम को शुभकामना दी है। श्रीमती मिश्र ने कहा है कि पूरी तरह से स्वच्छता प्रक्रिया का पालन करते हुए हाथ से तैयार किया गया विभिन्न प्रकार का पीठा लोगों की आवश्यकता को निश्चित रूप से पूरा करेगा। पर्यटन निदेशक सचिन आर यादव ने कहा है कि पंथनिवास में केवल प्रतीकात्मक झूले की व्यवस्था की गई है। यहां पर कोई कार्यक्रम नहीं किया जाएगा। भुवनेश्वर, कटक एवं संबलपुर के पंथनिवास में विशेष काउंटर खोल कर यह पीठा बेचा जाएगा।

पुरी जगन्नाथ मंदिर की मरम्मत को लेकर उच्च स्तरीय बैठक, पुरातत्व विभाग ने मंदिर प्रशासन को लिखा पत्र

भुवनेश्वर । पुरी श्री जगन्नाथ जी की रथयात्रा के दौरान 9 दिन का समय पुरातत्व विभाग को मंदिर के मरम्मत के लिए मिलता है। इस बार पुरातत्व विभाग ने समय से पहले ही जगन्नाथ मंदिर के मरम्मत को लेकर एक आकलन आरंभ कर दिया है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार जगन्नाथ मंदिर में कई जगह पर दरार आ गई है। महालक्ष्मी तथा माता विमला के मंदिर में से पानी का रिसाव भी होता है। पुरातत्व विभाग पर जगन्नाथ मंदिर के रखरखाव का उत्तरदायित्व है मगर विभाग द्वारा सही ढंग से काम ना करने की बात सामने आती रही है। शनिवार को जगन्नाथ मंदिर के प्रशासक भारतीय पुरातत्व विभाग के डीजी एवं तकनीकी कमेटी के विशेषज्ञों के मध्य एक उच्च स्तरीय बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक के बाद निर्णय लिया गया है कि रथयात्रा के दौरान जगन्नाथ मंदिर के गर्भगृह सहित नाट्य मंदिर, जगमोहन, महालक्ष्मी मंदिर, बिरला मंदिर, कोइली बैकुंठ, मेघनाद प्राचीर का मरम्मत कार्य किया

शिवसेना नेता संजय राउत का भाजपा पर आरोप कहा- शिवसेना से किया गया गुलामों जैसा बर्ताव

जलगांव । शिवसेना सांसद संजय राउत ने जलगांव में रविवार को एक कार्यक्रम के दौरान भाजपा पर आरोप लगाते हुए कहा कि शिवसेना से गुलाम की तरह व?यवहार किया जाता था। 2014 से 2019 तक जब महाराष्ट्र में भाजपा सत्ता में थी, उस दौरान शिवसेना को राजनीतिक रूप से खत्म करने की कोशिश की गई थी। संजय राउत ने पार्टी कार्यालय में एक बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि बीते पांच वर्षों में शिवसेना के सत?ता में रहने के बावजूद भी ग्रामीण इलाकों से शिवसेना की मौजदूगी को मिटाने का प्रयास किया गया और हमारे साथ गुलामों जैसा बर्ताव किया गया।

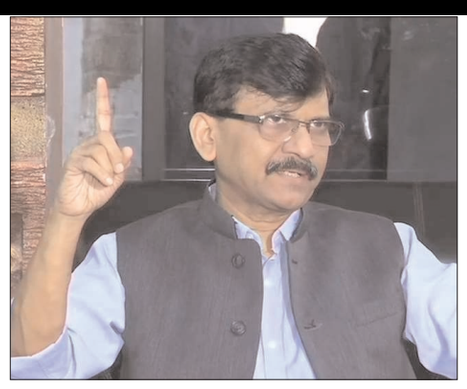

बता दें कि संजय राउत की ये टिप्पणी बीते दिनों महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात के कई दिन बाद आई है। इस बैठक के बाद से लगातार राजनीतिक अटकलें लगायी जा रही हैं। जबकि पीएम के साथ हुई इस बैठक को लेकर मुख्यमंत्री ठाकरे का कहना है कि, हम (भाजपा और शिवसेना) राजनीतिक रूप से एक साथ नहीं जुड़ सकते लेकिन इसका अर्थ ये बिलकुल भी नहीं है कि हमारा रिश्ते टूट गए हैं। मैं कोई पाकिस्तान में नवाज शरीफ से नहीं मिलने गया था, मैं पीएम से व्यक्तिगत रूप से मिलने गया था और इसमें कुछ भी गलत नहीं है।

संजय राउत ने मुख्यमंत्री ठाकरे की पीएम मोदी से मुलाकात के बाद से शिवसेना, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) और कांग्रेस की महा विकास अघाड़ी सरकार में मची हलचल को लेकर कहा कि, यह एक मात्र अफवाह है कि शिवसेना के मुख्यमंत्री को बदल दिया जाएगा। जब तीन राजनीतिक दलों ने मिलकर सरकार बनाई है तो सबने मिलकर निर्णय लिया कि कि मुख्यमंत्री पांच साल के लिए उद्धव ठाकरे ही होंगे। संजय राउत ने साफ किया कि ये तीन दलों का विलय नहीं है बल्कि गठबंधन है। हर दल अपने विस्तार और खुद को मजबूत करने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र है। हर चुनाव एक साथ लड़ने के लिए हम प्रतिबद्ध नहीं हैं। स्थानीय चुनावों का निर्णय स्थानीय नेता लेता है, हम तो बस लोकसभा और राज्य चुनावों के लिए रणनीति बनाते हैं। ज्ञात हो कि मुख्यमंत्री पद के मुद्दे पर 2019 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों के पश्चात भाजपा-शिवसेना गठबंधन खत्म हो गया था।

मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना तेलंगाना के मुख्यमंत्री और गवर्नर के साथ यादाद्री मंदिर में करेंगे पूजा

नई दिल्ली । भारत के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना तेलंगाना के राज्यपाल तमिलिसाई सुंदरराजन और सीएम के चंद्रशेखर राव के साथ शहर में स्थित यादाद्री मंदिर में जाएंगे। बता दें कि इससे पहले गुरुवार से न्यायाधीश ने कई मंदिरों का दौरा किया है।

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, एनवी रमना अपनी पत्नी के साथ इससे पहले शुक्रवार को आंध्र प्रदेश के तिरुपति मंदिर पहुंचे थे और भगवान बाला जी व्यंकटेश्वर के दर्शन किए और पूजा की थी। वहीं गुरुवार को भी देर रात सीजेआई और उनकी पत्नी ने मंदिर में दर्शन किए और 'द्वाजस्थंबम' में पूजा अर्चना की थी। बता दें कि इस साल 24 अप्रैल को मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ लेने के बाद यह उनका मंदिर का पहला दौरा है।

केरल में फिर उभरा लव जिहाद का खतरा, आईएसआईएस में शामिल चार महिलाओं को भारत नहीं आने देगी सरकार

तिरुअनंतपुरम । केरल में एक बार फिर से लव जिहाद का मुद्दा उभरकर सामने आ गया है। दरअसल, केंद्र सरकार ने उन चार आइएस आतंकियों की बीवियों को भारत में वापस लेने से इन्कार कर दिया है जो अफगानिस्तान के इस्लामिक शासन में रहने के लिए अपने पति और बचों के साथ वहां गई थीं। सोनिया सबैस्टियन उर्फ आएशा, मेरिन जेकब उर्फ मेरिन, निमिषा नायर उर्फ फातिमा इसा और रफीला वर्ष 2016-18 के बीच इस्लामिक एस्टेट के खुरासन प्रांत में रहने गई थीं। विभिन्न हमलों में उनके पति मारे गए और इन महिलाओं ने वर्ष 2019 में अफगानिस्तान प्रशासन के समक्ष समर्पण कर दिया था।

भारत से भागकर इस्लामिक स्टेट में शामिल होने वाली चार महिलाओं को लेकर मोदी सरकार ने बड़ा फैसला किया है। रिपोर्ट है कि मोदी सरकार ने आतंकी संगठन में शामिल होने वाली चारों महिलाओं को भारत नहीं आने देने का फैसला किया है। ये चारों महिलाएं केरल की रहने वाली थीं और अफगानिस्तान के जेल में बंद हैं। रिपोर्ट के मुताबिक ये चारों महिलाएं केरल से भागकर अफगानिस्तान के खुरासान प्रांत में अपने पति के साथ गई थीं और फिर इन्होंने आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट वाइन कर लिया था।

विदेश मंत्रालय के अधिकारियों और खुफिया एजेंसियों के बड़े अफसरों समेत कई भारतीय सुरक्षा एजेंसियों ने इन पूछताछ के बाद पाया इनके धर्मातरण के बाद इन्हें बेहद घातक किस्म का कट्टरपंथी बनाया गया है। इनका केरल में वापस आना राय के लिए बेहद घातक हो सकता है। जबकि बिंदू की मां ने इस मामले में सगाई का कोई हाथ ही नहीं है। चारों महिलाएं केरल की रहने वाली हैं, जिन्होंने पूरी दुनिया में इस्लाम का शासन स्थापित करने की मकदस से बनाए गय आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट को 2016-18 में वाइन किया था। उस वक्त आईएसआईएस ने दुनियाभर के मुस्लिमों से आईएसआईएस वाइन करने की अपील की थी, लेकिन चंद मुस्लिमों का उन्हें समर्थन मिला था। भारत से भी करीब दर्जन भर लोग भागकर अफगानिस्तान और सीरिया पहुंचे थे।

दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल का अहमदाबाद दौरा, सियासी जमीन की तलाश शुरू

अहमदाबाद । दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि गुजरात में भाजपा-कांग्रेस का गठजोड़ है। आम आदमी पार्टी जनता को एक नया विकल्प देगी। गुजरात में 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी ने प्रदेश में अपनी सियासी जमीन तलाशना शुरू कर दिया है।

अहमदाबाद में केजरीवाल ने कहा की 75 साल से जनता ने कांग्रेस - भाजपा को वोट दिया लेकिन जनता को इन लोगों ने बदहाल बना दिया। युवा बेरोजगार है तथा किसान आत्महत्या कर रहे हैं। बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं मिल रही है और लोगों को स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए भटकना पड़ रहा है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के लोगों को बिजली मुफ्त, पानी मुफ्त दिया तथा बेहतर शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं दी है। गुजरात के लोगों को भी इन सब सुविधाओं को पाने का हक है, भाजपा और कांग्रेस पिछले 27 साल से गुजरात में गठजोड़ की राजनीति कर रहे हैं। भाजपा को जब भी जरूरत होती है कांग्रेस अपना माल पहुंचा देती है। प्रदेश में राजनीतिक विकल्प हीनता का माहौल है, सरकार जनता की बात सुनने को तैयार नहीं है। उनको परिणाम पता है, सत्ता में उन्हें ही रहना है इसलिए वे जनता की समस्याओं को सुनना भी पसंद नहीं करते हैं।

गुजरात की राजनीति खराब है कोरोना महामारी के दौरान यहां लोगों को अनाथ छोड़ दिया गया। केजरीवाल ने कहा चुनाव में चेहरे जनता खुद तय करती है लेकिन उन्होंने पार्टी में आज ही शामिल हुए पत्रकार ईशुदान गढवी को गुजरात का केजरीवाल बताया। उन्होंने कहा सिस्टम के अंदर रहकर काम करने की एक सीमा होती है आप बहस, शोर, वाद-विवाद कर सकते हैं लेकिन काम करना तो सरकार के हाथ में होता है। केजरीवाल के साथ आम आदमी पार्टी गुजरात के अध्यक्ष गोपाल इटालिया मौजूद थे। पत्रकार ईशुदान गढवी ने आप में शामिल होने के बाद कहा कि वह जनता की सेवा के लिए उनकी समस्याओं को उठाने के लिए राजनीति में शामिल हुए हैं। केजरीवाल उनके रोल मॉडल हैं तथा उनकी तरह ही वह राजनीति की गंदगी को साफ करने के लिए इसमें उतरने को तैयार हुए है। केजरीवाल पत्रकार वार्ता से पहले आश्रम रोड स्थित भगवान कृष्ण के मंदिर वल्लभ सदन पहुंचे। मंदिर में दर्शन करने तथा पत्रकारों से मुखातिब होने के बाद उन्होंने आश्रम रोड पर ही पार्टी के नए कार्यालय का उद्घाटन किया। पार्टी की मीडिया प्रभारी तुली बैनर्जी ने केजरीवाल के स्वागत में लगाए गए झंडे व बैनर को फाड़ने का आरोप लगाया है।

धीमी पड़ी कोरोना संक्रमण की रफ्तार- 72 दिनों बाद आए सबसे कम मामले व 3,921 लोगों की हुई मौत

नई दिल्ली । कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर का प्रकोप अब देश में शांत होता दिख रहा है। बीते 24 घंटों के दौरान देश में कोरोना संक्रमण के 70,421 नए मामले आए और 3,921 संक्रमितों की मौत हुई। 31 मार्च के बाद संक्रमण का सबसे कम आंकड़ा आज दर्ज किया गया है। इसके बाद अब तक देश में कुल संक्रमितों का आंकड़ा 2,95,10,410 हो गया और मरने वालों की संख्या 3,74,305 हो गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने सोमवार सुबह महामारी से जुड़े ताजा आंकड़ों को जारी किया।

स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार, बीते 24 घंटों में 1,19,501 संक्रमित स्वस्थ हो अस्पताल से डिस्चार्ज किए गए। इसके बाद कुल डिस्चार्ज की संख्या 2,81,62,947 हो गई। वहीं अभी देश में सक्रिय मामलों की कुल संख्या 9,73,158 है। 16 जनवरी से देश में राष्ट्रीय टीकाकरण अभियान शुरू हुआ। इसके तहत अब तक कुल टीकाकरण का आंकड़ा 25,48,49,301 है जिसमें से 14,99,771 वैक्सीन गई है।

भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के अनुसार भारत में रविवार तक कोरोना वायरस के लिए 14,92,152 सैंपल टेस्ट किए गए। इसके बाद अब तक देश में कुल टेस्ट किए गए सैंपल का आंकड़ा 37,96,24,626 है। अमेरिका की जॉन्स हॉपकिन्स यूनिवर्सिटी के अनुसार, पूरी दुनिया में अब तक कोरोना संक्रमितों का कुल आंकड़ा 175,884,287 हो गया है और 3,799,649 संक्रमितों की मौत हो चुकी है।

महामारी की दूसरी लहर की तबाही के मद्देनजर देश के अधिकांश हिस्सों में नाइट कर्फ्यू और लॉकडाउन समेत कड़ी पाबंदियां लागू की गई। कई राज्यों को अनलॉक कर दिया गया है लेकिन अभी 12 राज्यों- हिमाचल प्रदेश, पुडुचेरी, पश्चिम बंगाल, गोवा, तेलंगाना, केरल, तमिलनाडु, ओडिशा, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, झारखंड और ओडिशा में अब भी सख्त पाबंदी जारी है।

गुजरात में 455 नए मरीज, 6 की मौत; अब तक 8 लाख हुए स्वस्थ

अहमदाबाद । गुजरात में कोरोना संक्रमण से स्वस्थ होने वालों की संख्या 8 लाख के पार चली गई है। पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 455 केस दर्ज किए गए जबकि 6 लोगों की मौत हुई। राज्य में कोरोना के सक्रिय केसों की संख्या 10249 है जबकि अब तक 8 लाख 75 लोग स्वस्थ होकर घर पहुंच गए हैं। राज्य में अब तक कुल 8 लाख 20326 लोग संक्रमित हो चुके हैं। अहमदाबाद महानगर पालिका में 54 केस दर्ज किए गए जबकि मरने वालों की संख्या 2 रही। वडोदरा में 41 केस 1 मौत, सूरत में 71 केस 1की मौत, राजकोट में 22 केस, 0 मौत, जामनगर में 9 केस 0 मौत, भावनगर में 00 केस मौत शून्य, जूनागढ़ में 15 केस मौत का आंकड़ा शून्य, वही गांधीनगर में भी संक्रमण के 4 मामले सामने आए जबकि मौत का आंकड़ा शून्य रहा। पिछले 24 घंटे में 8 में से 5 महानगर पालिकाओं में कोरोना से एक भी मौत नहीं हुई इनमें राजकोट जूनागढ़ जामनगर गांधीनगर तथा भावनगर महानगर पालिका शामिल है। विविध जिलों में कोरोना संक्रमण के आंकड़े इस प्रकार रहे सूरत में कोरोना संक्रमण के 25 केस दर्ज किया गए। वडोदरा 31 राजकोट 24 जूनागढ़ 19 नवसारी 17, गीर सोमनाथ 14, भरूच 11 कक्षा 10 मेहसाणा 7 बनासकांठा 6 खेड़ा 5 साबरकांठा 5 जामनगर 3 अरवल्ली दो केस दर्ज किए गए।

डेल्टा वेरिएंट म्यूटेट कर हुआ डेल्टा प्लस, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी कॉकटेल को दे सकता है मात

नई दिल्ली । कोरोना वायरस से लड़ रही दूनियां को अब इसके ने वेरिएंट का बी सामना करना पड़ रहा है। कोरोना वायरस लगातार अपने आप को बदल रहा है। एक अध्ययन में कहा गया है कि कोरोना का डेल्टा वेरिएंट म्यूटेट कर डेल्टा प्लस में बदल गया है, जो मौजूदा वैरिएंट से अधिक घातक साबित हो सकता है। वैज्ञानिकों को का मानना है कि कोरोना संक्रमण के इलाज के लिए मरीजों को दी जा रही मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज कॉकटेल को बी यह वेरिएंट मात दे सकता है।

बता दें कि वायरस से संक्रमित होने या उसके खिलाफ टीकाकरण के बाद जो एंटीबॉडी बनती है, वो वायरस से लड़ने में बहुत प्रभावी होती है। एक वायरस आमतौर पर एक सेल में प्रवेश करके खुद की संख्या को बढ़ाता है और समय आने पर नई कोशिकाओं को अपना शिकार बनाता है। हमारे शरीर में मौजूद एंटीबॉडी वायरस से चिपक जाती है और अन्य कोशिकाओं तक पहुंच को खत्म कर देती है।

हाल ही में डब्ल्यूएचओ ने भारत में पहली बार पहचाने गए कोरोना के वैरिएंट बी.1.617.1 और बी.1.617.2 को कप्पा और डेल्टा नाम दिया था। जबकि, ब्रिटेन में पहली बार मिले वैरिएंट बी.1.17 को अल्फा, दक्षिण अफ्रीका में पहचाने गए वैरिएंट को बीटा और ब्राजील के वैरिएंट को गामा नाम दिया गया। हालांकि इनकी वैज्ञानिक पहचान में कोई बदलाव नहीं किया गया है।

दूरी तरफ कोविड-19 के डेल्टा वेरिएंट के मामलों की रफ्तार को देखते हुए ब्रिटेन 21 जून को समाप्त होने वाली लॉकडाउन की तमाम पाबंदियों को और चार सप्ताह तक जारी रखने पर विचार कर रहा है। वहीं पब्लिक हेल्थ इंग्लैंड (पीएमई) के अनुसार, डेल्टा वेरिएंट से संक्रमित होने वालों की संख्या में पिछले एक सप्ताह में करीब 30,000 का इजाफा हुआ है और यह 42,323 पहुंच गयी है।

जयपुर में बनेगा महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ गर्वनेंस एंड सोशल साइंसेज

जयपुर । टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज और महाराष्ट्र इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी स्कूल ऑफ गर्वनेंस, पुणे की तर्ज पर जयपुर में भी महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ गर्वनेंस एंड सोशल साइंसेज शुरू होगा। यह इंस्टीट्यूट युवाओं को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की शिक्षा को आत्मसात करते हुए सामाजिक कार्यों में भूमिका निभाने को लेकर तैयार करने के लिहाज से शुरू किया जा रहा है। इंस्टीट्यूट की योजना को मूर्त रूप देने के लिए लॉ यूनिवर्सिटी के कुलपति डॉ.देवस्वरूप की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की है।

यह कमेटी पुणे जाकर महाराष्ट्र इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी स्कूल ऑफ गर्वनेंस एवं टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज के कार्यकलापों का अध्ययन करेगी। वहां के प्रबंधकों के साथ संवाद कर कार्य योजना तैयार करेगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बजट में महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ गर्वनेंस एंड सोशल सोशल साइंसेज बनाने की घोषणा की थी। जयपुर के सेंट्रल पार्क में बनने वाले इस इंस्टीट्यूट में प्राथमिकता के आधार पर स्टूडेंट्स का चयन होगा। चयनित स्टूडेंट्स को डिप्लोमा कोर्स में प्रवेश दिया जाएगा।

इंस्टीट्यूट परिसर में ही महात्मा गांधी दर्शन म्यूजियम भी बनाया जाएगा। इंस्टीट्यूट और म्यूजियम में महात्मा गांधी की पूरी जीवन यात्रा से जुड़े तथ्यों का समावेश किया जाएगा। गहलोत का कहना है कि प्रदेश में युवा शांति सेना बनाने जैसे प्रयास भी किए जाने की योजना है। उल्लेखनीय है कि डॉ.देवस्वरूप गहलोत के पिछले कार्यकाल में राजस्थान यूनिवर्सिटी के कुलपति थे। उसके बाद वे यूजीसी में चले गए थे।

गैर-कोरोना मरीजों के लिए खुला एम्स भोपाल, आम मरीजों के लिए इलाज मिलना होगा आसान

भोपाल । देश में धीरे-धीरे अनलॉक हो रहा है, जिसके तहत कोरोना प्रतिबंधों में ढील दी जा रही है। बढ़ते मामलों के चले अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) भोपाल भी गैर-कोरोना मरीजों के लिए फिर से खुल गया है। आज यानी 14 जून से आम मरीजों के लिए इलाज की सुविधा मिलना शुरू हो जाएगी। अस्पताल के डायरेक्टर प्रोफेसर डॉक्टर सरमन सिंह ने इस संबंध में शुक्रवार को आदेश जारी कर दिए हैं।

बता दें कि एम्स भोपाल समेत सभी एम्स में गैर कोरोना मरीजों के इलाज की सुविधा फिर से शुरू करने को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय में एक बैठक के बाद यह निर्णय हुआ है। बैठक में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ हर्षवर्धन भी मौजूद थे। एम्स भोपाल में ओपीडी, गैर कोरोना मरीजों की सर्जरी, फिजियोथेरेपी आदि सुविधाएं धीरे-धीरे फिर से शुरू हो रही हैं। ओपीडी में फिलहाल ज्यादा मरीजों को इकट्ठा होने की इजाजत नहीं है। हालांकि, इस दौरान कोविड मरीजों के इलाज की सुविधा भी जारी रहेगी।

कोरोना के चलते भले ही ओपडी को फिर से शुरू किया गया है, लेकिन कुछ प्रतिबंध अभी जारी रहेंगे।ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से कम लोगों को ही टोकन दिए जाएंगे ताकी ज्यादा भीड़ ना हो। बता दें कि अप्रैल में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ने के बाद से पहले सर्जरी बंद की गई थी। इसके बाद गैर कोरोना मरीजों की ओपीडी भी बंद कर दी गई थी। हालाकि, इमरजेंसी वाले मरीजों के लिए सुविधाएं बंद नहीं की गई थी। इमरजेंसी मरीजों के ऑपरेशन भी किए जा रहे थे। एम्स के अधिकारियों के मुताबिक, 1 से 2 दिन के भीतर यह तय कर लिया जाएगा कि किस तरह से ओपीडी और अन्य सुविधाएं बहाल की जाएंगी। बता दें कि एम्स भोपाल में भोपाल ही नहीं प्रदेश भर के मरीज इलाज कराने के लिए आते हैं।

शतरंज के ग्रैंडमास्टर विश्वनाथन आनंद के खिलाफ खेलेगे आमिर

भारतीय शतरंज ग्रैंडमास्टर और पूर्व विश्व शतरंज चैंपियन विश्वनाथन आनंद अक्षय पात्र फाउंडेशन के कोविड-19 राहत फीडिग प्रयासों के लिए धन जुटाने के लिए देश की मशहूर हस्तियों और व्यवसायियों के खिलाफ एक 'एक साथ प्रदर्शनी' मैच खेलेंगे। चेकमेट कोविड श्रृंखला में 5 बार के विश्व चैंपियन, विश्वनाथन आनंद होंगे, जो दस भारतीय हस्तियों और व्यापारिक नेताओं-पांच को एक घंटे के सिमुल गेम एक बार में खेलेंगे। इनमें आमिर खान, किच्चा सुदीप, रितेश देशमुख, गायक अरिजीत सिंह, गायक-गीतकार अनन्या बिड़ला, क्रिकेटर युजवेंद्र चहल, श्याओमी इंडिया के एमडी मनु कुमार जैन, जेरोधा के सह-संस्थापक निखिल कामथ, निर्माता साजिद नाडियाडवाला और प्रचुरा पदकन्नया शामिल हैं। इस चैरिटी कार्यक्रम की सभी आय कमजोर समुदायों के व्यक्तियों और परिवारों की सेवा करने के लिए जाएगी, जो महामारी की इस विनाशकारी दूसरी लहर के दौरान भूख से जूझ रहे हैं। चैरिटी इवेंट चेसडॉटकॉम इंडिया द्वारा चेकमेट कोविड-सेलिब्रिटी एडिशन का एक हिस्सा है और अक्षय पात्र के सहयोग से, प्रचुरा पदकन्नया ,सीईओ - एकस्ट्रा टेलेन्ट मैनेजमेंट का हिस्सा है। यह 13 जून, 2021 को शाम 500 बजे आयोजित किया जाएगा और भारत के आधिकारिक यू-ट्यूब चैनल चेस डॉट कॉम पर लाइव-स्ट्रीम किया जाएगा।

शेरनी में अपने किरदार में ढलने के लिए विद्या बालन ने ऐसे की तैयारी

विद्या बालन अभिनीत अमेजन प्राइम वीडियो की आगामी फिल्म 'शेरनी' एक पथप्रदर्शक कहानी है, जो एक महिला वन अधिकारी की असामान्य नौकरी और उनकी शादी के माध्यम से नेविगेट करते हुए उनके सफर को दर्शाती है।

विद्या बालन ने इस फिल्म की तैयारी के बारे में बात करते हुए कहा, मैं वास्तव में कुछ वन अधिकारियों से यह समझने के लिए मिली थी कि उनकी नौकरी में क्या शामिल है। जिसमें एक वन अधिकारी बनने के लिए ट्रेनिंग, विभिन्न पोस्टिंग और उनके सामने आने वाली चुनौतियों से जुड़ी स्टडी आती है। उन्होंने कहा, काम की प्रकृति ऐसी है कि यह कई बार शारीरिक रूप से कठिन और खतरनाक भी हो सकता है, इसलिए पारंपरिक रूप से पुरुष प्रधान था, लेकिन इन महिला अधिकारियों ने साझा किया कि कैसे वे पितृसत्तात्मक मानसिकता के आसपास अपना रास्ता तय करती हैं, यह सब बहुत मददगार था। अपने करैक्टर के बारे में विद्या ने कहा, विद्या विन्सेंट के बारे में मुझे जो पसंद है वह यह है कि वह कुछ शब्दों की महिला है और फिर भी वह जिस चीज में विश्वास करती है उसके लिए खड़े होने का साहस रखती है। इसलिए आपको आक्रामक होने या पुरुषों की दुनिया में पुरुष होने की जरूरत नहीं है, आप एक महिला की तरह रह सकती हैं और फिर भी अपना रास्ता खोज सकती हैं।

विद्या बालन के साथ-साथ शरत सक्सेना, मुकुल चड्ढा, विजय राज, इला अरुण, बृजेंद्र कला और नीरज काबी जैसे नाम आपका मनोरंजन करने के लिए तैयार हैं। टी-सीरीज और अबुदंतिया एंटरटेनमेंट द्वारा निर्मित, यह मस्ट-वॉच ड्रामा न्यूटन-फेम निर्देशक अमित मसुरकर द्वारा निर्देशित है। प्राइम मेंबर्स 'शेरनी' को 18 जून से एक्सक्लूसिव तौर पर ऐमजॉन प्राइम वीडियो पर स्ट्रीम कर सकते हैं।

राजस्थानी रेगिस्तान की तपती गर्मी में दो दिनों में हुई 'पानी पानी' की शूटिंग

जैकलीन फर्नांडीज का कहना है कि उन्होंने राजस्थान की भीषण गर्मी में अपने नए म्यूजिक वीडियो 'पानी पानी' के लिए दो दिनों तक शूटिंग की। अभिनेत्री ने शुक्रवार को एक इंस्टाग्राम कोलाज पोस्ट के साथ यह खुलासा किया। कोलाज पर्दे के पीछे के पलों का है जो बादशाह द्वारा रचित और बादशाह और आस्था गिल द्वारा गाया गया गीत बनाने में इस्तेमाल किया गया। उन्होंने कैप्शन के रूप में लिखा, ''हमने राजस्थानी रेगिस्तानी गर्मी में 2 दिनों में हैशटैग पानीपानी की शूटिंग की लेकिन फिर भी इस टीम ने इसे इतना आसान बना दिया! लव यू दोस्तों।'' यह ट्रैक पिछले साल के विवादास्पद लेकिन लोकप्रिय 'गेंदा फूल' के बाद बादशाह और जैकलीन के बीच दूसरा गाना है। जैसलमेर में सेट किया गया यह गीत 8 जून को रिलीज हुआ और वर्तमान में फोटो-शेयरिंग वेबसाइट पर 26,161,055 बार देखा गया और 4.20 लाख लाइक्स हैं।

'राधे' के बाद 'मास्टर' बनने की तैयारी में सलमान खान

सलमान खान की फिल्म 'राधे : योर मोस्ट वांटेड भाई' को समीक्षकों की भले ही कुछ खास प्रतिक्रिया ना मिली हो लेकिन प्रशंसकों ने जबरदस्त उत्साह दिखाया। फिल्म को रिकॉर्ड संख्या में ओटीटी प्लेटफॉर्म पर लोगों ने देखा। 'राधे' के बाद अब सलमान के प्रशंसक उनकी अगली फिल्म का इंतजार कर रहे हैं। खबर है कि जल्द ही अभिनेता अपनी दो बड़ी बजट की फिल्मों का एलान कर सकते हैं।

'मास्टर' बनेंगे सलमान

खबरों की मानें तो सलमान अगले महीने अपनी दो फिल्मों की घोषणा करेंगे। अंग्रेजी अखबार मिड डे के मुताबिक, सलमान खान थालापति विजय की तमिल फिल्म 'मास्टर' की हिंदी रीमेक करेंगे। यह फिल्म इस साल की शुरुआत में रिलीज हुई थी और दर्शकों ने इसे बहुत पसंद किया। लोकेशन कनगराज निर्देशित फिल्म को सलमान ने देखा। रिपोर्ट के मुताबिक वो फिल्म को लेकर एक्साइटेड हैं और इसे करने के लिए तैयार हैं।

दूसरी आने वाली फिल्म

इसके अलावा एक बड़े स्टूडियो के तहत सलमान खान एक्शन थ्रिलर फिल्म करेंगे। इन सबके साथ सलमान के पास मनीष शर्मा की 'टाइगर 3', फरहाद सामजी की 'कभी ईद कभी दिवाली', साजिद नाडियाडवाला की 'किक 2' और सूरज बड़जात्या की अगली फिल्म है। इस तरह कुल छह बड़े बजट की फिल्में अब सलमान के कंधे पर हैं।

परिवार के साथ बिता रहे वक्त

फिलहाल सलमान खान अपने पनवेल स्थित फार्महाउस पर हैं और परिवार के साथ वक्त बिता रहे हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक पूरा परिवार गोवा में छुट्टियां बिताने जाएगा। वहां से लौटने के बाद सलमान अपनी आने वाली दो फिल्मों का एलान करेंगे।

एक्ट्रेस अनीता हसनंदानी ने छोड़ी इंडस्ट्री

टीवी की जानी-मानी एक्ट्रेस अनीता हसनंदानी इन दिनों अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर काफी बिजी हैं। उन्होंने कुछ समय पहले ही बेटे आरव रेड्डी को जन्म दिया है। सोशल मीडिया पर अनीता आए दिन अपने बेटे के साथ क्यूट फोटोज और वीडियोज शेयर करती दिखाई दे जाती हैं। वहीं, हाल ही में अनीता अपने करियर को लेकर चौंकाने वाला फैसला लेकर सुर्खियों में आ गई हैं। अनीता ने एक्टिंग को अलविदा कह दिया है। अपने लेटेस्ट इंटरव्यू में उन्होंने शोबिज क्विट करने के पीछे की वजह भी बताई है। अनीता हसनंदानी छोटे पर्दे के कई बड़े शोज का हिस्सा रह चुकी हैं। उन्होंने कुछ समय पहले एकता कपूर के सुपरनैचुरल सीरियल 'नागिन' में शानदार एक्टिंग से फैंस का दिल जीत लिया था। अनीता ने खुलासा किया है कि वो सिर्फ अपने बेटे के साथ घर पर वक्त बिताना चाहती हैं। उन्होंने कहा- 'मैंने तय किया था कि जब भी मेरा बच्चा होगा तो मैं इंडस्ट्री और अपने काम को छोड़ दूंगी। मैं अब केवल अपने बेटे की मां के रोल पर फोकस करना चाहती हूं'। अनीता ने कहा- 'महमारी की वजह से नहीं बल्कि मैं तो वैसे ही इंडस्ट्री छोड़ने वाली थी। मैं घर पर अपने बच्चे के साथ रहना चाहती हूं। इमानदारी से कहूं तो काम अभी मेरे दिमाग में है ही नहीं। मैं वाकई नहीं जानती कि मैं कब वापस लौटूंगी'। उन्होंने ये भी बताया कि अभी वो थोड़ा-बहुत काम इसलिए कर रही हैं क्योंकि उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था। बता दें कि अनीता और रोहित रेड्डी इसी साल फरवरी महीने में पेरेंट्स बने हैं।

कटरीना कैफ के साथ रोमांस करना चाहते हैं सुनील ग्रोवर

सुनील ग्रोवर अपनी बेहतरीन कॉमेडी के साथ ही अपनी दमदार एक्टिंग के लिए भी जाने जाते हैं। सुनील ग्रोवर जल्दी ही जी5 की वेब सीरीज सनफ्लावर में नजर आएंगे। वेब सीरीज की रिलीज से पहले सुनील ग्रोवर के साथ खास बातचीत।

सिनेमाई दुनिया की शुरुआत कैसे हुई?

मैं चंडीगढ़ के कॉलेज के फर्स्ट ईयर में था, तब ये लोग (फिल्म प्यार तो होना ही था की टीम) शूट करने आए थे। मैं कॉलेज में एक्टिंग वगैरह करता रहता था, टीम के लोगों ने कहा कि एक आर्टिस्ट चाहिए। ऐसे में अनीज बज्मी साहब से मिला और फिर शुरुआत हुई। एक ही दिन का शूट था।

डेब्यू से पहले सिनेमाई सफर आसान लगता था या डेब्यू के बाद सफर आसान लगा?

पहले आसान लगता था, लेकिन दूसरे तरीके से। क्योंकि कुछ किया नहीं था, तो लगता था कि बस जाकर कर दो। वैसे होता सब आसान ही है, हम लोग खुद ही उसे मुश्किल बना देते हैं।

अपने किरदारों की तैयारी कैसे करते हैं?

ये पूरी तरह से निर्भर करता है कि किरदार क्या है। इसके बाद जो भी हमें स्टोरी बता रहे हैं, उनकी उस किरदार से क्या अपेक्षा है। फिर उनके विजन के हिसाब से तैयारी होती है। कई किरदारों की तैयारी कम होती है, कई किरदारों पर तैयारी ज्यादा करनी होती है। कुछ के लिए फिजिकल तो कुछ के लिए मेंटली तैयारी करनी होती है। मुझे हर किरदार के लिए मेहनत करनी होती है। क्योंकि मैं थोड़ा मंदबुद्धि भी हूं।

जी5 की आपकी अपकमिंग सीरीज सनफ्लावर के बारे में कुछ बताएं?

ये वेब सीरीज है, जो विकास बहल साहब ने लिखी है और विकास बहल व राहुल सेनगुप्ता ने निर्देशित की है। इस में एक किरदार है सोनू, ये सीरीज एक सोसायटी के लोगों की कहानी है। जहां एक शख्स की मौत हो जाती है, फिर किस- किस पर शक का दायरा जाता है, यही कहानी है। मेरा किरदार सोनू है. देखने में सिंपल है, इनोसेंट है.लेकिन वो अपने हिसाब से सिंपल और इनोसेंट नहीं है। इसके अदंर एक स्टोरी है, जहां कई ऐसे मूमेंट्स हैं, जहां आप सबसे कम उम्मीद करते हैं कि अब हंसी आएगी, वहीं पर हंसी आती है। ह्यूमर और थ्रिल का साथ में मजा है।

ऑनस्क्रीन सभी किरदार जमे हुए हैं, ऑफस्क्रीन कैसा माहौल रहता था?

उन दिनों कोविड के दिशा निर्देश लिए जा रहे थे। सेट पर बहुत अच्छा और टेंशन फ्री माहौल रहता था। शुरुआती दो- तीन दिन थोड़ा जमने में लगा, उसके बाद तो खूब हंसता खेलता माहौल था। मैं सोचता था कि सेट पर थोड़ा जल्दी जाने का मौका मिल जाए तो सबके साथ वक्त मिल जाएगा। सेट पर बहुत- बहुत एन्जॉय किया।

किरदारों का आइडिएशन कैसे होता है?

कई बार चीजें आ जाती हैं, जो आपने देखी होती हैं, जिसमें आपको ह्यूमर नजर आता है। आप एन्जॉय खुद करते हैं तो फिर आप उस किरदार को डेवलेप करते हैं और फिर राइटर्स के साथ उनको लिखने की जंग शुरू हो जाती है।

आपका ड्रीम कैरेक्टर कौन सा है?

ड्रीम कैरेक्टर मुझे लगता है कि वो इसलिए ड्रीम होता है क्योंकि वो किसी ने किया हुआ है, और वो बहुत अच्छा किया है। बाकी हम लोग जो सोचते भी हैं, कि ऐसा होना चाहिए। वो हमारी सोच पर नहीं होता है, वो राइटर्स की सोच होती है। जो उनके दिमाग की उपज है। बाकी मुझे लगता है कि किरदार से ज्यादा जरूरी है स्टोरी। क्योंकि स्टोरी अच्छी है तो फिर उसके बाद ही किरदार का नंबर आता है।

आपका रोमांटिक अवतार कब देखने को मिलेगा और कब किस एक्ट्रेस के साथ आप रोमांस करना चाहेंगे?

देखिए मैं तो तैयार हूं, एक बार आप कटरीना कैफ से पूछ लो। ख्याल तो यही है कि किस तरह के रोल आपको ऑफर होंगे। बाकी मुझे लगता है कि हर आदमी इंडिया में बहुत रोमांटिक है। हमारे देश की जनसंख्या ही ये बात बताती है कि हमारे यहां बहुत रोमांस है। मुझे लगता है कि किस तरह से पेश किया जाए और किस तरह से वो लिखी गई है। अगर कोई लिखेगा और आएगा तो मैं कर लूंगा।

आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स क्या- क्या हैं?

सनफ्लावर के बाद एक और फिल्म है। लेकिन उसके बारे में मैं आपसे अगली बार बात करूंगा।

कपिल शर्मा को साथ में कब देख पाएंगे फैन्स?

अभी ऐसी कोई प्लानिंग नहीं है, और कोई ऐसी बात भी नहीं है। हम सब लोग अपनी- अपनी लाइफ में व्यस्त हैं। कभी ईश्वर ने चाहा और भविष्य में मौका मिलेगा तो जरूर काम करेंगे। लेकिन अभी ऐसी कोई भी बात नहीं चल रही है।

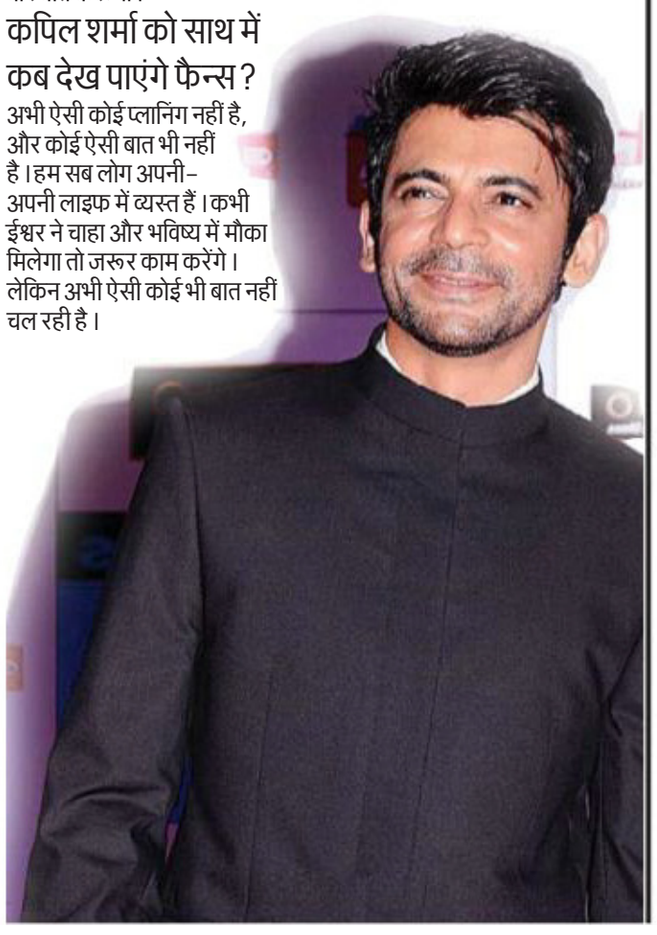

सिर्फ सुनील ग्रोवर के कारण मैंने सनफ्लावर साइन की

आगामी वेब सीरीज 'सनफ्लावर' में अहम भूमिका निभा रहे अभिनेता रणवीर शौरी का कहना है कि सुनील ग्रोवर के साथ काम करना एक रोमांचक अनुभव है। रणवीर ने कहा, जब मुझे 'सनफ्लावर' का नैरेशन मिला तो मैंने पूछा कि सोनू का किरदार कौन निभा रहा है, और मुझे बताया गया कि सुनील इस रोल को निभा रहे है। तभी से मैं इस कहानी का हिस्सा बनने के लिए बहुत उत्साहित था।''

रणवीर ने बताया, यह एक मर्डर मिस्ट्री है और सुनील के साथ काम करना बहुत खुशी की बात है। वह वास्तव में एक प्रतिभाशाली अभिनेता है, जिसे सभी योग्य मौके मिल रहे हैं। उन्होंने कॉमेडी के साथ शुरूआत की, इसलिए उनकी यात्रा अलग है। लेकिन वास्तव में, सुनील एक बहुत अच्छे अभिनेता हैं।''

शो की कहानी एक हत्या, जो सनफ्लावर नाम की एक हाउसिंग सोसाइटी में होती है और उसके बाद होने वाली जांच के इर्द गिर्द घूमती है। रणवीर शो में एक पुलिस इंस्पेक्टर की भूमिका निभाते हैं। सुनील सोनू के रोल में है, जो सोसाइटी में रहने वाले निवासियों में से एक है। रणवीर इससे पहले 'रंगबाज' और 'लूटकेस' में वर्दी में दिखाई दिए हैं। उन्होंने साझा किया कि कैसे वह हर नई पुलिस भूमिका के साथ अपने प्रदर्शन के प्रति वष्टिकोण को ताजा रखते हैं। रणवीर ने कहा, ''एक अभिनेता के रूप में मुझे लगता है कि मुझे इसे कैरिकेचर की तरह नहीं निभाना चाहिए और इसलिए मैं पेशे के आधार पर चरित्र को नहीं देखता हूं।'' रणवीर ने साझा किया कि जब आप कोई भी किरदार निभाते हैं, तो हर बार उनमें कुछ अलग होता हैं और इस तरह ये दर्शकों के लिए फ्रैश और अटरेक्टिव बन जाते है। विकास बहल द्वारा निर्देशित, वेब सीरीज में रणवीर और सुनील के साथ मुकुल चड्ढा, गिरीश कुलकर्णी, अन्नपूर्णा सोनी, दयाना एरप्पा, आशीष विद्यार्थी और शोनाली नागरानी जैसे बड़े कलाकार हैं।

पेरिस में फ्रैंच ओपन टेनिस में जीत के बाद ट्रॉफी उठाये हुए चेक गणराज्य की बारबोरा क्रेजसीकोवा व कैटरीना सिनीआकोवा।

टीम इंडिया के अंतिम ग्यारह को लेकर सिराज और इशांत दोनों के दावे मजबूत

लंदन, (एजेंसी)। भारत ओर न्यूजीलैंड के बीच विश्व टेस्ट चैंपियनशिप (डब्ल्यूटीसी) फाइनल को लेकर अनुमान लगाये जा रहे हैं।

टीम इंडिया के अंतिम ग्यारह में कौन गेंदबाज शामिल होंगे इसको लेकर भी दिग्गजों ने अपनी-अपनी राय दी है। पूर्व भारतीय क्रिकेटर संजय मांजरेकर ने कहा है कि यदि पिच पर स्विंग गेंदबाजों को मदद मिलने वाली है तो मोहम्मद सिराज को तीसरे तेज गेंदबाज को तौर पर अंतिम ग्यारह में इशांत शर्मा की जगह शामिल किया जा सकता है।

वहीं इशांत ने अभ्यास मैच में अच्छी गेंदबाजी कर तीन विकेट लेकर अपनी दावेदारी जतायी है। सिराज भी गेंदबाजी में अच्छी लय में दिखे हालांकि उन्हें विकेट नहीं मिला। ऐसे में अंतिम ग्यारह के गेंदबाज को लेकर संशय बरकरार है। इन दोनों तेज गेंदबाजों के आखिरी 5 टेस्ट मैचों के प्रदर्शन को देखा जाये तो इशांत ने कुल 11 विकेट लिए हैं। इस दौरान इस अनुभवी गेंदबाज ने 5 विकेट 68 रन देकर लिए थे।

वहीं आखिरी 5 टेस्ट मैचों के दौरान मोहम्मद सिराज ने 16 विकेट लिए हैं। सिराज का सबसे बेहतर प्रदर्शन 6 विकेट 150 रन देकर रहा है। जो उन्होंने ऑस्ट्रेलिया दौरे पर इसी साल ब्रिस्बेन टेस्ट मैच के दौरान लिया था. ब्रिस्बेन टेस्ट मैच की पहली पारी में सिराज को केवल एक विकेट मिले थे लेकिन इसके बाद दूसरी पारी में कहर बरपाते हुए 73 रन देकर 5 विकेट हॉल करने में सफल रहे थे। वहीं, अबतक खेले आखिरी 5 टेस्ट मैचों के दौरान सिराज ने एक बार ही 5 विकेट लिए हैं।

इन आंकड़ों को देखकर यह कहना मुश्किल है कि दोनों में से कौन बेहतर हैं पर हाल के प्रदर्शन को देखा जाये तो सिराज ने अच्छी गेंदबाजी की है। सिराज युवा हैं और आक्रमक गेंदबाजी करने में माहिर हैं। उनकी गेंदबाजी में स्विंग भी देखने को मिलती है जबकि दूसरी ओर इशांत के साथ अनुभव का भरा है। न्यूजीलैंड के खिलाफ इशांत ने अबतक 7 टेस्ट मैचों में 35 विकेट लिए हैं।

मुशफिकुर और कैथरीन बने आईसीसी के मई माह के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी

दुबई, (एजेंसी)। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) ने अपने माह के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी के लिए पुरुष वर्ग से बांग्लादेश के पूर्व कप्तान मुशफिकुर रहीम जबकि महिला वर्ग से स्कॉटलैंड की ऑलराउंडर कैथरीन ब्राइस का नाम घोषित किया है। इससे पहले इन दोनो को पुरुष और महिला वर्ग से आईसीसी का मई महीने का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया। आईसीसी के अनुसार विकेटकीपर बल्लेबाज मुशफिकुर ने मई में श्रीलंका के खिलाफ एक टेस्ट और तीन वनडे खेले। उन्होंने दूसरे एकदिवसीय में 125 रन की पारी खेली जिससे उनकी टीम श्रीलंका के खिलाफ पहली बार एकदिवसीय अंतरराष्ट्रीय श्रृंखला जीतने में सफल रही।

आईसीसी वोटिंग अकादमी के सदस्य वीवीएस लक्ष्मण ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर 15 साल तक क्रिकेट खेलने के बाद भी मुशफिकुर की रन बनाने की भूख कम नहीं हुई है। उनकी बल्लेबाजी के बल पर ही बांग्लादेश ने श्रीलंका को पहली बार एकदिवसीय श्रृंखला में हराया है।

लक्ष्मण ने कहा कि मध्यक्रम को मजबूत करने और विकेटकीपिंग करने से उनकी फिटनेस और कौशल का पता चलता है। दूसरी ओर महिला वर्ग में कैथरीन हाल में जारी रैंकिंग में शीर्ष 10 में शामिल स्कॉटलैंड की पहली खिलाड़ी बनी हैं। उन्होंने आयरलैंड के खिलाफ चार टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में 96 रन बनाने के अलावा पांच विकेट लिए।

डब्ल्यूटीसी मुकाबले के लिए तैयार हुई पिच, तेज गेंदबाजों को मिलेगी सहायता

साउथम्प्टन। भारत और न्यूजीलैंड के बीच यहां 18 से 22 जून तक होने वाले पहले विश्व टेस्ट चैंपियनशिप (डब्ल्यूटीसी) के खिताबी मुकाबले के लिए पिच तैयार हो गयी है। यह पिच से तेज गेंदबाजों को सहायता मिलने की उम्मीद है। ऐसे में न्यूजीलैंड टीम को लाभ मिल सकता है क्योंकि उसने इंग्लैंड में तेज पिचों पर टेस्ट सीरीज जीती है जिससे उसका मनोबल बढ़ा हुआ है। कीवी टीम के पास टेंट बोल्ट और टिम साउदी जैसे तेज गेंदबाज हैं जो भारतीय बल्लेबाजों के सामने चुनौती पेश करेंगे। आईसीसी की ओर से पहली बार इस प्रकार के टूर्नामेंट का आयोजन किया जा रहा है। ऐसे में सभी की नजर फाइनल पर हैं, साउथम्पटन के मैदानकर्मी और पिच क्यूरेटर सिमोन ली ने कहा कि पिच पर अच्छा उछाल और तेजी होगी। उन्होंने कहा, मैं व्यक्तिगत रूप से चाहता हूं कि पिच पर अच्छी गति और उछाल हो हालांकि यह कठिन होता है, क्योंकि मौसम ज्यादातर समय ठीक नहीं रहता है। उन्होंने कहा कि मौसम को लेकर पूवार्नुमान अच्छा है। धूम रहेगी। ऐसे में हम तेज और उछाल वाली पिच बनाने में कामयाब रहेंगे। सिमोन ने कहा, लाल गेंद क्रिकेट को रोमांचक बनाती है। मैं एक क्रिकेट प्रशंसक हूं और मैं एक ऐसी पिच बनाना चाहता हूं, जहां क्रिकेट प्रेमी को हर गेंद देखना पड़े। चाहे वह अच्छी बल्लेबाजी हो या शानदार गेंदबाजी का ओवर हो उन्होंने कहा कि मेडन ओवर काफी रोमांचक होता है। अगर गेंदबाज और बल्लेबाज के बीच अच्छी लड़ाई होती है तो ऐसे में पिच पर गति और उछाल तो होगा ही। सिर्फ तेज गेंदबाजों को ही फायदा नहीं होगा. मौसम पूवार्नुमान के अनुसार सभी पांच मैच के दिन तापमान 20 डिग्री सेल्सियस के आस-पास रहेगा और हल्की बारिश की संभावना है। ली का मानना है कि हालात अधिक शुष्क रहे तो अंतिम दो दिन स्पिन गेंदबाज भी अहम भूमिका निभाएंगे। उन्होंने कहा कि यहां की पिच जल्दी सूख जाती है, क्योंकि यहां मिट्टी में रेत मिली होती है लेकिन हम ऐसी पिच बनाने चाहते हैं जिससे सभी खिलाड़ियों को अपना कौशल दिखाने का मौका मिले।

हार से निराश हुए रुट ने माना टीम हर क्षेत्र में नाकाम रही

लंदन, (एजेंसी)। न्यूजीलैंड के हाथों यहां दूसरे टेस्ट मैच में मिली हार के बाद निराश हुए इंग्लैंड के कप्तान जो रुट ने माना है कि उनकी टीम का प्रदर्शन अच्छा नहीं था और उसे मेहमान कीवी टीम ने हर क्षेत्र में पीछे छोड़ दिया था। दूसरा टेस्ट मैच हारने के साथ ही मेजबान इंग्लैंड टीम 1-0 से टेस्ट सीरीज हार गयी है। रूट ने साथ ही कहा कि हमने इस सीरीज के लिए जो मेहनत की, उस पर बात करने के लिए यह सही समय नहीं होगा। इंग्लैंड की साल 2014 के बाद से और कप्तान के तौर पर रूट की घरेलू धरती पर यह पहली सीरीज हार है।

वहीं साल 1999 के बाद से ही इंग्लैंड में न्यूजीलैंड की यह पहली टेस्ट सीरीज जीत है। रूट ने कहा कि इस सप्ताह हमारा प्रदर्शन विफल और निराशाजनक रहा है। मुझे नहीं लगता कि हमने अपना सही आंकलन किया है। हमें तीनों विभागों, खासकर बल्लेबाजी में नाकामी मिली है। पहली पारी में हम रन नहीं बना सके जो हमें बनाने चाहिए थे। इसके बाद क्षेत्ररक्षण के दौरान हमने विकेट के कई मौके गंवाए और विकेट लेने में अपने गेंदबाजों की मदद नहीं की। वहीं दूसरी पारी में एक बार बार फिर हमारी बल्लेबाजी ढ़ह गयी।

इंग्लैंड के कप्तान ने कहा कि कभी-कभी टेस्ट क्रिकेट में गेंद के साथ आपका सत्र खराब हो सकता है, लेकिन आप फिर भी काफी हद तक खेल में बने रहते हैं, लेकिन कई बार एक सत्र ही बहुत भारी पड़ जाता है और यही हमारे साथ हुआ। इसकी कीमत हमें श्रृंखला में हार के साथ चुकानी पड़ी है। इस दौरान हमें कुछ कठिन सबक सीखने को मिले हैं। हमें यह देखना होगा कि हम व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से कहां बेहतर हो सकते हैं। रूट ने साथ ही कहा कि हमें रचनात्मक होना होगा। मुझे लगता है कि टीम के हर एक खिलाड़ी ने साबित किया है कि वह टेस्ट में बड़ा व्यक्तिगत स्कोर बना सकते हैं। अभी हमें तनाव में नहीं आना चाहिये क्योंकि यह समय टेंशन लेने का नहीं है। हमें आगे बढ़ना होगा और बेहतर होने के लिए और प्रयास करने होंगे।

ओमाहा में अमेरिकी ओलंपिक तैराकी ट्रायल्स में भाग लेते हुए कारसन फोस्टर।

टोक्यो ओलिम्पिक में बेहतर प्रदर्शन के लिए गलतियां करने से बचना होगा : नवनीत

बेंगलुरु। भारतीय महिला हॉकी टीम की फॉरवर्ड नवनीत कौर ने कहा है कि आगामी टोक्यो ओलिम्पिक में बेहतर प्रदर्शन के लिए टीम को गलतियां करने से बचना होगा। इसके साथ ही सही तरीके से सोचने और कठिन हालातों में शांत बने रहने का तरीका भी तलाशना होगा। नवनीत ने कहा कि हम सभी के पास दुनिया भर में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने का कौशल और प्रतिभा है, हालांकि मैदान पर महत्वपूर्ण फैसला लेना किसी भी टीम के लिए एक अहम बात है, इसलिए हमारे लिए यह बहुत महत्वपूर्ण होगा कि हम मुश्किल हालातों में शांत बने रहें और अपनी क्षमताओं के अनुसार ही फैसला लें। टीम प्रबंधन भी यह तय कर रहा है कि सभी खिलाड़ी मैदान पर अपनी भूमिका के बारे में स्पष्ट रुप से जान लें। नवनीत ने कहा कि हम सभी के लिए पिच पर अपनी भूमिका के बारे में स्पष्ट होना बहुत अहम है, क्योंकि मैच के दिन खिलाडिों के बीच कोई भ्रम नहीं होना चाहिए। कोच और कप्तान यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि हर कोई अपनी भूमिकाओं के बारे में जानता हो और वे अपनी योजनाओं को कैसे कार्यान्वित कर सकते हैं, ताकि हम मैच के दौरान मैदान पर अच्छा तालमेल कर सकें। ओलिम्पिक हमारे लिए एक बड़ी चुनौती होने जा रहा है और हमें अच्छे परिणाम हासिल करने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करना होगा। इस युवा फॉरवर्ड ने भारतीय टीम के प्रशिक्षण सत्र के बारे में कहा कि हम इस समय काफी कड़ा प्रशिक्षण ले रहे हैं। हम अभ्यास के दौरान मैच की स्थितियों का अनुकरण करने की कोशिश करते हैं और प्रशिक्षण सत्र के दौरान अपना सौ फीसदी देते हैं। हम अपनी क्षमताओं को लेकर बहुत आश्वस्त हैं। इसके बाद भी जीत तभी मिलेगी जब मैच में योजनाओं को सही तरीके से अमल में लाया जा सकेगा। के दिन अपनी योजनाओं को ठीक से क्रियान्वित करने के ऊपर है।

मिल्खा सिंह की पत्नी का निधन

नई दिल्ली, (एजेंसी)। महान धावक मिल्खा सिंह की पत्नी निर्मल कौर का निधन हो गया है। वह पिछले कई दिनों से कोरोना वायरस संक्रमण के कारण अस्पताल में भर्ती थीं। भारतीय महिला वॉलीबाल टीम की कप्तान रहीं निर्मल कौर का निधन रविवार शाम चार बजे के करीब हुआ।

आईसीसी के हॉल ऑफ फेम की सूची में भारत के वीनू मांकड़ भी शामिल

दुबई, (एजेंसी)। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) ने अपने हॉल ऑफ फेम में शामिल 10 खिलाड़ियों के नाम घोषित किये हैं। इसमें भारत के वीनू मांकड़ को भी शामिल किया गया है। हॉल ऑफ फेम में पांच युगों से दो-दो महान खिलाड़ियों को शामिल किया गया है।

आईसीसी के अनुसार इसमें शामिल किए जाने वाले खेल के 10 दिग्गजों ने टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में अहम योगदान दिया है और इसी लिए उन्हें हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। इस प्रकार इसमें शामिल खिलाड़ियों की कुल संख्या बढ़कर 103 हो गयी है। सूची में जगह पाने वाले खिलाड़ियों में प्रारंभिक युग (1918 से पूर्व) के लिए दक्षिण अफ्रीका के ऑब्रे फॉल्कनर और ऑस्ट्रेलिया के मोंटी नोबल, दोनों विश्व युद्ध के बीच के समय के लिए (1918-1945) वेस्टइंडीज के सर लीरी कॉन्सटेंटाइन और ऑस्ट्रेलिया के स्टेन मैककेबे, युद्ध के बाद के युग (1946 -1970) के समय के लिए इंग्लैंड के टेड डेक्सटर और भारत के वीनू मांकड़ का नाम है। वनडे युग (1971-1995) के लिए वेस्टइंडीज के डेसमंड हेन्स और इंग्लैंड के बॉब विलिस जबकि आधुनिक युग (1996-2016) के लिए जिम्बाब्वे के एंडी फ्लावर और श्रीलंका के कुमार संगकारा को इसमें जगह दी गयी है। महानतम ऑलराउंडरों में से एक माने जाने वाले मांकड़ ने 44 टेस्ट में 31.47 की औसत से 2,109 रन बनाने के साथ 32.32 के औसत से 162 विकेट भी लिए है। वह एक सलामी बल्लेबाज और वामहस्त स्पिनर थे।

वह अपने टेस्ट करियर के दौरान हर स्थान पर बल्लेबाजी करने वाले केवल तीन क्रिकेटरों में से एक हैं। उन्होंने बाद में मुंबई में एक अन्य महान क्रिकेटर और बाद में आईसीसी हॉल ऑफ फेम के सदस्य बने सुनील गावस्कर को भी कोचिंग दी थी। हॉल ऑफ फेम में मांकड़ के शामिल होने पर गावस्कर ने कहा कि वीनू मांकड़ की विरासत यही है कि भारत के लिए क्रिकेट खेलने का सपना देखने वाले हर खिलाड़ी को खुद पर विश्वास करने के लिए कहते थे। वे आत्म-विश्वास के प्रबल समर्थक थे।

शाकिब अल हसन तीन मैचों के लिए प्रतिबंधित

ढाका, (एजेंसी)। बांग्लादेश के स्टार ऑलराउंडर शाकिब अल हसन पर तीन मैचों का प्रतिबंध लग गया है। शाकिब पर यह प्रतिबंध ढाका प्रीमियर लीग (डीपीएल) के 11 जून को खेले गए मैच के दौरान अंपायरों के प्रति गुस्से वाले व्यवहार के कारण लगाया गया है। प्रतिबंध के साथ ही उनपर पांच लाख टका का जुमार्ना भी लगाया गया है। ढाका मेट्रोपोलिस क्रिकेट समिति (सीसीडीएम) ने यह कारर्वाई की है। मोहम्मडन स्पोर्टिंग क्लब क्रिकेट समिति के अध्यक्ष मसूदुज्जमां ने एक बयान में कहा कि हम बीसीबी (बांग्लादेशक्रिकेट बोर्ड) से इस मामले को गंभीरता से लेने की भी अपील करेंगे जिससे यह पता चले कि इस अनुभवी खिलाड़ी ने ऐसा व्यवहार किस कारण से किया।

मसूदुज्जमां ने कहा कि हमें पता चला है कि अंपायर समिति ने चार मैचों के प्रतिबंध की सिफारिश की थी। हम बीसीबी से अपील करेंगे और उनसे कहेंगे कि वह मामले की तह तक जाए और देखे कि शाकिब ने ऐसा कदम क्यों उठाया क्योंकि इस प्रकार का व्यवहार स्वीकार नहीं किया जा सकता। इसके साथ ही हमें यह भी पता लगाना होगा कि ऐसा क्यों हुआ। शेर-ए-बंगला स्टेडियम में अबाहानी लिमिटेड और मोहम्मडन स्पोर्टिग के बीच खेले गए मैच के दौरान शाकिब दो बार अंपायरों पर भड़कते हुए दिखे।

पहला मौका मुशफिकुर रहीम के खिलाफ पगबाधा की अपील को नकार दिए जाने के वक्त था। तब शाकिब ने अपना आपा खो दिया था और स्टंप पर लात मार दी थी। इसके बाद अबाहानी लिमिटेड की पारी के दौरान छठे ओवर में पांचवीं गेंद के बाद जब दोनों मैदानी अंपायरों ने बारिश के कारण मैच रोकने की घोषणा की तब भी शाकिब ने गुस्से में दूसरे छोर के स्टंप्स उखाड़ दिए। शाकिब ने हालांकि बाद में अपनी इस गलती के लिए माफी मांगी।

ह्यूस्टन में समर सरीज फुटबॉल में गोल के बाद उत्साहित होती हुई अमेरिकी महिला मिडफील्डर मारग्रेट पुरसे।

डब्ल्यूटीसी फाइनल के लिए टीम के पास कई विकल्प : टेलर

बर्मिंघम। न्यूजीलैंड के प्रमुख बल्लेबाज रोस टेलर ने कहा है कि उनकी टीम की बेंच स्ट्रेंथ अच्छी है ओर यह बात इंग्लैंड के साथ दूसरे टेस्ट में साबित हुई है जब युवा खिलाड़ियों ने अपनी क्षमताएं दिखायी है। ऐसे में चयनकताओं के पास अगले सप्ताह भारत के साथ होने वाले विश्व टेस्ट चैंपियनशिप (डब्ल्यूटीसी) फाइनल के लिए टीम का चयन करते समय पर्याप्त विकल्प होंगे। न्यूजीलैंड ने अपने मुख्य खिलाड़ियों को तरोताजा रखने इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच के लिए छह बदलाव किए थे। उसने भारत के खिलाफ अगले सप्ताह शुरू होने वाले डब्ल्यूटीसी फाइनल के लिए कुछ खिलाड़ियों को आराम दिया जबकि कुछ खिलाड़ी चोटिल होने के कारण नहीं खेल पाए। टेलर ने कहा कि यह उनके लिए ही टीम के लिए भी चुनौती थी। हमारे कई खिलाड़ी दूसरे टेस्ट मैच में नहीं खेल रहे थे। कुछ को चोटिल होने के कारण होकर बाहर बैठना पड़ा तो कुछ को फाइनल से पहले विश्राम दिया गया। इन खिलाड़ियों ने इस मैच में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इससे चयनकताओं के पास विश्व कप (डब्ल्यूटीसी) फाइनल के लिए पर्याप्त विकल्प हो गए हैं। कप्तान केन विलियमसन को कोहनी की चोट के कारण बाहर होना पड़ा जबकि चयनकताओं ने तेज गेंदबाज टिम साउदी और काइल जैमीसन को विश्राम दिया। वहीं इनकी जगह टीम में लिए गए विल यंग, मैट हेनरी और अजाज पटेल ने अच्छा प्रदर्शन किया। इसके अलावा इस मैच में वापसी करने वाले तेज गेंदबाज ट्रेंट बोल्ट ने भी प्रभावशाली गेंदबाजी की।

जोकोविच ने स्टेफानोस को हराकर फ्रेंच ओपन जीता

पेरिस, (एजेंसी)। विश्व के नंबर एक खिलाड़ी सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने साल के दूसरे ग्रैंड स्लैम फ्रेंच ओपन टेनिस का एकल खिताब जीत लिया है। जोकोविच ने पुरुष एकल वर्ग के फाइनल में यूनान के स्टेफानोस सितसिपास को 6-7, 6-8, 2-6, 6-3, 6-2, 6-4 से हराया जबकि सेमीफाइनल में स्पेन के दिग्गज खिलाड़ी राफेल नडाल हराया। दूसरी ओर सितसिपास ने जर्मनी के एलेक्जेंडर ज्वेरेव को हरा पहली बार किसी ग्रैंड स्लैम के फाइनल में जगह बनायी थी। यह जोकोविच के करियर का दूसरा फ्रेंच ओपन और करियर का 19वां ग्रैंड स्लैम खिताब है।

मैच के दौरान सितसिपास ने शुरूआती दो सेट अपने नाम किये। जोकोविच ने पहले सेट में यूनान के युवा खिलाड़ी को अच्छी टक्कर दी पर 6-7 6-8 से सेट हार गए। इस जीत से उत्साहित सितसिपास ने दूसरा सेट 6-2 से अपने नाम किया पर जोकोविच ने इसके बाद वापसी के प्रयास किये और तीसरा सेट जीत लिया। इसके बाद इस सर्बियाई खिलाड़ी ने चौथे सेट में को भी अपने नाम कर लिया। पांचवें सेट में मुकाबला शुरू में 1-1 से बराबर था। फिर जोकोविच 4-2 से आगे हो गए। सितसिपास ने यहां वापसी की और स्कोर 4-3 कर लिया पर जोकोविच ने एक बार फिर 6-4 से पांचवां सेट जीत लिया। जोकोविच यहां सितसिपास को हराने के साथ ही 52 वर्षों में पहले ऐसे खिलाड़ी बन गए हैं जिन्होंने हर ग्रैंड स्लैम का एकल खिताब दो बार अपने नाम किया है। वह रॉय एमरसन और रॉड लेवर के अलावा केवल तीसरे ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने चारों ग्रैंड स्लैम को दो-दो बार जीता है।

रक्तदान शिविर में शामिल हुए सचिन

मुम्बई, (एजेंसी)। मास्टर बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर सामाजिक मामलों से जुड़े रहते हैं। अब सचिन ने अपने घर के बाहर रक्तदान शिविर में हिस्सा लिया। सचिन ने कोरोना संक्रमण से उबरने के बाद कहा था कि वह प्लाज्मा दान करने के लिए भी तैयार हैं। जब भी वह इसके लिए योग्य होंगे प्लाज्मा दान करेंगे। सचिन आम तौर पर सामाजिक मुद्दों से जुड़े रहते हैं। कोरोना काल में भी वह लगातार सरकार और लोगों की सहायता के लिए सामने आये थे।